

[2023] 8 एस. सी. आर 1

हरियाणा पावर खरीद केंद्र

वी.

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस।

(2018 की सिविल अपील संख्या 11826)

अप्रैल 06,2023

[के. एम. जोसेफ और बी. वी. नागरत्ता, जे. जे.]

विद्युत कानून-विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (ए. पी. टी. ई. एल.) और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.), यदि

विनियामक निकाय अनुबंध की स्पष्ट शर्तों से परे जाने के लिए-हालांकि यह किसी विनियमन के लिए किसी पक्ष को अपने संविदात्मक दायित्वों से बाहर निकालने के लिए खुला हो सकता है, अपनी न्यायिक शक्ति के दौरान यह अनुबंध की शर्तों की अवहेलना करने के लिए इस शक्ति को हड़पने के लिए नामकरण विनियमन का उपयोग करके आयोग के लिए खुला नहीं हो सकता है बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण वास्तव में पक्षों के लिए एक नया सौदा नहीं कर सकता है न्यायाधिकरण एक अनुबंध को फिर से नहीं लिख सकता है। गंभीरता से प्रवेश किया-यह एक नए समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है

लिखित अनुबंध में परिवर्तन करने वाले कार्य करने की अवशिष्ट शक्तियों को विनियमित करने की शक्ति में स्थित नहीं किया जा सकता है-किसी भी दर पर, अनुबंध के स्पष्ट प्रावधानों के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है-ऐसे मामले में जहां पक्षों ने स्पष्ट के साथ अनुबंध किया है।

प्रावधानों के अनुसार, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायाधिकरण के पास अनुबंध के स्पष्ट प्रावधानों की अवहेलना करने की शक्ति होगी क्योंकि यह पता चलता है कि समय बीतने के साथ और यहां तक कि इसमें परिवर्तन भी होता है।

परिस्थितियों में, यह पाया जाता है कि अनुबंध पर ठेकेदार के लिए नुकसान के अलावा काम नहीं किया जा सकता है-अनुबंध। विद्युत अधिनियम, 2003: एस. 79 बिजली संयंत्र परियोजना-विशेष प्रयोजन वाहन-बिजली खरीद समझौता (पी. पी. ए.)-'कानून में बदलाव' के कारण मुआवजा-एक अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए गठित विशेष उद्देश्य वाहन-सफल बोलीदाता द्वारा उत्पन्न बिजली की आपूर्ति खरीदारों/वितरण लाइसेंसधारियों के माध्यम से की जानी थी।

(अपीलार्थी)-याचिका यू / प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बिजली की खरीद को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 79

[2023] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्माण अवधि के दौरान कानून में परिवर्तन के कारण मुआवजे के लिए बोली और पीपीए के अनुच्छेद 13 और 17 'A-आयोजित: इस मामले को परिभाषित करने वाले विशिष्ट प्रावधानों के चश्मे से देखा जाना चाहिए

कानून में परिवर्तन और कानून में वास्तविक परिवर्तन-तथ्यों पर, पी. पी. ए. विचार करता है कि यदि विक्रेता कानून में परिवर्तन से प्रभावित है और कानून में परिवर्तन का दावा करना चाहता है, तो उसे कानून में परिवर्तन के बारे में जागरूक होने के बाद जल्द से जल्द कानून में परिवर्तन के बारे में खरीदारों को सूचित करना होगा-ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है जो यह दर्शाती है कि खरीदारों ने कहा है कि वे उत्तरदायी होंगे-यह कानून में परिवर्तन नहीं हो सकता है जैसा कि समझौते में विचार किया गया था क्योंकि यह प्रारंभिक सहमति में परिवर्तन नहीं था जो इस संबंध में तर्क दिया गया था-पक्ष इस बारे में स्पष्ट थे कि कानून में परिवर्तन को कैसे मुआवजा दिया जाना था और कार्यप्रणाली स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है इसलिए, अनुच्छेद 13.2 में सामान्य भाग में की गई कोई भी अपील अनुच्छेद 13.2 में निर्धारित की गई है।

जो प्रभावित पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में बहाल किए जाने के बारे में बताता है जैसे कि कानून में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ था, जिसका परिणाम उस विशिष्ट सूत्र से अलग नहीं हो सकता है जो निर्धारित किया गया है-यदि इस संबंध में अपने दायित्वों के निष्पादन में खरीदारों द्वारा एक निश्चित समय सीमा पार की जाती है, तो विक्रेता (पहले प्रतिवादी) को अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया है-यह पहले प्रतिवादी का मामला नहीं है कि उसने अनुबंध को अस्वीकार करने का इरादा किया था-दूसरी ओर, यह सामान्य मामला है कि अनुबंध जीवित रहा और यह उन दावों के अधीन बच गया है जो उसके तहत उठाए गए हैं-इसका मतलब यह होगा कि कार्य को पूरा करने में विफलता के परिणाम के रूप में किया गया है। अनुबंध में प्रदान किए गए तरीके से, किसी को सामान्य रूप से यह पूछने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि क्या यह अनुच्छेद 13.1 के तहत विचार किए गए कानून में परिवर्तन के लिए आधार प्रदान करेगा। 1 यहां तक कि पी. पी. ए. की अनुसूची 2 के भाग 2 के आसपास बनाए गए मामले के संदर्भ में भी, जिसके तहत अनुच्छेद 3.1 में उल्लिखित कार्य का निष्पादन किया जाता है। 2 प्रदान किए गए समय के भीतर ए को प्रारंभिक सहमति के रूप में माना जाना था, ऐसा करने में विफलता के परिणाम को स्पष्ट रूप से लिखा गया है-सबसे अच्छा या सबसे बुरा, यह पहले प्रतिवादी को अनुबंध को रद्द करने का अधिकार दे सकता था-पहला प्रतिवादी यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हुआ है कि कानून में कोई बदलाव हुआ था।

सिद्धांत/सिद्धांत-विरोधाभास का सिद्धांत समझाया गया-आयोजित: कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम के सिद्धांत का उपयोग आम तौर पर बीमा के अनुबंधों और मानक रूप के अनुबंधों में किया जाता है स्पष्ट रूप से सिद्धांत यह है कि किसी भी संदेह के मामले में रयान पावर खरीद केंद्र V.

सासान पाउ लिमिटेड। & ओआरएस।

: शर्तों के अनुसार, संदेह को पार्टी के खिलाफ हल किया जाना चाहिए

अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक

आयोग (2010) 4 एससीसी 603: [2010] 3 एससीआर 609 -

अप्रयोज्य रखा गया।

एनर्जी वॉचडॉग बनाम। केंद्रीय विद्युत नियामक

आयोग और अन्य (2017) 14 एस. सी. सी. 80: [2017]

325 [2019] 4 एससीआर 487-पर निर्भर। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। एस्सार पावर (2008) 4 एस. सी. सी. 755: [2008] 4 एस. सी. आर. 822; स्कंदिया बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम। कोकिलाबेन चंद्रवन और अन्य। (1987) 2 एस. सी. सी. 654 [1987] 2 एस. सी. आर. 752; डी. एल. एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड बनाम।

हरियाणा (2010) 14 एससीसी 1: [2010] 15 एस. सी. आर. 85; सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज बनाम। तेल और प्राकृतिक गैस भारतीय आयोग (2010) 11 एससीसी 296: [2010] 9 एससीआर 176; नाभा पावर लिमिटेड बनाम। पीएसपीसीएल (2018) 11 एससीसी 508 [2017] 14 एससीआर 301; प्रह्लाद और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्न. (2010) 10 एससीसी 458: [2010] 11 एस. सी. आर. 916; पंजाब राज्य और अन्य। वी. बख्शीश सिंह (1998) 8 एस. सी. सी. 222: [1998] 1 पूरक। एस. सी. आर. 478; महांत धनगीर और अन्न। वी. मदन मोहन और अन्य। (1987) (एस. सी. सी. 528 [1988] 1 एस. सी. आर. 679; उत्तर प्रदेश पावर

निगम लिमिटेड बनाम। राष्ट्रीय ताप विद्युत

निगम लिमिटेड और अन्य (2009) 6 एस. सी. सी. 235: [2009] 3 एससीआर 1060; गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। तारिणी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य (2016) 8 एस. सी. सी. 743 [2016] 5 एस. सी. आर. 990 और मनोहर लाल शर्मा बनाम। प्रधान सचिव और अन्य। (2014) 9 एससीसी 614: [2014]

12 एस. सी. आर. 110-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

उस पर भरोसा करें

7] 3 एससीआर 153

पैरा 28

9] 4 एससीआर 487

उस पर भरोसा करें

पैरा 28

8] 4 एससीआर 822

संदर्भित किया गया है

पैरा

28 [2023] 8 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1987] 2 एससीआर 752

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[2010] 15 एससीआर 85

पै

रा 28

संदर्भित किया गया है

[2010] 9 एससीआर 176

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[2017] 14 एससीआर 301

पै

रा 28

संदर्भित किया गया है

[2010] 11 एससीआर 916

संदर्भित किया गया है

पै

रा 29

[1998] 1 पूरक। एससीआर 478

पै

रा 29

संदर्भित किया गया है

[1988] 1 एससीआर 679

	संदर्भित किया गया है	
रा 29		पै
[2009] 3 एससीआर 1060		
रा 37		पै
	संदर्भित किया गया है	
[2016] 5 एससीआर 990		
	संदर्भित किया गया है	
रा 39		पै
[2019] 4 एससीआर 487		
रा 84		पै
	संदर्भित किया गया है	
[2017] 3 एससीआर 153		
	संदर्भित किया गया है	
रा 86		पै
[2010] 3 एससीआर 609		
	अप्रयोज्य रखा गया	
रा 94		पै
[2014] 8 एससीआर 446		
	संदर्भित किया गया है	
रा 118		पै
[2014] 12 एससीआर 110		

रा118

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.11826

2018 से।

अपीलीय के 20.11.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 की अपील No.121 में विद्युत न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

के साथ

सिविल

अपील सं। 11927 , 12190 2018 का 1670,2019 का 12232

2018 और 2019 का 1742

जी. उमापति, पी. चिदंबरम, एम. जी. रामचंद्रन, राणा

मुखर्जी, साजन पोवय्या, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रोहित के. सिंह, आनंद के. गणेशन, सुश्री पूर्वा सहगल, निकुंज दयाल, शुभम आर्य, अमल नायर, सुश्री कृतिका खन्ना, सुश्री पल्लवी सहगल, सुश्री रीहा सिंह, सुश्री शिखा सूद, सुश्री अनुमेहा स्मिटी, के. वी. मोहन, के. वी. बालाकृष्णन, रवि नायर, राहुल कुमार शर्मा, राकेश के. शर्मा, राजीव श्रीवास्तव, निशांत शर्मा, सुश्री गार्गी श्रीवास्तव, सुश्री अद्वितीया, सुश्री अपर्णा भट, अमित कपूर, पुखरंभम रमेश कुमार, राहुल किनरा, आदित्य अजय, करुण श्रमा, गिरधर गोपाल खट्टार, सुश्री अलिवा अहमद, सुश्री। उपस्थित दलों के लिए।

हरियाणा पावर खरीद केंद्र V. ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
के. एम. जोसेफ, जे.

(1) जिन छह अपीलों से हम संबंधित हैं, वे विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के तहत दायर की गई हैं।

' संक्षिप्तता के लिए कार्य करें)। अधिनियम की धारा 111 के तहत पहले प्रतिवादी द्वारा की गई अपील में बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपीलों का निर्देश दिया जाता है।

(2) न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, बदले में, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई थी

(इसके बाद संक्षिप्तता के लिए 'कमीशन' के रूप में संदर्भित)। आयोग ने प्रथम प्रतिवादी द्वारा दायर एक याचिका में अधिनियम की धारा 79 (बी) के तहत एक होने का तात्पर्य रखते हुए आदेश पारित किया।

तथ्य

(3) एक अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस दिशा में, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया को होना था नोडल एजेंसी। इसने एक विशेष प्रयोजन वाहन को शामिल किया, जो पहला उत्तरदाता है। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने का विचार था जिसे एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से चुने गए सफल बोलीदाता द्वारा संचालित किया जाएगा। सफल बोलीदाता द्वारा उत्पन्न बिजली की आपूर्ति खरीदारों (हमारे समक्ष अपीलकर्ता) के माध्यम से की जानी थी, जिन्हें अधिनियम के तहत वितरण लाइसेंसधारी के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। अपीलकर्ताओं को अंत में इस तरह से खरीदी गई बिजली की आपूर्ति करनी थी

उपभोक्ता।

(4) चूंकि अधिनियम की धारा 63 के तहत आश्रय लेने पर विचार किया गया था, इसलिए हमें उन दिशानिर्देशों का उल्लेख करना चाहिए जो केंद्र सरकार द्वारा धारा 63 के तहत कार्य करने के लिए जारी किए गए हैं। 19.01.2005 पर दिशानिर्देश जारी किए गए थे। हम निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित करना उचित समझते हैं:

" 2.1 ये दिशा-निर्देश बिजली की खरीद के लिए बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के तहत जारी किए जा रहे हैं।

वितरण लाइसेंसधारी (खरीददार):

(क) 7 वर्ष की अवधि के लिए बिजली की दीर्घकालिक खरीद

और ऊपर;

(ख) 7 वर्ष तक की लेकिन 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए मध्यम अवधि की खरीद।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.2 दिशा-निर्देश प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से बेस-लोड और मौसमी बिजली आवश्यकताओं की खरीद के लिए लागू होंगे।

निम्नलिखित तंत्र: आई. जहाँ स्थान, प्रौद्योगिकी या ईंधन निर्दिष्ट नहीं है

खरीददार (मामला 1);

ii. पनबिजली परियोजनाओं, भार केंद्र परियोजनाओं या विशिष्ट ईंधन आवंटन के साथ अन्य स्थान विशिष्ट परियोजनाओं के लिए जैसे कि कैप्टिव खदानें उपलब्ध हैं, जिन्हें खरीददार शुल्क आधारित के तहत स्थापित करना चाहता है। बोली प्रक्रिया (मामला 2) "।

(5) दिशानिर्देश खरीदारों के लिए बाध्यकारी हैं। दिशानिर्देश 3.2 'एन बोलियों के निमंत्रण की तैयारी से संबंधित है। वह इस प्रकार है:

" 3.2 पनबिजली परियोजनाओं से दीर्घकालिक खरीद के लिए या उन परियोजनाओं के लिए जिनके लिए पूर्व-चिन्हित स्थलों का उपयोग किया जाना है (मामला 2), निम्नलिखित गतिविधियों को खरीदार द्वारा पूरा किया जाना चाहिए या

आरंभ करने से पहले खरीददार का अधिकृत प्रतिनिधि

बोली प्रक्रिया: - परियोजना के लिए आवश्यक स्थल की पहचान और भूमि अधिग्रहण

- पर्यावरण मंजूरी

- ईंधन लिंकेज, यदि आवश्यक हो (बोली लगाने वाले से भी पूछा जा सकता है)

- जल संपर्क

- आवश्यक जलविज्ञान, भूवैज्ञानिक, मौसम विज्ञान और

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. पी. आर.) तैयार करने के लिए आवश्यक भूकंपीय डेटा, जहां लागू हो। बोलीदाता अपने स्वयं के स्रोतों के माध्यम से भूवैज्ञानिक डेटा को सत्यापित करने के लिए स्वतंत्र होगा, क्योंकि भूवैज्ञानिक जोखिम परियोजना विकासकर्ता के पास होगा।

परियोजना स्थल को सफल बोलीदाता को स्थानांतरित कर दिया जाएगा

घोषित कीमत।

बशर्ते कि उन परियोजनाओं के लिए जिनसे विभिन्न राज्यों में स्थित एक से अधिक वितरण लाइसेंसधारी बिजली खरीदने का इरादा रखते हैं और

यदि ऐसी परियोजनाओं की तैयारी को केंद्र सरकार द्वारा सुगम बनाया जा रहा है, तो ऊपर उल्लिखित गतिविधियाँ बोली प्रक्रिया से पहले शुरू की गईं और चयनित बोलीदाता के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी की जानी चाहिए।

हरियाणा पावर खरीद केंद्र v. ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

(6) दिशानिर्देशों के तहत, शुल्क संरचना पर विचार किया जाता है जो

इसमें क्षमता शुल्क और ऊर्जा शुल्क शामिल हैं जिन पर विस्तार से विचार किया जाता है। यह बोली प्रक्रिया से भी संबंधित है। बोली प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया गया है, अर्थात् , एक पूर्व-योग्यता प्रणाली द्वारा योग्यता का निर्धारण और उसके बाद वित्तीय बोली को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना और उस पर विचार करना। एक दिशानिर्देश है जो मध्यस्थता से संबंधित है और यह दिशानिर्देश 5,17 में निहित था:

" 5.17 खरीददार एक सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान स्थापित करेगा।

(ए. डी. आर.) भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार तंत्र

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। एडीआर होगा

बोली के संबंध में विवादों को कम करने के लिए अनिवार्य और समयबद्ध

प्रक्रिया और उसका प्रलेखन।

यदि ए. डी. आर. विवाद को हल करने में विफल रहता है, तो यह इसके अधीन होगा:

के अधीन उपयुक्त विनियामक आयोग की अधिकारिता

विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान।

(7) तदनुसार, दिशानिर्देशों के संदर्भ में कार्य करना अभिप्रेत है।

कि योग्यता के लिए अनुरोध (संक्षिप्त आर. एफ. क्यू. के लिए) 31.03.2006 पर जारी किया गया। रिलायंस पावर लिमिटेड उन बोलीदाताओं में से एक था जो आर. एफ. क्यू. के मामले में पूर्व-योग्य था। 18.08.2006 पर, दिशानिर्देशों में एक बदलाव अधिसूचित किया गया था। इसने दिशानिर्देश संख्या 4.7 के अलावा दिशानिर्देश 5,17 में निम्नलिखित परिवर्तन किए। अपरिवर्तित और

संशोधित दिशा-निर्देश 4.7 और 5,17 निम्नानुसार हैं:

18.08.2006 पर संशोधित

सीबीजी

एस. नहीं। 19.01.2005 1 पर सी. बी. जी.। 4. 7 उत्पादन पर कर में कोई परिवर्तन या 4. लागत को प्रभावित करने वाले कानून में कोई परिवर्तन या

बिक्री के व्यवसाय से किसी भी राजस्व के परिणामस्वरूप बिजली की बिक्री

उस बिजली के संबंध में खरीददार को कानून में परिवर्तन

बोली जमा करने की तारीख को लागू होने वाले कानून को 7 दिनों की तारीख को अलग से समायोजित किया जाएगा। [पेज। आर. एफ. पी. बोली जमा करने की अंतिम तिथि से पहले

किसी भी मामले में

इसे अलग से समायोजित किया जाएगा।

345 , सीसी-1]

विवाद

किसी भी परिवर्तन के प्रभाव के बारे में

कानून में, उपयुक्त का निर्णय

आयोग लागू होगा।

2 .

मध्यस्थता

मध्यस्थता

सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान (ए. डी. आर.) के निर्धारण में या उसके संबंध में परिवर्तन शुल्क या किसी भी शुल्क से संबंधित मामलों के अनुसार तंत्र, या जो

भारतीय मध्यस्थता के प्रावधान और आंशिक रूप से या पूरी तरह से परिवर्तन में परिणाम हो सकता है

सुलह अधिनियम, 1996। ए. डी. आर. शुल्क लगाएगा, ऐसे विवाद का निर्णय इसके द्वारा किया जाएगा

उपयुक्त आयोग के लिए अनिवार्य और समयबद्ध होना।

बोली के संबंध में विवादों को कम करें अन्य सभी विवादों का समाधान इसके द्वारा किया जाएगा

प्रक्रिया और उसका प्रलेखन। भारतीय मध्यस्थता के तहत मध्यस्थता और

सुलह अधिनियम, 1996।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(8) 21.08.2006 पर, संक्षिप्त आर. एफ. पी. के लिए प्रस्ताव के लिए एक अनुरोध जारी किया गया। हम निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख करना उचित समझते हैं।

ई आर. एफ. पी.

" 4. जबकि यह आर. एफ. पी. सद्भावना से तैयार किया गया है, न ही

खरीददार, अधिकृत प्रतिनिधि और बिजली वित्त

निगम लिमिटेड (पी. एफ. सी.) और न ही उनके निदेशक या कर्मचारी या सलाहकार/सलाहकार कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी देते हैं, व्यक्त करते हैं।

या इसमें निहित किसी भी कथन या चूक के संबंध में, या यहाँ निहित जानकारी की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में किसी भी जिम्मेदारी या दायित्व को निहित या स्वीकार करते हैं, और

इस आर. एफ. पी. की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के बारे में किसी भी कानून, कानून, नियमों या विनियमों के तहत कोई दायित्व नहीं होगा, भले ही किसी भी कार्य या चूक से बोलीदाता को कोई नुकसान या क्षति होती है।

उनकी तरफ से।

1.3 बोली प्रक्रिया का उद्देश्य एक का चयन करना है

शर्तों के अनुसार परियोजना के विकास के लिए सफल बोलीदाता

आर. एफ. पी. इस परियोजना की संविदित क्षमता होगी -

पी. पी. ए. की शर्तों के अनुसार न्यूनतम 3500 मेगावाट और अधिकतम 3800 मेगावाट। चयनित बोलीदाता शेयर खरीद के अनुसार पी. एफ. सी. और उसके नामितों से अधिकृत प्रतिनिधि की पूरी हिस्सेदारी खरीदेगा। समझौता करें और विक्रेता को आर. एफ. पी. परियोजना में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करें

दस्तावेज़। चयनित बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि विक्रेता विकास, वित्त, स्वामित्व, डिजाइन, इंजीनियरिंग खरीद, निर्माण, कमीशनिंग, संचालन करता है।

आर. एफ. पी. परियोजना की शर्तों के अनुसार परियोजना का रखरखाव

दस्तावेज़। चयनित बोलीदाता यह भी सुनिश्चित करेगा कि:

(i) सभी उपकरण और सहायक निरंतर उपयोग के लिए उपयुक्त होंगे।

47. 5 से 51.5 हर्ट्ज (-5 प्रतिशत से + 3 प्रतिशत) की आवृत्ति सीमा में संचालन

50.0 हर्ट्ज की रेटेड आवृत्ति)।
अनुबंधित क्षमता प्रदान करने में सक्षम होगा।

((ii) यह संयंत्र 47.5 हर्ट्ज ग्रिड आवृत्ति पर लगातार

1.4 खरीददारों ने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सासण में परियोजना के विकास की शुरुआत की है और इसमें निम्नलिखित कार्यों को पूरा करेंगे। जैसा कि यहाँ निर्दिष्ट किया गया है, उस समय को ध्यान में रखते हुए:

रयान पावर खरीद केंद्र V. ससान पावर लिमिटेड & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

iv. मुख्य बंदी कोयला खदानों का आवंटन और प्रदान करना

रिपोर्ट (जीआरएस), बोली लगाने की समय सीमा से कम से कम तीस (30) दिन पहले उपलब्ध कराई जाएगी; वी. बोली की समय सीमा से कम से कम तीस (30) दिन पहले केंद्रीय जल आयोग की मंजूरी के साथ परियोजना की आवश्यकता के लिए जल संपर्क को जोड़ना।

जल ग्रहण अध्ययन रिपोर्ट और भू-विज्ञान सहित परियोजना रिपोर्ट तकनीकी अध्ययन, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, क्षेत्र जल निकासी अध्ययन, सामाजिक

आर्थिक अध्ययन और ई. आई. ए. अध्ययन (त्वरित) बोली की समय सीमा से कम से कम नब्बे (90) दिन पहले उपलब्ध कराया जाएगा।

vi. बिजली मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मेगा बिजली नीति के तहत बिजली उत्पादन परियोजनाओं को लाभ प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करना, भारत सरकार द्वारा बोली की समय सीमा से कम से कम तीन दिन पहले (30) बिजली स्टेशन के अनुसूचित सीओडी तक;

यह ध्यान दिया जा सकता है कि खरीदारों की संख्या, अधिकृत

प्रतिनिधि और पी. एफ. सी., न ही उनके निदेशक, कर्मचारी या सलाहकार/सलाहकार कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी देते हैं, व्यक्त करते हैं या

जल ग्रहण में किए गए किसी भी कथन या चूक के संबंध में निहित, या किसी भी जिम्मेदारी या दायित्व को स्वीकार करें।

अध्ययन रिपोर्ट और परियोजना रिपोर्ट, या उसमें निहित जानकारी की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता, और इसमें कोई खर्च नहीं होगा

ऐसे जल सेवन अध्ययन रिपोर्ट और परियोजना रिपोर्ट की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के बारे में किसी भी कानून, कानून, नियमों या विनियमों के तहत दायित्व, भले ही कोई नुकसान या क्षति हो।

चयनित बोलीदाता को उनकी ओर से किसी भी कार्य या चूक द्वारा विद्युत मंत्रालय और मध्य प्रदेश राज्य सरकार विक्रेता को परियोजना विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए, सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर, विक्रेता को अपना समर्थन व्यक्त किया है।

2.7 .2.1 बोलीदाता स्वतंत्र जांच करेगा और संतुष्ट करेगा।

सभी आवश्यक जानकारी, इनपुट, शर्तों और परिस्थितियों और कारकों के संबंध में जो उनके [2023] 8 एस. सी. आर. पर कोई प्रभाव डाल सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिजली अधिनियम, 2003, आयकर अधिनियम, 1961, कंपनी अधिनियम, 1956, सीमा शुल्क अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, आई. ई. जी. सी., विनियमों से परिचित हों। भारत में प्रचलित नियामक आयोगों और अन्य सभी संबंधित अधिनियमों, कानूनों, नियमों और विनियमों द्वारा तैयार किया गया। खरीददार इस संबंध में बोलीदाताओं से स्पष्टीकरण के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेंगे। इन कानूनों या ऐसी जानकारी के बारे में जानकारी न होना बोलीदाता के लिए बोली की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करने का कारण नहीं होगा। बोलीदाता वचन देता है और सहमत होता है कि इससे पहले

अपनी बोली प्रस्तुत करना ऐसे सभी कारक, जो आम तौर पर सामने लाए जाते हैं

ऊपर, बोली जमा करते समय पूरी तरह से जांच और विचार किया गया है।

संलग्नक 5

साइट मानचित्र के साथ साइट विवरण

यह स्थल मध्य प्रदेश के सीधी जिले की सिंगरौली तहसील के सासण गाँव के पास स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन शक्तिनगर (18 किमी) है और निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी (250 किमी) है। यह स्थल 23° 58'30 "उत्तर अक्षांश और 82° 37'03" पूर्व देशांतर पर स्थित है।

परियोजना के लिए लगभग 3500 एकड़ भूमि की पहचान की गई है, जिसमें सिद्धिकला, हरहावा, टियारा, झंजीतोला और अन्य गाँव शामिल हैं। सिद्धिखुदा इसमें से मुख्य संयंत्र के लिए लगभग 2000 एकड़, राख निपटान/डाइक के लिए लगभग 1100 एकड़ और कॉलोनी के लिए 400 एकड़ भूमि की पहचान की गई है।

परियोजना के लिए जल स्रोत गोविंद बल्लभ पंत सागर (रिहंद जलाशय) है, जो मुख्य संयंत्र स्थल से लगभग 6-7 किमी दूर है। उपयुक्त पम्पिंग व्यवस्था द्वारा स्थल पर पानी लाया जाएगा और

पाइप लाइनें।

हरियाणा पावर खरीद केंद्र V. ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

लगभग 700 करोड़ टन के भंडार वाले सिंगरौली क्षेत्र में कोयला ब्लॉकों (खदानों) को इस परियोजना के लिए कैप्टिव कोयला ब्लॉकों (खदानों) के रूप में आवंटित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए एक कोयला खदान के विकास की आवश्यकता होगी जिसमें प्रति वर्ष 18-20 मिलियन टन (एम. टी. पी. ए.) का उत्पादन होगा। अधिक विवरण परियोजना रिपोर्ट में दिए गए हैं।

(9) हम, इस मोड़ पर, यह भी ध्यान दे सकते हैं कि विशेष प्रयोजन वाहन जो गतिविधियों को पूरा करने के लिए रखा गया था,

सबसे कम बोली लगाने वाला पात्र नहीं पाया गया, रिलायंस पावर लिमिटेड सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में उभरा। शर्तों को ध्यान में रखते हुए, रिलायंस पावर लिमिटेड ने पहले प्रतिवादी की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया और इसे 01.08.2007 पर आशय पत्र के साथ पसंद किया गया। इसने 07.08.2007 पर एक बिजली खरीद समझौता (इसके बाद 'PPA' के रूप में संदर्भित) किया। दिसंबर, 2007 के दूसरे सप्ताह में, ऐसा प्रतीत होता है कि पहला प्रत्यर्थी, जो अब सफल बोलीदाता रिलायंस पावर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में परिवर्तित हो गया था, चालू हो गया। वैंपकोस द्वारा एक नया अध्ययन। डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. ने 04.04.2008 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हमें इस मोड़ पर ध्यान देना चाहिए कि '21.07.2007' को कट ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसकी प्रासंगिकता निर्णय के बाद के भाग में सामने आएगी।

(11) पी. पी. ए. ने दो चरणों पर विचार किया। पहला चरण बिजली संयंत्र का निर्माण था। दूसरा ऑपरेशन था

बिजली संयंत्र। पी. पी. ए. को 25 साल की अवधि के लिए लागू किया जाना था। इसलिए, हम इसे सुरक्षित रूप से अवधि समझौते के रूप में चिह्नित कर सकते हैं

क्रय शक्ति। चूंकि यह प्रतिस्पर्धी बोली का मामला था, जिससे सबसे कम बोली लगाने वाले को पता चला, लेकिन अधिनियम की धारा 63 के तहत शासन का सामना करना पड़ा, जो पी. पी. ए. में प्रवेश करने के बाद आकर्षित हुआ, पी. पी. ए. में विचार की गई दरों को अपनाने के लिए आयोग के समक्ष एक याचिका दायर की गई। दिनांक 17.10.2007 के आदेश द्वारा, आयोग ने संबंधित मामलों पर विचार करने के बाद, पी. पी. ए. के अनुसार दरों को अपनाया। इसके बाद, वर्तमान याचिका [2023] 8 एस. सी. आर. द्वारा दायर की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19.02.2013 पर पहला उत्तरदाता। याचिका के कुछ हिस्सों को निर्धारित करना इस स्तर पर प्रासंगिक है। याचिका अधिनियम की धारा 79 के तहत दायर की गई है जिसे प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से बिजली की खरीद को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे और पी. पी. ए. के अनुच्छेद 13 और 17 के तहत पढ़ा गया है। 'निर्माण अवधि के दौरान' कानून में परिवर्तन के कारण मुआवजे के लिए पक्षों के बीच। जिन तथ्यों को हम विज्ञापन के लिए प्रासंगिक नहीं मानते हैं, उन्हें निर्धारित करने के बाद, निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाता है।

" 5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान कानून में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं जिनके कारण परियोजना की पूंजीगत लागत में काफी वृद्धि होगी:

क) परियोजना के लिए भूमि की घोषित कीमत में वृद्धि जिसमें विद्युत केंद्र, मोहेर, मोहेर-अमलोहरी विस्तार और छत्रसाल कैप्टिव कोयला ब्लॉक के लिए भूमि शामिल है;

ख) मोहर, मोहर-अमलोहरी के लिए पुनर्वास और पुनर्वास योजना (आर एंड आर योजना) के कार्यान्वयन की लागत में वृद्धि।

च) परियोजना में उपयोग किए जाने वाले सीमेंट और इस्पात पर उत्पाद शुल्क का शुल्क; और
छ) परियोजना के लिए आयातित खनन उपकरणों पर सीमा शुल्क का शुल्क।

(12) चूंकि, इस मामले में, हम केवल दो पहलुओं से संबंधित हैं, अर्थात् खंड (ई) और खंड (जी) के तहत दावे हम इसे उचित समझते हैं।

केवल प्रथम प्रत्यर्थी के अभिवचनों को संदर्भित करने के लिए

एक ही।

जल ग्रहण प्रणाली की लागत में वृद्धि

" 65. सासण यू. एम. पी. पी. के लिए आर. एफ. पी. के खंड 1.4 (वी) के अनुसार, खरीदारों को अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से पानी का सेवन रयान पावर खरीद केंद्र V प्रदान करना था।

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

अध्ययन रिपोर्ट। वैपकोस (भारत सरकार की एक प्रमुख एजेंसी) को पानी के सेवन का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था। वैपकोस ने विशेषज्ञ एजेंसी के रूप में अपनी रिपोर्ट में पानी लेने वाले पंप हाउस के स्थान और अंतर्ग्रहण पंप हाउस से बिजली संयंत्र तक पाइपलाइन मार्ग की पहचान की। यह रिपोर्ट बोली जमा करने से पहले सभी बोलीदाताओं को उपलब्ध कराई गई थी ताकि बोलीदाता अपनी वित्तीय बोली की तैयारी में पानी के सेवन की प्रणाली की लागत को ध्यान में रख सकें, यानी वह शुल्क जिस पर खरीददारों को बिजली की आपूर्ति की जाएगी। जल ग्रहण प्रणाली के निर्माण के लिए कुल अनुमानित लागत

वैपकोस द्वारा रिपोर्ट में बताए गए स्थान और मार्ग के लिए लगभग Rs.92 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था। डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. रिपोर्ट को अनुमानित लागत के साथ संलग्न किया गया है और इसे अनुलग्नक पी-24 (कोली) के रूप में चिह्नित किया गया है।

" 66. आर. पावर द्वारा याचिकाकर्ता का अधिग्रहण करने के बाद, विस्तृत इंजीनियरिंग अभ्यास के हिस्से के रूप में तकनीकी व्यवहार्यता की पुष्टि करने के लिए वैपकोस को नियुक्त किया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान, यह पता चला कि डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. द्वारा पानी के सेवन के स्थान को अंतिम रूप देने से पहले बोली एक उपयुक्त स्थान नहीं था और बिजली संयंत्र को पानी की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित नहीं करता है। यह भी पाया गया कि डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. द्वारा बोली-पूर्व रिपोर्ट में बताए गए मूल स्थान पर पानी के सेवन के परिणामस्वरूप कम मौसम के दौरान काफी समय तक बिजली संयंत्र बंद रहा होगा।

" 67. इसके बाद, डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. ने विस्तृत खानमापी अध्ययन किए और पानी के सेवन के लिए एक नए स्थान की सिफारिश की, जो बिजली संयंत्र से 23 कि. मी. दूर था, जबकि शुरू में यह संकेत दिया गया था

बोली लगाने का समय (मूल स्थान)। यह रेखांकित किया गया कि नया स्थान बिजली संयंत्र को विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। दूरी में वृद्धि के कारण, मार्ग के साथ जलमग्न क्षेत्र और निर्माण के समय, जल ग्रहण प्रणाली की लागत में काफी वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे विस्तृत है। संशोधित स्थान की सिफारिश करने वाली वैपकोस की रिपोर्ट संलग्न है।

इसके साथ और अनुलग्नक पी-25 "के रूप में चिह्नित।

" 68. नए स्थान के लिए जल प्रणाली के निर्माण की लागत रु। 244 क्र. उपर्युक्त राशि में से,

Rs.185 करोड़ पहले ही खर्च किए जा चुके हैं और रु। 59 करोड़ों खर्च किए जाने हैं। जल ग्रहण प्रणाली के स्थान में परिवर्तन के कारण जल ग्रहण प्रणाली की लागत में अनुमानित वृद्धि Rs.152 करोड़ है। चूंकि यह वृद्धि सीधे [2023] 8 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रदान की गई वैपकोस रिपोर्ट में त्रुटि के कारण

" 76. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 2002 की अधिसूचना 21-सीमा शुल्क दिनांक 01.03.2002 के अनुसार, वृहद बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक वस्तुओं पर सीमा शुल्क

शून्य के रूप में निर्धारित किया गया है जिसका अर्थ है कि एक बड़ी बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए आयातित वस्तुओं पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा। 2002 की अधिसूचना 21 की एक प्रति-सीमा शुल्क संलग्न है।

इसके साथ और अनुलग्नक पी-32 "के रूप में चिह्नित किया गया।

" 77. ससान यू. एम. पी. पी. को विद्युत मंत्रालय के पत्र सं. 1 के अनुसार सैद्धांतिक रूप से वृहद विद्युत परियोजना का दर्जा दिया गया था। एफ. नं. 12/18/2006

" 80. 05.05.2011 पर, याचिकाकर्ता ने ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार को आवेदन किया सासन के लिए खनन उपकरणों के आयात के लिए सिफारिश पत्र

शून्य सीमा शुल्क के तहत यू. एम. पी. पी. जैसा कि दूसरे के लिए लागू होता है। परियोजना के बिजली संयंत्र जैसे उपकरण।

यह अनुप्रयोग Ryana पावर खरीद केंद्र v. ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

2002 की अधिसूचना 21-सीमा शुल्क पर आधारित था। हालांकि, एक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17.06.2011 के माध्यम से, बिजली मंत्रालय ने सूचित किया है कि यू. एम. पी. पी. के लिए सीमा शुल्क के लिए छूट केवल बिजली उपकरणों के संबंध में दी गई है, जिसे अग्रेषित किया गया था।

20.06.2011 पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को। 05.05.2011 और 17.06.2011 दिनांकित पत्रों की प्रतियां इसके साथ संलग्न की गई हैं और अनुलग्नक पी-33 (कोली) के रूप में चिह्नित की गई हैं।

भविष्य में पूंजीगत लागत में वृद्धि। इस संबंध में, याचिकाकर्ता निम्नलिखित राहत का दावा कर रहा है: (क) कानून में परिवर्तन के संबंध में जहां अतिरिक्त पूंजी लागत पहले ही वहन की जा चुकी है, यह माननीय आयोग [2023] 8 एस. सी. आर. कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून में बदलाव। वास्तविक भुगतान का दावा देय होने पर किया जाएगा।
चर्चाओं और तथ्यों से यह स्पष्ट है कि:

" 89.उपरोक्त

(क) राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति के उद्देश्यों में से एक उचित मूल्य निर्धारण और आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए बिजली क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुरक्षित करना है।

(ख) अधिनियम की धारा 63 के तहत बिजली की खरीद वैधानिक ढांचे द्वारा नियंत्रित होती है जिसमें (i) अधिनियम की धारा 63, (ii) भारत सरकार के दिशानिर्देश और (iii) आर. एफ. पी. और पी. पी. ए. मानक दस्तावेज शामिल हैं।

(ग) अधिनियम की धारा 63 के संदर्भ में सफल बोली का चयन अधिनियम की धारा 61 के तहत मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप किया जाना चाहिए जिसका अर्थ है कि अधिनियम की धारा 63 के तहत शुल्क को अपनाते समय, धारा 61 के तहत निर्धारित सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है।

(घ) वैधानिक ढांचे के अनुसार बिजली की खरीद

अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ दिशानिर्देशों द्वारा शासित पूर्व-अनुमोदित और अंतिम रूप दिए गए पी. पी. ए. के संदर्भ में एक वैधानिक अनुबंध का गठन करता है। (ई) पी. पी. ए. प्रतिकूल रूप से प्रभावित पक्ष (वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता) को बहाल करने/पुनर्स्थापित करने के लिए इस माननीय आयोग द्वारा शुल्क के समायोजन की परिकल्पना करता है।

" 90. यह भी ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम की धारा 79 (1) (बी) के तहत, इस माननीय आयोग को याचिकाकर्ता जैसी उत्पादक कंपनियों के शुल्क को विनियमित करने की शक्ति दी गई है, जिनके पास एक से अधिक राज्यों में बिजली के उत्पादन और बिक्री के लिए एक समग्र योजना है।

" 91.वर्तमान याचिका कानून में परिवर्तनों के कारण मुआवजे के लिए दायर की गई है, जिसने परियोजना की पूंजी लागत को प्रभावित किया है और साथ ही साथ रयान पावर खरीद केंद्र V.

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

खरीददारों द्वारा प्रदान की गई सांकेतिक लागतों से अधिक, जो आर पावर की वित्तीय बोली के निर्माण के लिए आधार थे।

" 92. याचिकाकर्ता ने एक सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए खरीददारों से संपर्क किया था। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा खरीददारों के साथ अप्रत्याशित और अनुचित वाणिज्यिक निहितार्थ के लिए एक सौहार्दपूर्ण समाधान की मांग करने के लिए किए गए सभी प्रयास विफल साबित हुए हैं। इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता के लिए यह अनिवार्य और आवश्यक हो गया है कि वह याचिका में अनुरोध किए गए उचित आदेश जारी करने के लिए इस माननीय आयोग के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करे।

" 93. यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान याचिका का आह्वान करते हुए दायर किया गया है:

(क) अधिनियम की धारा 79 (1) ख) जिसके तहत इस माननीय आयोग को याचिकाकर्ता के शुल्क को विनियमित करने की शक्ति है।

(ग) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (व्यवसाय संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 82,92 और 113। (घ) पी. पी. ए. के अनुच्छेद 13 को प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 5,17 के साथ पढ़ा जाता है, जिसके संदर्भ में -

माननीय आयोग के पास किसी भी विवाद पर निर्णय लेने की शक्ति है

जो प्रशुल्क या किसी प्रशुल्क संबंधी मामलों के निर्धारण में या उसके संबंध में किसी भी परिवर्तन का दावा करता है, या जिसके परिणामस्वरूप आंशिक या पूर्ण रूप से प्रशुल्क में परिवर्तन हो सकता है।

" 104. जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ 75-83 में विस्तृत है, 2002 की अधिसूचना 21-वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सीमा शुल्क ने मेगा बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी। याचिकाकर्ता को कोयला खदान के संचालन के लिए उपकरण आयात करने की आवश्यकता थी जो परियोजना का एक अभिन्न अंग है।

" 105. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त अधिसूचना के अनुसार, कोई भी संस्था जो सीमा शुल्क छूट का दावा करने का इरादा रखती है, उसकी आवश्यकता थी

छूट प्रमाणपत्र के लिए प्रायोजक प्राधिकरण को आवेदन करना। सीमा शुल्क छूट का दावा करने के लिए यह आवश्यक था। इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश सरकार को याचिकाकर्ता के मामले की सिफारिश करने के लिए पत्र लिखा।

खनन उपकरणों पर शून्य सीमा शुल्क के लिए 5.5.2011 पर सीमा शुल्क। "[2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 106. यह प्रस्तुत किया जाता है कि 17.06.2011 दिनांकित एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से, बिजली मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार को सूचित किया कि यू. एम. पी. पी. के लिए सीमा शुल्क के लिए छूट केवल बिजली उपकरणों के संबंध में दी गई है। सासन यू. एम. पी. पी. के लिए आयातित खनन उपकरणों पर याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई सीमा शुल्क की कुल राशि रु. 361.47 अब तक करोड़। कुल

" 107. यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्युत मंत्रालय का निर्णय पी. पी. ए. के अनुच्छेद 13.1 के तहत कानून में बदलाव के बराबर है और याचिकाकर्ता इसके लिए मुआवजे का हकदार है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को आयात करने की अनुमति नहीं दी जा रही है शून्य सीमा शुल्क के तहत खनन उपकरण, जैसा कि परियोजना के बिजली संयंत्रों जैसे अन्य उपकरणों के लिए दिया जाता है, पी. पी. ए. के अनुच्छेद 13.1 के तहत कानून में परिवर्तन के रूप में योग्य है।

" 108. यह प्रस्तुत किया जाता है कि सासन यू. एम. पी. पी. के लिए आर. एफ. पी. के अनुसार, खरीददारों को पानी के सेवन अध्ययन रिपोर्ट प्रदान करनी थी। यह अध्ययन वैपकोस द्वारा किया गया था और बोली जमा करने से पहले सभी बोलीदाताओं को रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार जल ग्रहण प्रणाली की लागत लगभग Rs.92 करोड़ थी।

इस अनुमान को वित्तीय बोली जमा करने के समय बोली में शामिल किया गया था। "

" 109. यह प्रस्तुत किया जाता है कि आर पावर द्वारा याचिकाकर्ता का अधिग्रहण करने के बाद,

वैपकोस को तकनीकी व्यवहार्यता की पुष्टि करने का काम सौंपा गया था

शुरुआत में बोली लगाने के समय (मूल स्थान) संकेतित 12.50 कि. मी. की तुलना में। " 110. यह प्रस्तुत किया जाता है कि दूरी में वृद्धि, मार्ग के साथ जलमग्न क्षेत्र और निर्माण के समय के कारण जल ग्रहण प्रणाली की लागत में काफी वृद्धि हुई है। नए स्थान के लिए जल प्रणाली के निर्माण की लागत रु. 244 क. जल ग्रहण प्रणाली के स्थान में परिवर्तन के कारण जल ग्रहण प्रणाली की लागत में अनुमानित वृद्धि Rs.152 करोड़ है। रयान पावर खरीद केंद्र V.

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 111. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जल ग्रहण प्रणाली की लागत में वृद्धि खरीददारों द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट में त्रुटियों के कारण हुई है और इसलिए, खरीददार इसके लिए बाध्य हैं

याचिकाकर्ता को लागत में अंतर के लिए क्षतिपूर्ति करना। यह आगे है

प्रस्तुत किया कि चूंकि जल पाइपलाइन गलियारा पावर स्टेशन भूमि का हिस्सा है और जल अंतर्ग्रहण पाइपलाइन इसका एक अभिन्न हिस्सा है

विद्युत केंद्र, जल ग्रहण प्रणाली की सांकेतिक लागत में किसी भी बदलाव को कानून में बदलाव के तहत शामिल किया जाएगा।

" 120. अधिनियम की धारा 79, अन्य बातों के साथ-साथ, माननीय आयोग को निम्नलिखित अधिकार देती है:

(क) केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनियों के अलावा अन्य उत्पादन कंपनियों के शुल्क को विनियमित करें यदि ऐसी उत्पादन कंपनियां एक से अधिक राज्यों में बिजली उत्पादन और बिक्री के लिए एक समग्र योजना में प्रवेश करती हैं या अन्यथा करती हैं; और

(ख) वितरण से जुड़े विवादों पर निर्णय लेना।

उत्पादन करने वाली कंपनियों के शुल्क के विनियमन से जुड़े मामलों के संबंध में कंपनियां या पारेषण लाइसेंसधारी।

" 128. यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में ऐसी स्थिति शामिल है जहां पी. पी. ए. के तहत क्षतिपूर्ति तंत्र

कानून में परिवर्तन के लिए मुआवजा विफल रहा है। यह किसी प्रभावित पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में बहाल करने के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है जैसे कि कानून में परिवर्तन नहीं हुआ था। इसलिए, इस माननीय आयोग के लिए यह एक उपयुक्त मामला है कि वह धारा 79 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करे और अनुच्छेद 13 के उद्देश्य और उद्देश्य को बनाए रखने के लिए एक तंत्र तैयार करे-आर्थिक बहाली प्रदान करने के लिए।

" 129. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पी. पी. ए. एक ऐसे परिदृश्य की परिकल्पना करता है जहां यह माननीय आयोग किसी भी परिवर्तन और/या शुल्क के निर्धारण के लिए किसी पक्ष द्वारा किए गए दावे से संबंधित मुद्दों या किसी भी पक्ष द्वारा किए गए शुल्क या दावों से संबंधित किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से शुल्क में किसी भी बदलाव या ऐसे किसी भी दावे के निर्धारण से संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप शुल्क में परिवर्तन हो सकता है। इस संदर्भ में अनुच्छेद 13 और 17 उल्लेखनीय हैं। जबकि पी. पी. ए. के अनुच्छेद 13 में "कानून में परिवर्तन" की स्थिति में शुल्क समायोजन की परिकल्पना की गई है, पी. पी. ए. के अनुच्छेद 17 में किसी भी पक्ष द्वारा शुल्क में किसी भी बदलाव या निर्धारण या किसी भी पक्ष द्वारा किए गए शुल्क या दावों से संबंधित किसी भी मामले के लिए किए गए दावे के मामले में माननीय आयोग द्वारा विवाद समाधान का प्रावधान है, जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से [2023] 8 एस. सी. आर.

शुल्क में किसी भी परिवर्तन या इनमें से किसी के निर्धारण से संबंधित

दावों के परिणामस्वरूप शुल्क में परिवर्तन हो सकता है।

" 142. इसलिए याचिकाकर्ता अत्यंत विनम्रता और सम्मानपूर्वक प्रार्थना करता है कि यह माननीय आयोग इस पर निर्णय लेने के लिए प्रसन्न हो

याचिका प्रस्तुत करना:

(क) घोषणा करें कि उपरोक्त पैराग्राफ 5 में निर्माण अवधि के दौरान कानून में परिवर्तन और/या परिवर्तनों के रूप में निर्धारित वस्तुओं के कारण परियोजना की पूंजी लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) याचिकाकर्ता को उसी आर्थिक स्थिति में पुनर्स्थापित करें जैसे कि कानून में उक्त परिवर्तन नहीं हुए थे और एक ऐसा तंत्र तैयार करें जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को कानून में परिवर्तनों के कुल वित्तीय प्रभाव और खाते की पूंजी लागत में वृद्धि के लिए मुआवजा दिया जाता है, जिसका विवरण उपरोक्त पैराग्राफ 113 में दिया गया है; और

(ग) इस तरह के किसी भी अन्य और आगे के राहत को पारित करें
प्रकृति और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित मानता है।

(13) दलीलों के आदान-प्रदान के बाद, आयोग ने दिनांकित 04.02.2015 पारित किया। चूँकि हम इन अपीलों में दो पहलुओं द्वारा हिरासत में लिए जाने के लिए हैं, हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर ध्यान देते हैं:

" 30. याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि के खंड 1.4 (वी) के अनुसार

सासन यू. एम. पी. पी. के लिए आर. एफ. पी., अधिकृत के माध्यम से खरीददार

प्रतिनिधि को जल सेवन अध्ययन रिपोर्ट प्रदान करनी थी। वैपकोस (भारत सरकार की एक प्रमुख एजेंसी) को पानी के सेवन का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था। वैपकोस ने विशेषज्ञ एजेंसी के रूप में अपनी रिपोर्ट में पानी लेने वाले पंप हाउस के स्थान और अंतर्ग्रहण पंप हाउस से बिजली संयंत्र तक पाइपलाइन मार्ग की पहचान की। यह रिपोर्ट बोली जमा करने से पहले सभी बोलीदाताओं को उपलब्ध कराई गई थी ताकि बोलीदाता पानी के सेवन की प्रणाली की लागत को ध्यान में रख सकें।

उनकी वित्तीय बोली की तैयारी में अर्थात वह शुल्क जिस पर खरीददारों को बिजली की आपूर्ति की जाएगी। स्थान और मार्ग के लिए जल ग्रहण प्रणाली के निर्माण के लिए कल अनुमानित लागत

वैपकोस द्वारा रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि

लगभग ₹92 करोड़। आर. पावर द्वारा परियोजना के अधिग्रहण के बाद, विस्तृत इंजीनियरिंग अभ्यास के हिस्से के रूप में तकनीकी व्यवहार्यता की पुष्टि करने के लिए वैपकोस को नियुक्त किया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान यह पता चला कि बोली लगाने से पहले वैपकोस द्वारा अंतिम रूप दिया गया जल ग्रहण स्थान एक उपयुक्त स्थान नहीं था और हरियाणा पावर खरीद केंद्र V नहीं है।

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

बिजली संयंत्र को पानी की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करें। यह भी था

पाया कि मूल स्थान पर पानी का सेवन द्वारा इंगित किया गया है

डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. ने बोली-पूर्व रिपोर्ट में बंद करने का परिणाम दिया होगा।

कम मौसम के दौरान काफी अवधि के लिए बिजली संयंत्र का निर्माण।

इसके बाद, डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. ने विस्तृत बाथिमेट्रिक अध्ययन किए और

जल ग्रहण के लिए एक नए स्थान की सिफारिश की, जो 23 कि. मी. था।
बिजली संयंत्र से शुरू में संकेतित 12,5 कि. मी. की तुलना में

बोली लगाने का समय (मूल स्थान)। यह बताया गया कि नए

यह स्थान बिजली संयंत्र को विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

निम्नलिखित विवरण के अनुसार जल ग्रहण प्रणाली की लागत (अनुलग्नक)
याचिका का पी-26) और वैपकोस की पिछली रिपोर्ट के अनुसार:

एस. नहीं। लागत वस्तु

पहले के वैपकोस वर्तमान अनुमान

के अनुसार

रिपोर्ट करें।

(* करोड़)

(2 करोड़)

पंप हाउस की लागत

21.00

62.97

पुल की लागत

10.5

0

पाइप लाइन की आपूर्ति

73.91

30.50

14 ए.

पाइप लाइन बिछाना

16.7

0

57.97

10.2

0

मैकेनिकल

20.32

16

विद्युत

3.50

4.02

पंप हाउस के लिए ड्रेजिंग

25.13

कुल

244.32

92.40

31. एम. पी. पी. एम. सी. एल. ने प्रस्तुत किया है कि यह एक खर्च है जो

याचिकाकर्ता लेकिन अनुच्छेद 13.1 के तहत "कानून में परिवर्तन" के तहत शामिल नहीं है। 1 पी. पी. ए. से। हालांकि, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि लागत याचिकाकर्ता द्वारा वहन की गई है और बोली जमा करने से पहले खरीदार के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिए गए अनुमानों से अधिक है। एचपीसीसी ने प्रस्तुत किया है कि

बोली दस्तावेज में दी गई कीमत और अन्य विवरण सूचना के माध्यम से थे और यह बोलीदाताओं को स्वतंत्र जांच करने के लिए था

और जानकारी और विवरणों को सत्यापित करें। परियोजना के लिए पानी के सेवन के संबंध में बोली लगाने के समय खरीदारों या बोली प्रक्रिया समन्वयकों द्वारा कोई गलत व्याख्या नहीं की गई है। विशिष्ट अस्वीकृति और स्वतंत्र जांच करने की आवश्यकता को देखते हुए, याचिकाकर्ता को बोली लगाने से पहले मामले में उचित पूछताछ करने की आवश्यकता थी और बोली लगाने वाले केवल बोली प्रक्रिया समन्वयक द्वारा दी गई सांकेतिक जानकारी के आधार पर आगे बढ़ने के हकदार नहीं थे।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

32. हमने याचिकाकर्ता के निवेदन पर विचार किया है और उत्तरदाता। ₹1 करोड़ की सांकेतिक लागत के मुकाबले, नए स्थान के लिए जल प्रणाली के निर्माण की लागत उपरोक्त राशि में से 244 करोड़ है, 185 करोड़ की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है और 59 करोड़ रुपये की शेष राशि खर्च की जानी है। जल ग्रहण प्रणाली के स्थान में बदलाव के कारण जल ग्रहण प्रणाली की लागत में अनुमानित वृद्धि 152 करोड़ रुपये है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि यह वृद्धि सीधे तौर पर प्रदान की गई वैपकोस रिपोर्ट में त्रुटि के कारण है

बोली लगाने वालों को बोली लगाने से पहले के चरण में, याचिकाकर्ता को इसके लिए मुआवजा दिया जाना आवश्यक है।

33. हमारे विचार में, दावा अनुच्छेद 13.1 के किसी भी प्रावधान के तहत नहीं आता है। 1 पी. पी. ए. से। याचिकाकर्ता को इस बात से अवगत होना चाहिए कि जल ग्रहण प्रणाली की लागत प्रकृति में सूचक है और अनुच्छेद 13 के तहत "कानून में परिवर्तन" के तहत शामिल नहीं है, इसलिए बोली तैयार करने से पहले खुद को वास्तविक स्थल स्थितियों के साथ पूरी तरह से सूचित करना चाहिए था और तदनुसार सांकेतिक लागत पर भरोसा करने के बजाय बोली का हवाला देते हुए जल सेवन प्रणाली के संभावित अनुमानों को ध्यान में रखना चाहिए था। इस संबंध में आर. एफ. पी. दस्तावेज़ के पैरा 2.7.1 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

" 2.7 .2.1 बोलीदाता स्वतंत्र जांच करेगा और संतुष्ट करेगा।

उसकी बोली पर प्रभाव। बोली का आकलन करते समय, यह माना जाता है कि बोलीदाता ने भारी सामग्री को उतारने और/या परिवहन के लिए सड़कों, पुलों, बंदरगाहों आदि की साइट स्थितियों का निरीक्षण और जांच की है और इसके डिजाइन, उपकरण के आकार को आधार बनाया है और ऐसी सभी प्रासंगिक स्थितियों और जोखिमों, आकस्मिकताओं और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसकी कीमत तय की है। बिजली की आपूर्ति को प्रभावित या प्रभावित कर सकता है।

आर. एफ. पी. दस्तावेज़ के पैरा 4 में यह प्रावधान किया गया है कि बोली दस्तावेजों में दिए गए मूल्य निर्धारण और अन्य विवरण केवल जानकारी के माध्यम से हैं और यह बोलीदाताओं के लिए स्वतंत्र जांच करने और विवरण और जानकारी को सत्यापित करने के लिए था। पैरा 4 को निम्नानुसार निकाला गया है:

" 4. जबकि आर. एफ. पी. अच्छी भावना से तैयार किया गया है, न तो खरीदार, अधिकृत प्रतिनिधि और बिजली वित्त निगम (पी. एफ. सी.) और न ही उनके निदेशक या कर्मचारी या सलाहकार/रयान पावर खरीद केंद्र V.

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

सलाहकार कोई भी प्रतिनिधित्व या वारंटी, व्यक्त या निहित करते हैं, या किसी भी जिम्मेदारी या दायित्व को स्वीकार करते हैं, जो भी हो।

यहाँ किसी भी कथन या चूक, या यहाँ निहित जानकारी की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में, और इस आर. एफ. पी. की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के रूप में किसी भी कानून, कानून, नियमों या विनियमों के तहत कोई दायित्व नहीं होगा, भले ही किसी भी अधिनियम या अधिनियम द्वारा बोलीदाता को कोई नुकसान या क्षति हुई हो।

उनकी ओर से चूक "।

इसलिए, यह याचिकाकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह सत्यापित करे

पानी के सेवन के स्थान की उपयुक्तता और बिजली संयंत्र के लिए विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित करना और प्रासंगिक अनुमानित कार्य करना। जल ग्रहण प्रणाली की लागत स्वतंत्र रूप से और इसमें कारक

बोली में अनुमान लगाया जाता है ताकि बोली में एक यथार्थवादी लागत दिखाई दे। याचिकाकर्ता ऐसा करने में विफल रहा है, खाते पर लागत में वृद्धि

इस सिर का स्वीकार्य नहीं है "।

(14) जहाँ तक सीमा शुल्क निंग उपकरण के अधिरोपण से संबंधित प्रश्न का संबंध है, उसी पर अनुच्छेद डी 41 में चर्चा की गई है।

" 40. हमने याचिकाकर्ता के निवेदन पर विचार किया है और उत्तरदाताओं। अधिसूचना No.49/2006 निम्नानुसार प्रदान करती है:

अधिसूचना संख्या 49/2006-सीमा शुल्क

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि यह जनहित में आवश्यक है,

करते हैं, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं

वित्त मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना (राजस्व विभाग) सं. 21/2002-सीमा शुल्क, दिनांक 1

मार्च, 2002, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, असाधारण संख्या जी. एस. आर. 118 (ई), दिनांक 1 मार्च,

2002 , अर्थात्: उक्त अधिसूचना में कहा गया है,

(I) तालिका में, S.No.400 के विपरीत, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए,

निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

" किसी भी मेगा बिजली परियोजना की स्थापना के लिए आवश्यक सामान, जो संयुक्त सचिव [2023] 8 एस. सी. आर. के पद से कम के अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विद्युत मंत्रालय में भारत सरकार को, अर्थात्

कहो (क) जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में स्थित 700 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता का अंतर-राज्यीय ताप विद्युत संयंत्र,

नागालैंड और त्रिपुरा; या

(ख) खंड में निर्दिष्ट राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में स्थित 1000 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता का अंतर-राज्यीय ताप विद्युत संयंत्र।

(क) ऊपर; या (ग) जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में स्थित 350 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता का अंतर-राज्यीय पनबिजली संयंत्र; या

(घ) खंड में निर्दिष्ट राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में स्थित 500 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता का अंतर-राज्यीय पनबिजली संयंत्र।

(ग) ऊपर";

(II) अनुलग्नक में, खंड (क) के उपखंड (ii) और (iii) के लिए शर्त संख्या 86 में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

" (ii) बिजली खरीद राज्य, सैद्धांतिक रूप से, बिजली मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली अवधि के भीतर उस राज्य के सभी शहरों में वितरण का निजीकरण करने का कार्य करता है, जिनकी आबादी दस लाख से अधिक है। .

[F.No.354/104/2003-TRU]

यह देखा गया है कि भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित नीति दिशानिर्देश इसके पत्र सं। ए-118/2003-आई. पी. सी. ए. टी. 2.8.2006 ने कहा है कि एक अंतर-राज्य ताप विद्युत संयंत्र

1000 मेगावाट या उससे अधिक की क्षमता मेगा अनुदान के लिए पात्र है।

क्या स्थिति है। इसमें आगे कहा गया है:

" शून्य सीमा शुल्क: अधिसूचना के संदर्भ में

वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (विभाग)

राजस्व) सं. 21/2002-सीमा शुल्क दिनांक 1.3.2002 पढ़ें

संख्या 49/2006-सीमा शुल्क दिनांक 26.5.2006 के साथ, आयात

इनके लिए पूंजीगत उपकरण सीमा शुल्क से मुक्त होंगे।

परियोजनाएँ "।

.....यह विचार किया जाना चाहिए कि क्या अधिसूचना के तहत जैसा कहा गया है

खनन उपकरणों को सीमा शुल्क से छूट दी गई थी।

सीमा शुल्क अधिसूचना No.21/RYANA पावर खरीद केंद्र v के तहत आंतरिक छूट संख्या 122।

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

2002 समय-समय पर संशोधित वस्तुओं में उन वस्तुओं की सूची होती है जिन्हें सीमा शुल्क से छूट दी जाती है। यह देखा गया है कि 2002 की अधिसूचना 21-सीमा शुल्क स्पष्ट रूप से बिजली परियोजनाओं का सीमांकन करती है और

खनन परियोजनाएं अलग से। यह देखा गया है कि सूची के Ser No.399 पर, कोयला खनन परियोजनाएं सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। सर नंबर 400 केवल मेगा बिजली परियोजना को सीमा शुल्क के भुगतान से छूट देता है और इसमें कोई उल्लेख नहीं है कि इसमें कैप्टिव बिजली संयंत्र शामिल हैं।

इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि कट-ऑफ तिथि पर खनन उपकरणों पर छूट थी और याचिकाकर्ता ने इसे स्वीकार किया था।

बोलियों को उद्धृत करते समय ऐसी छूट पर विचार करें। याचिका में ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह संकेत दे सके कि बोली लगाने से पहले खरीददारों या उनके प्रतिनिधि द्वारा ऐसा कोई प्रभाव दिया गया था। पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता का यह निवेदन कि बिजली मंत्रालय के निर्णय ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17.06.2011 में विस्तार से बताया है और ऊर्जा द्वारा इनकार किया गया है

विभाग, मध्य प्रदेश सरकार प्रदान करेगी सासान यू. एम. पी. पी. के लिए शून्य सीमा शुल्क के तहत खनन उपकरणों के आयात के लिए सिफारिश पत्र पी. पी. ए. के अनुच्छेद 13.1 के तहत "कानून में परिवर्तन" के बराबर है और याचिकाकर्ता इसके हकदार हैं

उसी के लिए क्षतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं है और इसलिए नहीं

इस संबंध में मुआवजा उपलब्ध होगा।

न्यायाधिकरण से पहले की अपील

(15) इसके कारण पहले प्रतिवादी द्वारा अधिनियम की धारा 111 के तहत अपील दायर की गई। यह उचित है कि हमने सटीक मामला निर्धारित किया है। न्यायाधिकरण के समक्ष प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा एच की स्थापना की गई है।

" 9.5 रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जल अंतर्ग्रहण पंप हाउस स्थान और अंतर्ग्रहण पंप हाउस से बिजली संयंत्र तक पाइपलाइन मार्ग की पहचान की। यह रिपोर्ट सभी बोलीदाताओं को उपलब्ध कराई गई थी।

बोली जमा करने से पहले ताकि बोलीदाता अपनी वित्तीय बोलियों की तैयारी में पानी के सेवन की प्रणाली की लागत को ध्यान में रख सकें, यानी वह शुल्क जिस पर खरीददारों को बिजली की आपूर्ति की जाए। डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. द्वारा रिपोर्ट में बताए गए स्थान और मार्ग के लिए जल ग्रहण प्रणाली के निर्माण की कुल लागत Rs.92 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था। जल ग्रहण प्रणाली परियोजना का एक अभिन्न अंग है जिसके बिना इसे स्थापित करना और संचालित करना संभव नहीं है।

परियोजना। डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. रिपोर्ट में अनुमानित लागत के साथ-साथ इसके साथ संलग्न और अनुलग्नक ए-14 के रूप में चिह्नित।

9.6 आर. पावर को सफल बोलीदाता घोषित किए जाने और अपीलकर्ता कंपनी को आर. पावर को हस्तांतरित किए जाने के बाद, वैपकोस [2023] 8 एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भाग के रूप में तकनीकी व्यवहार्यता की पुष्टि करने के लिए फिर से नियुक्त

विस्तृत इंजीनियरिंग अभ्यास। इस प्रक्रिया के दौरान, यह सामने आया कि डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. द्वारा पी. एफ. सी./खरीददारों के लिए तैयार की गई अपनी पिछली रिपोर्ट के अनुसार पानी के सेवन के स्थान को अंतिम रूप दिया गया और सभी के लिए उपलब्ध कराया गया।

बोली जमा करने से पहले बोली लगाने वाले एक उपयुक्त स्थान नहीं थे और बिजली संयंत्र को पानी की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित नहीं करते थे। यह भी सामने आया कि डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. द्वारा पूर्व-बोली रिपोर्ट में बताए गए मूल स्थान पर पानी के सेवन का परिणाम होगा

मन्द मौसम के दौरान एक वर्ष में काफी अवधि के लिए बिजली संयंत्र को बंद करना। इसलिए, डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. ने पानी के सेवन के लिए एक नए स्थान की सिफारिश की, जो बिजली संयंत्र से 23 कि. मी. दूर था, जबकि बोली (मूल स्थान) के समय शुरू में 12,5 कि. मी. का संकेत दिया गया था। यह रेखांकित किया गया कि नया स्थान होगा बिजली संयंत्र को विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित करें। दूरी में वृद्धि, मार्ग के साथ जलमग्न क्षेत्र और निर्माण के समय में वृद्धि के कारण, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार स्थान में परिवर्तन के कारण जल ग्रहण प्रणाली की लागत में काफी वृद्धि हुई है। संशोधित स्थान की सिफारिश करने वाली डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. की रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है और इसे अनुलग्नक ए-15 के रूप में चिह्नित किया गया है।

9.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्थान में परिवर्तन के कारण, निम्नलिखित मामलों में जल ग्रहण प्रणाली की लागत में वृद्धि हुई है:

(क) जबकि मार्ग की लंबाई बढ़कर 23 किलोमीटर हो गई, पाइप की लंबाई 24 किलोमीटर (12 किलोमीटर की 2 पाइप लाइनें) से बढ़कर 59 किलोमीटर (8 किलोमीटर की 2 पाइप लाइनें और 14 किलोमीटर की 3 पाइप लाइनें) हो गई।

(ख) गहरे पंप हाउस के कारण लागत में वृद्धि।

लगभग एक करोड़ रुपये की काफी वृद्धि हुई है। 176 जल ग्रहण प्रणाली की लागत में करोड़, जो अब लगभग Rs.268 करोड़ होने का अनुमान है। जल ग्रहण प्रणाली के लिए नए स्थान के लिए लागत का विभाजन इसके साथ संलग्न किया गया है और इसे अनुलग्नक ए-16 के रूप में चिह्नित किया गया है। 9.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जल ग्रहण प्रणाली की लागत में वृद्धि खरीददारों द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट में त्रुटियों के कारण हुई है और इसलिए, खरीददारों को लागत में अंतर के लिए अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता है।

रयान पावर खरीद केंद्र V. ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

9.9 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि जल पाइपलाइन गलियारा विद्युत केंद्र के लिए भूमि का हिस्सा है और जल अंतर्ग्रहण पाइपलाइन विद्युत केंद्र का एक अभिन्न अंग है, इसलिए जल अंतर्ग्रहण प्रणाली की सांकेतिक लागत में किसी भी बदलाव को पी. पी. ए. के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में कानून में परिवर्तन के तहत शामिल किया जाता है क्योंकि यह परियोजना की भूमि की लागत में परिवर्तन के बराबर है। वास्तव में, एल. डी. सामान्य आयोग ने विवादित आदेश में उल्लेख किया है कि बिजलीघर के लिए भूमि के घोषित मूल्य के अनुमान में जल ग्रहण प्रणाली शामिल है। विवादित आदेश के सक्रिय भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 19. भूमि की घोषित कीमत में परिवर्तन "कानून में परिवर्तन" के अंतर्गत आता है। खरीददार इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि

"कानून में परिवर्तन" के तहत व्यय स्वीकार्य है। पावर स्टेशन के लिए भूमि की घोषित कीमत 190.677 करोड़ बताई गई थी। यह खरीददारों के प्रतिनिधि से बोलीदाताओं को दिनांकित 23.10.2006 संचार से सत्यापित किया गया है। इसमें बिजली संयंत्र क्षेत्र, ईंधन परिवहन प्रणाली भूमि, जल पाइपलाइन गलियारा और राख पाइपलाइन गलियारा शामिल थे।

लगना प्रदान की गई जानकारी और सामग्री के आधार पर, इस बात का कोई संकेत नहीं था कि वैपकोस रिपोर्ट में प्रस्तावित जल सेवन प्रणाली व्यवहार्य नहीं थी। इसलिए, अस्वीकरण खरीदारों को क्षतिपूर्ति करने के उनके दायित्व से मुक्त नहीं करता है लागत में वृद्धि के लिए अपीलकर्ता। यह प्रस्तुत किया जाता है कि डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. की रिपोर्ट में त्रुटि के कारण, अपीलार्थी को Rs.176 करोड़ के अतिरिक्त बोझ का सामना करना पड़ता है जिसने परियोजना के अर्थशास्त्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आर. एफ. क्यू. के पैरा 2.7.1 और पैरा 4 में निहित अस्वीकृतियों को पूर्ण प्रकृति का नहीं माना जाना चाहिए ताकि उन लागतों के भार को रोका जा सके जो अपीलार्थी द्वारा बोली-पूर्व चरण के दौरान जानकारी प्रदान करने में खरीददारों की ओर से चूक या त्रुटि के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में की जाती हैं। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने के विपरीत है कि अपीलकर्ता परियोजना खरीददार राज्यों में 42 मिलियन से अधिक उपभोक्ताओं को सस्ती और सस्ती बिजली की आपूर्ति करने में सक्षम है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अस्वीकरण [2023] 8 एस. सी. आर. के दायित्व के लिए एक पूर्ण बाधा के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खरीदार। इनपुट, सूचना कारकों आदि को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के किसी भी कर्तव्य के लिए केवल उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। गंभीर तकनीकी कमियां और बोलीदाताओं को प्रदान की गई वास्तविक लागत और अनुमानों के बीच भारी अंतर बोलीदाताओं को जानकारी प्रदान करने के मौलिक उद्देश्य को विफल कर देते हैं, विशेष रूप से जब इस मामले में खर्च की प्रकृति एक सरकारी कंपनी से एक रिपोर्ट खरीदने की थी जिसने एक विस्तृत अध्ययन किया था। अपीलार्थी के पास खरीददारों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसलिए, एल. डी. अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार करने के लिए बोली दस्तावेजों में निहित अस्वीकृति पर आयोग की निर्भरता नहीं है।

टिकाऊ "।

(16) विद्युत मंत्रालय में सचिव द्वारा जारी अधिसूचना में बदलाव लाने की शिकायत के संबंध में

, हम अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शिकायत पाते हैं:

" 9.20 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 2022 की अधिसूचना 21-सीमा शुल्क दिनांक 01.03.2002 के अनुसार, मेगा की स्थापना के लिए आवश्यक वस्तुओं पर सीमा शुल्क परियोजनाओं को शून्य के रूप में निर्धारित किया गया है जिसका अर्थ है कि एक बड़ी बिजली स्थापित करने के लिए आयातित वस्तुओं पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा

परियोजना। अधिसूचना 21.2022-सीमा शुल्क जो निम्नानुसार प्रदान करता है:

वस्तुओं का अध्याय या विवरण

मानक अतिरिक्त शर्त

शुल्क दर

न

हीं।

शीर्षक या

दर

उप-शीर्षक

(3)

(4)

(

6)

(2)

(5)

स्थापना के लिए आवश्यक वस्तुएँ

98.01

सूची 42 में विनिर्दिष्ट यदि ऐसा है

मेगा पावर है (ए) एक अंतर

राज्य ताप विद्युत संयंत्र

1000 मेगावाट या अधिक (बी) एक अंतर

सरकार के सचिव

विद्युत मंत्रालय में भारत।

9.22 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कैप्टिव कोयला ब्लॉक परियोजना का एक अभिन्न अंग होने के कारण खनन उपकरण को भी इस प्रावधान के तहत शामिल किया जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आर. एफ. पी. ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलार्थी के माध्यम से खरीदार (जो एक पूर्ण स्वामित्व वाला रियाणा पावर खरीद केंद्र V था।

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

उस समय पी. एफ. सी. की सहायक कंपनी) से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी
कहा कि वृहद विद्युत नीति के लाभ

विद्युत मंत्रालय ने

परियोजना का विस्तार निर्धारित वाणिज्यिक समय तक किया जाएगा
की तिथि। परिभाषा के अनुसार, परियोजना

पावर स्टेशन के संचालन

इसमें बंदी खदान शामिल है और इसलिए, यह खरीददार का दायित्व था कि

कोयला खनन उपकरणों को छूट प्रदान करना।

9.24 यह भी नोट किया जा सकता है कि:

XXX

XXX

XXX

9.35 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी ने एक अल्ट्रा-मेगा स्थापित किया है
परियोजना जिसमें कैप्टिव कोयला खदानें शामिल हैं। यह नहीं है।

बिजली

खनन गतिविधियों में अलग से शामिल होना। इसके अलावा, से कोयला

परियोजना का उपयोग केवल परियोजना के लिए किया जा रहा है। पूरी राजधानी

बिजली परियोजना की लागत में कोयला खदानों की लागत शामिल है। यह

पी. पी. ए. के अनुच्छेद 13 से भी स्पष्ट है जहाँ लागत में वृद्धि हुई है।

कोयला खदानों के लिए भूमि और अनुसंधान एवं विकास व्यय को इस प्रकार शामिल किया गया है -

कानून में परिवर्तन। इसलिए, यह निष्कर्ष कि कैप्टिव कोयला खदानें

एक अलग गतिविधि है और सीरियल नंबर 399 के तहत आने वाली है गलत है

और इसे अलग रखा जाना चाहिए।

ट्राइब्यूनल का अंत

(17) जहाँ तक खाते पर बढ़ी हुई लागत की शिकायत की बात है

जल ग्रहण प्रणाली में वृद्धि, निम्नलिखित का निष्कर्ष है

नल।

जल ग्रहण प्रणाली पर वैपकोस की प्रारंभिक रिपोर्ट,
एजेंसी को फिर से नियुक्त किया गया। यह.

उक्त रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए उसी

इस बात पर विवाद नहीं है कि सलाहकार, डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. ने इसकी पहले समीक्षा की थी

रिपोर्ट करें और इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि पानी का पहले का स्थान था और इसके परिणामस्वरूप अनुपलब्धता होगी।

सेवन उचित स्थान पर नहीं

कम अवधि के दौरान पौधे के लिए पानी। यह ध्यान देने योग्य है कि आधार पर, एस. पी. एल. ने जाने का फैसला किया

वैपकोस की सिफारिशों के

अनुशंसित और प्राप्त नए स्थान के चयन के लिए आगे

पूरे जल [2023] 8 एस. सी. आर. के आवश्यक डिजाइन और इंजीनियरिंग को पूरा किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अंतर्ग्रहण प्रणाली जिसके परिणामस्वरूप लंबी पाइप प्रणाली, मार्ग के साथ जलमग्न क्षेत्र में वृद्धि, अतिरिक्त निर्माण अवधि आदि हुई। इन कारकों के कारण, जल ग्रहण प्रणाली की लागत में Rs.176 करोड़ से अधिक की वृद्धि हुई। अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील ने बताया कि नाभा पावर मामले में इस न्यायाधिकरण का निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि नाभा को भूकंपीय क्षेत्र के आंकड़ों से संबंधित कोई लागत प्रदान नहीं की गई थी, जबकि तत्काल मामले में बोली लगाने वालों को लागत प्रदान की गई थी। अपीलार्थी ने आगे दोहराया है कि आर. एफ. पी. के पैरा 2.7.1 और पैरा 4 जिन पर प्रत्यर्थी खरीददारों द्वारा भरोसा किया गया था, वे ऐसा नहीं कर सकते।

इसे अप्रचलित प्रकृति का माना जाए ताकि खरीददारों को अत्यधिक गलत जानकारी प्रदान करने के लिए उनकी जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सके जिससे जल सेवन प्रणाली की लागत में पर्याप्त वृद्धि हो।

12.5 अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद और

केंद्रीय आयोग के निष्कर्षों में, हम पाते हैं कि बोली लगाने से पहले उचित परिश्रम करने और बोली दस्तावेजों में प्रदान की गई जानकारी की शुद्धता को सत्यापित करने की जिम्मेदारी बोलीदाताओं के पास है, साथ ही, प्रत्यर्थी खरीददार बोली पर घोर गलत रिपोर्ट प्रदान करने को उचित नहीं ठहरा सकते हैं।

जल सेवन प्रणाली बोली दस्तावेज में अस्वीकरण के तहत शरण ले रही है। वास्तव में, नियमित, विश्वसनीय और निर्बाध आधार पर इस परिमाण के ताप विद्युत केंद्र के लिए पानी की उपलब्धता आवश्यक है और संयंत्र के सफल संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है। यह देखा गया है कि बोली लगाने के समय बोलीदाताओं को आपूर्ति की गई वैपकोस की रिपोर्ट में पूरे वर्ष निर्बाध रूप से पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में कमी थी और यदि इसे निर्माण के लिए लिया गया होता और

कार्यान्वयन, इसके परिणामस्वरूप उत्तरदाता खरीददारों को बिजली की आपूर्ति से वंचित होने से भारी नुकसान हो सकता था

वर्ष की कुछ अवधि कम अवधि के दौरान पानी की कम/अनुपलब्धता के कारण। यह विवाद में नहीं है कि सासन यू. एम. पी. पी. देश में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी शुल्कों में से एक पर प्रत्यर्थी खरीदार को बिजली की आपूर्ति कर रहा है। प्रत्यर्थी खरीददारों की दलीलों से यह नोट किया जाता है कि इस तरह के मुद्दे से निपटा नहीं गया है

पी. पी. ए. में या अधिनियम की धारा 63 के तहत विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों में, हालांकि, ऐसी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, हमारा मानना है कि मामले को उपयुक्त निवारण के लिए नए सिरे से देखने की आवश्यकता है।

जबकि केंद्रीय रयान शक्ति खरीद केंद्र V. ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

आयोग ने सही निष्कर्ष निकाला है कि यह अनुच्छेद 13.1 के तहत कानून में परिवर्तन के रूप में योग्य नहीं है। 1 हालाँकि, पी. पी. ए. के बारे में, इसे कानून और समानता के तय किए गए सिद्धांतों के आधार पर भी संबोधित करने की आवश्यकता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्षों के आलोक में।

एनर्जी वॉचडॉग बनाम सी. ई. आर. सी. दिनांकित मामले में पैरा 19 में निर्णय

11.04.2017 . इस प्रकार, हमारा विचार है कि सलाहकारों की गलत रिपोर्ट से मूल रूप से उत्पन्न होने वाले पर्याप्त अतिरिक्त खर्च वाले इस मुद्दे की नए सिरे से जांच करने की आवश्यकता है।

केंद्रीय आयोग द्वारा। इसलिए, इस मुद्दे का जवाब पक्ष में दिया जाता है।

अपीलार्थी का "।

(18) ओ. एम. दिनांक 5.2011 कानून में परिवर्तन से संबंधित शिकायत के संबंध में, हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर ध्यान देते हैं:

" 14.5 हमने खनन उपकरणों पर सीमा शुल्क के लिए अतिरिक्त भुगतान के कारण मुआवजे के संबंध में अपीलार्थी के दावों से संबंधित इस मुद्दे पर केंद्रीय आयोग के विचार के साथ-साथ अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है। सावधानीपूर्वक विचार करने और इसके महत्वपूर्ण मूल्यांकन के बाद, विचार के लिए प्रमुख प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या यू. एम. पी. पी. को आवंटित कैप्टिव कोयला खदानों के लिए आवश्यक उपकरणों को बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए आवश्यक उपकरणों के बराबर माना जाना चाहिए, जहां तक सीमा शुल्क से छूट है। चिंतित हैं। अपीलार्थी का तर्क कि सासन यू. एम. पी. पी. को आवंटित कैप्टिव कोयला खदानें समग्र रूप से परियोजना का अभिन्न और आवश्यक हिस्सा हैं और इस तरह, सीमा शुल्क की छूट पूरी परियोजना के लिए आयात किए जा रहे सभी उपकरणों यानी कैप्टिव कोयला खदानों के साथ-साथ बिजली संयंत्रों पर लागू थी। यह विवाद में नहीं है कि कैप्टिव कोयला खदानों को यू. एम. पी. पी. के लिए बिजली उत्पादन के लिए विशेष उपयोग के लिए आवंटित किया गया था और किसी भी तरह से, कहीं और वाणिज्यिक उपयोग के लिए नहीं था।

14.6 इस संबंध में, हम मनोहर लाल शर्मा बनाम मामले में दिनांकित 24.08.2014 के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर भी ध्यान देते हैं। प्रधान सचिव। , डब्ल्यू. पी. में (सी. आर. एल.) 2012 का 120 (पैरा 158) कि कैप्टिव कोयला खदानों से कोयले का उपयोग अकेले यू. एम. पी. पी. के लिए किया जाना है और वाणिज्यिक दोहन के लिए कोयले के किसी भी मोड़ की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम दोहन के लिए स्वतंत्र कोयला खदानों के बीच चमकता अंतर देखते हैं

और वाणिज्यिक लाइनों पर कोयला बेचना और एक कैप्टिव कोयला खदान सेट [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल उत्तरदाता खरीदारों और बदले में उपभोक्ताओं के अंतिम लाभ के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए यू. एम. पी. पी. की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सस्ती दरों पर बिजली प्राप्त करने के लिए। वास्तविक स्थिति ने अपीलार्थी द्वारा की गई इस धारणा का संकेत दिया कि सीमा शुल्क छूट कैप्टिव खानों और बिजली संयंत्रों सहित पूरी परियोजना के लिए उपकरणों के आयात के लिए उपलब्ध होगी। हम अपीलार्थी के विद्वान वकील के तर्क में बल पाते हैं कि यू. एम. पी. पी. का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा होने के कारण, अकेले कोयला खनन परियोजनाओं के लिए लागू सीमा शुल्क दरें वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगी और छूट को प्रभावी बनाने की आवश्यकता होगी। हम, इस प्रकार यह मानते हैं कि केंद्रीय आयोग को यांत्रिक रूप से निर्देशित किया गया प्रतीत होता है

उक्त सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में प्रासंगिक प्रविष्टि (SI.No.399 और 400) का केवल विवरण और इस बात की सलाहना नहीं की गई है कि यू. एम. पी. पी. का अभिन्न अंग होने के नाते कैप्टिव कोयला खदानों को उपयोग की वाणिज्यिक लाइन वाली अकेले कोयला खदानों के बराबर नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार अपीलार्थी का यह मानना सही था कि कोयला खनन उपकरणों के लिए सीमा शुल्क में छूट उपलब्ध होगी। इस प्रकार, इस मुद्दे की कानून और आर. एफ. क्यू./आर. एफ. पी./पी. पी. ए. के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से जांच करने की आवश्यकता है। इसलिए हम इस मुद्दे का जवाब अपीलार्थी के पक्ष में देते हैं। ”

(19) उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर न्यायाधिकरण ने मामले को आयोग को वापस भेज दिया। हम अगली कड़ी को भी देख सकते हैं

विवादित निर्णय। रिमांड के अनुसार, आयोग ने

जल ग्रहण के संबंध में मामले पर पुनर्विचार किया। आयोग ने Rs.176 करोड़ की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। जहाँ तक इस आधार पर मुआवजे का दावा है कि कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है

विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव द्वारा एक

कानून में परिवर्तन, यह पाया गया कि विचाराधीन माल का आयात पहले प्रतिवादी द्वारा नहीं बल्कि उसकी मूल कंपनी द्वारा किया गया था। इसने, बदले में, न्यायाधिकरण के समक्ष फिर से अपीलार्थी के दो सेट शुरू कर दिए हैं और वे अभी भी लंबित हैं। निस्संदेह, उनका भाग्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इन मामलों में क्या निर्णय लेंगे।

(20) हमने श्री पी. चिदंबरम, श्री ध्रुव मेहता, श्री राणा मुखर्जी, श्री एम. जी. रामचंद्रन, श्री जी. उमापति के बारे में सुना है।

वरिष्ठ वकील, श्री निकुंज दयाल और सुश्री पल्लवी सहगल द्वारा सहायता प्राप्त। हमने श्री शुभम आर्य को भी सुना है, जो विद्वान वकील हैं। अपीलकर्ता की ओर से एक अपील में।

दूसरी ओर, हम हरियाणा पावर खरीद केंद्र वी। ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

श्री सज्जन पूवय्या, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री राहुल किनरा, विद्वान वकील और श्री अमित कपूर, विद्वान वकील द्वारा सहायता प्राप्त।

आवेदनों की प्रस्तुति

(21) अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री पी. चिदंबरम ने कहा कि न्यायाधिकरण ने स्पष्ट रूप से गलती से काम किया है

(22) उन्होंने कहा कि जहां तक जल ग्रहण प्रणाली के किसी अन्य स्थान पर स्थित होने के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निष्कर्ष का संबंध है, संबंधित, न्यायाधिकरण आयोग से सहमत था कि कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया था। एक बार, यह पाया गया कि कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ था, न्यायाधिकरण के पास वह करने की कोई शक्ति नहीं है जो उसने किया था। पी. पी. ए. का अर्थ है

पक्षों के बीच समझौता। पी. पी. ए. सावधानीपूर्वक विवरणों में जाता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बोली का अनुसरण करता है और दलों के दायित्वों को बहुत सावधानी के साथ तैयार किया गया है और व्यक्त किया गया है। एक बार पार्टी, अर्थात्, प्रथम प्रतिवादी आयोग के पास शिकायत करने गया कि कानून में परिवर्तन हुआ है और यह पाया गया कि कानून में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया। आई. एस. को समाप्त करने के बजाय, न्यायाधिकरण स्पष्ट रूप से इस आधार पर राहत देने में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर भटक गया है कि डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. की रिपोर्ट घोर रूप से गलत थी। मैं। इस संबंध में, उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में विभिन्न खंडों को सूचीबद्ध किया, जो डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. रिपोर्ट में परिलक्षित होने वाली किसी भी अशुद्धियों के कारण खरीदारों के साथ किसी भी दायित्व को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का निकाय है, केवल जानकारी प्रदान करने के माध्यम से थी। बोली लगाने वालों को अपनी बोली लगाने का फैसला करने से पहले रिपोर्ट प्रदान की गई थी। विभिन्न अस्वीकृति खंडों को ध्यान में रखते हुए, यह उनके मुंह में नहीं था कि बाद में रिपोर्ट के गलत होने के आधार पर एक मामले का निर्माण करने की कोशिश की जाए। इस संबंध में, यह बताया गया है कि खंड स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि बोली लगाने वाले को साइट का अध्ययन करके खुद को संतुष्ट करना था। किसी भी बात ने पहले उत्तरदाता को साइट का निरीक्षण करने और अपने लिए उस जानकारी का सत्यापन करने से नहीं रोका जो रिपोर्ट के माध्यम से प्रदान की गई थी

प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए भारी दावे के लिए, यह दिखाएगा कि दूसरी रिपोर्ट किसी भी तरह से पहली रिपोर्ट को गलत नहीं ठहराती है। यह विवाद में नहीं है, यह बताया गया है कि खरीददार किसी भी तरह से संबंधित नहीं थे [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दूसरी वैपकोस रिपोर्ट को पूरा करने के साथ। एकतरफा रूप से, पहला प्रत्यर्थी बिना किसी आधार के दूसरी रिपोर्ट कमीशन कराता है और यह केवल उक्त आधार पर है कि दावा किया गया था और जो अधिक है, न्यायाधिकरण द्वारा अनुमति दी गई थी। यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। जहां तक संयुक्त सचिव द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन द्वारा लाए गए कानून में बदलाव का आरोप लगाने वाले मुआवजे के दावे का संबंध है, सबसे पहले यह बताया जाता है कि पहले प्रतिवादी के लिए उचित बात यह होगी कि वह इस मामले को विभाग के साथ उठाए और धनवापसी का दावा करे और वह ऐसा करने के बजाय यह प्रस्तुत करेगा कि यह बोझ खरीदारों पर डाला जाना चाहिए और जो बदले में अंतिम उपभोक्ताओं पर अनिवार्य रूप से पारित किया जाएगा। (24) इसके अलावा, यह इंगित किया गया है कि न्यायाधिकरण ने वास्तव में पहले की अधिसूचनाओं को ध्यान में रखा है जो

कट ऑफ तिथि के समय प्रचलित थी जिसके संदर्भ में केवल कानून में परिवर्तन का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद, यह निष्कर्ष निकला है कि बंदी खदानों के उद्देश्य से विदेश से आयातित वस्तुओं के लिए छूट थी। इस तरह की जांच खुद नहीं की जा सकती थी। दूसरे शब्दों में, यह ऐसा मामला नहीं है जहां पहले प्रतिवादी के हाथ में निर्विवाद सामग्री थी जो स्पष्ट रूप से स्थापित करती थी कि कानून में परिवर्तन हुआ था। इसका कारण यह है कि यह स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि कटौती की तारीख से पहले, जो सामान विवाद का विषय हैं, उन्हें अधिसूचना के तहत छूट दी गई थी। दूसरी ओर, हमारा ध्यान अग्रिम सत्तारूढ़ प्राधिकरण के निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है जो इस मुद्दे पर गया है और पाया है कि विचाराधीन वस्तुओं को छूट नहीं दी गई थी। वास्तव में, यह अपीलार्थियों का तर्क है कि विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन केवल अग्रिम निर्णय का पालन करता है।

(25) इस संबंध में एक अन्य तर्क जो उठाया गया है, वह यह है कि विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव अंतिम सरकारी नहीं है

खंड 13.1 के अर्थ के भीतर प्राधिकरण। 1 . हम सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 के तहत जारी अधिसूचना से चिंतित हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्राधिकरण अनुच्छेद 13.1 के अर्थ के भीतर सक्षम है। 1 उक्त अनुच्छेद के अर्थ के भीतर एक अधिसूचना या एक व्याख्या भी जारी की है जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 13.1 के अर्थ के भीतर कानून में परिवर्तन हुआ है। 1 .

(26) हम श्री ध्रुव मेहता को भी सुन चुके हैं, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं। हमने अन्य वरिष्ठ वकीलों को सुना है जिन्होंने अनिवार्य रूप से श्री द्वारा संबोधित तर्कों को अपनाया गया।

हरियाणा पावर खरीद केंद्र V. ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

P.Chidambaram, विद्वान वरिष्ठ वकील, और वे यह तर्क देने में एक हैं कि न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा से बाहर भटक गया है और इसके परिणामस्वरूप एक आदेश आया है जो स्पष्ट रूप से अवैध और गलत है।

प्रथम उत्तरदाता की प्रस्तुतियाँ

विजली के उत्पादन और आपूर्ति में ठहराव। यह बिजली उत्पादन में निजी भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता को महसूस कर रहा है कि यह अधिनियम वर्ष 2003 में लागू किया गया था। विनियमों का विषय होने का मतलब है कि शुल्क समय-समय पर समीक्षा के लिए खुला था। यह ठीक यही व्यवस्था है जो अधिनियम की धारा 79 में परिलक्षित होती है। यह आगे है इंगित किया कि आयोग से सहमत होने के बावजूद जल ग्रहण प्रणाली के संबंध में न्यायाधिकरण के संबंध में अपीलकर्ताओं की शिकायत

कि कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया था और इसलिए, अस्थिर होने के कारण, न्यायालय विचार कर सकता है कि वास्तव में कानून में बदलाव किया गया था। इस तर्क को अनुच्छेद 13.1 के खंड (iii) के प्रावधानों के संदर्भ में पुष्ट करने का प्रयास किया गया है। 1 . दूसरे शब्दों में, यह तर्क दिया जाता है कि पी. पी. ए. के विभिन्न खंडों के अवलोकन से पता चलेगा कि खरीददार (अपीलार्थी) अनुबंध के तहत प्रारंभिक सहमति प्रदान करने के लिए बाध्य थे। परियोजना के लिए जल संपर्क से संबंधित प्रारंभिक सहमति में से एक। वह प्रस्तुत करेंगे कि पी. पी. ए. को अनुसूची II के प्रावधानों को देखते हुए प्रारंभिक सहमति में बिजली संयंत्र के लिए भूमि उपलब्ध कराने और पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी शामिल था। चूंकि यह निकला और जैसा कि दूसरी रिपोर्ट द्वारा समर्थित है

वैपकोस, पहली रिपोर्ट द्वारा समर्थित स्थल पर पानी की स्पष्ट रूप से अपर्याप्त उपलब्धता थी, पहले उत्तरदाता को विचाराधीन जलाशय के एक दूर के बिंदु से पानी लेने के लिए मजबूर किया गया था। इससे अन्य बातों के साथ-साथ पाइपलाइन बिछाने के खर्च में भारी वृद्धि हुई। इसलिए, यह कानून में एक बदलाव था।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(28) जहाँ तक अस्वीकरण खंडों पर आधारित विवाद का संबंध है, जिन पर अपीलार्थी भरोसा करता है, यह इंगित किया जाता है कि अस्वीकरण खंड की चौड़ाई को उस बिंदु तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जो अपीलार्थियों द्वारा प्रचार किया जाता है। हम एक ऐसे मामले पर विचार कर रहे हैं जहां एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई अर्थात्, वैपकोस ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अस्वाभाविक रूप से नहीं, पहले उत्तरदाता ने उसी पर भरोसा किया। इसे इसकी कीमत में शामिल किया जाता है और एक बार जब यह पाया जाता है कि रिपोर्ट पूरी तरह से गलत थी, तो अपीलकर्ताओं द्वारा अस्वीकरण खंडों के तहत कोई आश्रय नहीं लिया जा सकता है। विभिन्न निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया। इनमें एनर्जी वॉचडॉग बनाम शामिल हैं। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य (2017) 14 एस. सी. सी. 80, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और अन्य। वी. अदानी पावर लिमिटेड और अन्य। (2019) 5 एस. सी. सी. 325, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। एस्सार पावर (2008) 4 एस. सी. सी. 755, स्कंदिया बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम। कोकिलाबेन चंद्रवन और अन्य। (1987) 2 एस. सी. सी. 654, डी. एल. एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड बनाम निदेशक, नगर और ग्राम योजना विभाग, हरियाणा (2010) 14 एस. सी. सी. 1 और सुमितोमो भारी उद्योग बनाम। भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (2010) 11 एस. सी. सी. 296, नाभा पावर लिमिटेड बनाम। पी. एस. पी. सी. एल. (2018) 11 एस. सी. सी. 508

(29) प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया है जो अनिवार्य रूप से इस प्रस्ताव के लिए विस्तृत हैं कि

आदेश एक्स. एल. आई. नियम 22 और नियम 33 के तहत शक्ति है: प्रहलाद और ओआरएस। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्न. (2010) 10 एस. सी. सी. 458, पंजाब राज्य और अन्य। वी. बख्शीश सिंह (1998) 8 एस. सी. सी. 222, महंत धनगीर और अन्न। वी. मदन मोहन और अन्य। (1987) (सप) एस. सी. सी. 528।

(30) विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन पोवय्या द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वास्तव में धारा के प्रावधानों के तहत किसी भी तरह से शक्ति है।

79 (1) (ख) अनुबंध के तहत विचार की गई विशिष्ट राहत के लिए भी शुल्क निर्धारण पर पुनर्विचार करने के लिए अधिनियम। इस संबंध में, इस तथ्य पर जोर दिया जाता है कि दिशानिर्देशों के खंड 4.7 और 5.1.17 में संशोधन किया गया और यह संशोधित दिशानिर्देश हैं जो मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं। यह संशोधित दिशानिर्देश हैं जो लागू किए गए थे, इस तथ्य से समझा जा सकता है कि संशोधित दिशानिर्देश पी. पी. ए. में परिलक्षित होते हैं। संशोधित प्रावधान 17.3 में पाए जाते हैं। 1 और

13.1. 1

(31) संशोधित दिशानिर्देश 4.7 13.1 में परिलक्षित होता है। 1 जबकि संशोधित दिशानिर्देश 5,17 अनुच्छेद 17.3 में परिलक्षित होता है। 1 . (32) 17. 3 के संबंध में। 1 , यह इंगित किया गया है कि उसी को पढ़ने से, विशेष रूप से, प्रावधान के शुरुआती अंग से पता चलेगा कि हरियाणा शक्ति खरीद केंद्र V.

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

शुल्क बढ़ाने वाले निर्धारक को बदलने के उद्देश्य से स्पष्ट रूप से सामान्य शक्ति है। इसकी तुलना उन विशिष्ट उदाहरणों से की जानी चाहिए जो आयोग के अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित करेंगे जिनमें शामिल हैं -

अनुच्छेद 13.1 कानून में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, तर्क यह है कि कानून में परिवर्तन होने पर, यह आयोग और न्यायाधिकरण और इस न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है कि वह न्यायाधिकरण और आयोग को न्याय के हित में पर्याप्त शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखे, ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए जो निजी खिलाड़ी के साथ-साथ दीर्घकालिक अनुबंध में भी निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार की मांग करती हैं।

अधिनियम की धारा 61 पर हमारा ध्यान। उन्होंने कहा कि धारा 63 से 79 (बी) के साथ पठित धारा 61 एक वैधानिक ढांचा प्रदान करती है जो आयोग को शामिल सेवाओं की प्रकृति और अधिनियम के तहत विकसित बदली हुई प्रणाली को ध्यान में रखते हुए पीपीए शासित परिदृश्य में भी एक न्यायसंगत शुल्क तैयार करने में सक्षम बनाती है। (34) विद्वान वकील श्री अमित कपूर ने विरोध के सिद्धांत पर जोर दिया। वह श्री सज्जन पूव्या के साथ इशारा करते थे,

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, कि न्यायालय को इस तथ्य से अनजान नहीं होना चाहिए कि यह मामला आर. एफ. पी. के तहत एक मामले 2 परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब यह है कि उस स्थिति के विपरीत जहां ठेकेदार साइट और अन्य सुविधाओं को चुनने के लिए स्वतंत्र है, एक मामले में 2 स्थिति जो इस मामले में प्रचलित स्थिति है, सब कुछ नियोक्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है। , एसपीवी। उक्त बिंदु को दोहराते हुए, यह बताया गया है कि बोली लगाने वालों का जल स्रोत पर नियंत्रण नहीं था जिससे पानी लेना पड़ता था। दूसरे शब्दों में, पानी किसी अन्य जल निकाय से नहीं लिया जा सकता था। यह पहलू उस स्थिति के आधार पर शुल्क तय करने के मामले में आयोग के साथ स्वतंत्र रूप से विचार करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है जो दो आधारों द्वारा उदाहरण के रूप में बनाई गई थी और जो अपीलों की विषय वस्तु हैं। एक अन्य मुद्दा जो प्रस्तावित किया गया है वह यह है कि भूवैज्ञानिक मामलों के संबंध में, बोली लगाने वालों को चेतावनी दी गई थी कि उन्हें स्वयं मूल्यांकन करना होगा। लेकिन इस तरह की चेतावनी विशेष रूप से जलविज्ञान के संबंध में दर्ज नहीं की गई थी।

शर्ते। चूंकि जल ग्रहण प्रणाली जल विज्ञान से संबंधित है, इसलिए यह खुला नहीं है

अपीलार्थियों को इस तथ्य की खोज के आधार पर शुल्क के न्यायसंगत निर्धारण को रोकने के लिए कि पहली डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. रिपोर्ट अत्यधिक त्रुटिपूर्ण थी। हमें याद दिलाया जाता है कि पहले उत्तरदाता के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण था कि वह वार्षिक आधार पर बिजली संयंत्र चलाता था। डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. की दूसरी रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करेगी कि यदि अपीलार्थी को पानी [2023] 8 एस. सी. आर. लेना था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पहली डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. रिपोर्ट के संदर्भ में, कमजोर महीनों के दौरान, पहले उत्तरदाता को संयंत्र के संचालन के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं मिलेगी। यदि ऐसी घटना हुई होती, तो परिणाम यह होता कि खरीदार अंत में क्षमता शुल्क के लिए शुल्क का भुगतान करते, भले ही उसे बिजली नहीं मिलती। अपीलार्थी बाहर से बिजली खरीदने के लिए मजबूर होंगे और अंत में अंतिम उपभोक्ता को नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह इन सब से बचने के लिए है कि पहले प्रतिवादी ने इस तरह से काम किया है जो न केवल उसके सर्वोत्तम हित के अनुरूप था, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहा था कि खरीदार और अंत में उपभोक्ता सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित थे। विद्वान वकील द्वारा आगे यह इंगित किया गया है कि न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि विचाराधीन अनुबंध न केवल ठेकेदार को बल्कि नियोक्ता को भी लाभ देने की अनुमति देता है।, याचिकाकर्ताओं। दूसरे शब्दों में, यदि यह एक ऐसा मामला था जिसमें पहले प्रतिवादी को नियामक तंत्र के तहत अन्यायपूर्ण संवर्धन करते हुए पाया जाता, तो अपीलार्थी दरों को कम करने के लिए आयोग का रुख कर सकते थे। इसलिए, नियामक तंत्र दोनों दिशाओं में काम करने के लिए है और न्यायालय को एक विनियमित अनुबंध की अनूठी प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए।

(35) श्री अमित कपूर ने अधूरे अनुबंधों के सिद्धांत का भी उल्लेख किया। इसे इस अर्थ के रूप में समझाया गया है कि एक दीर्घकालिक संपर्क होने के नाते, पक्ष सभी संभावित विकास की उम्मीद नहीं कर सकते हैं और जो कारक हैं हो सकता है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आयोग को अधिनियम की धारा 61 के तहत व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ठेकेदार और नियोक्ता तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान की जाए।

(36) यह पूछे जाने पर कि पी. पी. ए. और आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर कानून की स्थिति क्या होगी और यदि -

श्री अमित कपूर ने भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 18 और 19 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। वह बताएगा कि एक निर्दोष भी

धारा 18 के अर्थ के भीतर प्रतिनिधित्व के परिणामस्वरूप धारा 19 के तहत संपर्क अमान्य हो सकता है। धारा 19 में विचार किया गया है कि जिस पक्ष की सहमति धारा 18 के अर्थ के भीतर गलत निरूपण द्वारा प्राप्त की जाती है, वह दूसरे पक्ष पर संपर्क करने के लिए जोर दे सकता है। लेकिन गलत पक्ष ने इस बात पर जोर देने का अधिकार बरकरार रखा कि उसे उसी स्थिति में रखा जाएगा जिस पर वह कब्जा कर लेता अगर कोई गलत प्रस्तुति नहीं होती। इसलिए, यह इंगित किया जाता है कि अनुबंध के कानून में भी यह तर्क देने का आधार है कि धारा 79 (बी) के तहत अपनी शक्तियों से लैस आयोग ठेकेदार को उस स्थिति में क्षतिपूर्ति कर सकता है जिससे हम चिंतित हैं।

हरियाणा पावर खरीद केंद्र V. ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

(37) इस न्यायालय के निर्णय ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम में रिपोर्ट किया। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

और अन्य (2009) 6 एस. सी. सी. 235 तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा के साथ न्यायालय की ओर से बोलने के लिए विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के तहत कार्य करने के लिए बनाए गए विनियमों के प्रभाव पर विचार करने का अवसर मिला। उक्त निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विनियम 92 के तहत शक्ति है,

विशेष रूप से, शुल्क को संशोधित करने के लिए (पैरा 35 को 38 और 40 के साथ पढ़ें)

(38) इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, जब हमने सहायता मांगी

विद्वान सलाहकार। हमने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ सुनीं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम. जी. रामचंद्रन इंगित करेंगे कि धारा 92 के तहत शक्ति से संबंधित टिप्पणियों को अधिनियम की धारा 62 के साथ पठित धारा 61 के तहत प्राप्त स्थिति तक ही सीमित समझा जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 63 के तहत शुल्क निर्धारित होने पर उक्त शक्ति उपलब्ध नहीं हो सकती है। जब हमसे पूछा गया कि क्या धारा 61 के प्रावधान धारा 63 से पूरी तरह से असंबद्ध हैं, तो विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एम. जी. रामचंद्रन ने कहा कि धारा 61 पूरी तरह से लागू नहीं हो सकती है। वह प्रस्तुत करेगा कि विशेष

प्रतिस्पर्धी बोली लगाने और धारा 63 के तहत शुल्क के अनुमोदन के बाद पी. पी. ए. के तहत एक दीर्घकालिक अनुबंध से बाध्य हो जाते हैं। एक मामले में जहां धारा 62 के अर्थ के भीतर शुल्क का निर्धारण होता है, दूसरी ओर, 1999 के विनियम लागू हो सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि विनियमन 92 के तहत शक्ति जो शुल्क की समीक्षा के लिए प्रदान करती है और जिसे समग्र रूप से शुल्क के संशोधन की शक्ति के रूप में समझा गया है, वह इस बात के अधीन होनी चाहिए कि शुल्क का संशोधन केवल वर्ष 2001 में लाए गए शुल्क नियमों के अनुसार सख्ती से किया जा सकता है और जैसा कि बाद में समय-समय पर संशोधित किया गया था। वास्तव में, वह 2014 के विनियमों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे जो स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 63 के तहत किए गए शुल्क निर्धारण को उक्त विनियमन के दायरे से बाहर रखा गया है। इस संबंध में, दूसरी ओर, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सज्जन पोवैया ने इस न्यायालय गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। तारिणी इन्फ्रास्ट्रक्चर [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एड और अन्य (2016) 8 एससीसी 743 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1615 2023 ऑनलाइन एससी 233। वह इन निर्णयों के बल पर इशारा करेंगे।

हैट द्वारा कवर किए गए मामले में भी नियामक शक्ति उपलब्ध है

अधिनियम के 63 पर।

विक्षेपण (40) हम, इन मामलों में, केवल दो मुद्दों से संबंधित हैं। के रूप में

ए. वी. ने देखा है, पहले प्रतिवादी ने पहले एक याचिका दायर की

धारा 79 (बी) के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करना। मामला स्पष्ट रूप से निर्माण अवधि का है। यह इस बिंदु पर पी. पी. ए. के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के लिए उपयुक्त है।

(41) अनुच्छेद 13 कानून में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 13.1। 1 . परिभाषित करता है

कानून में बदलाव है। वह इस प्रकार है:

" अनुच्छेद 13: कानून में बदलाव

13.1 परिभाषाएँ

इस अनुच्छेद 13 में निम्नलिखित शर्तें होंगी:

अर्थ:

13.1. 1 " कानून में परिवर्तन का अर्थ है उस तारीख के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से किसी की घटना, जो बोली की समय सीमा से सात (7) दिन पहले है:

((i) किसी विधि का अधिनियमन, प्रभाव में लाना, अपनाना, उद्घोषणा, संशोधन, संशोधन या निरसन या (ii) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी विधि की व्याख्या में परिवर्तन,

न्यायाधिकरण या भारतीय सरकारी साधन इस प्रकार प्रदान किए गए हैं न्यायालय, न्यायाधिकरण या भारतीय सरकारी साधन है

ऐसी व्याख्या के कानून के तहत अंतिम प्राधिकरण या (iii) परियोजना के लिए उपलब्ध या प्राप्त किसी भी सहमति, अनुमोदन या लाइसेंस में परिवर्तन, विक्रेता के चूक के अलावा, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री के व्यवसाय की किसी भी लागत या राजस्व में कोई बदलाव होता है। विक्रेता द्वारा इस शर्तों के तहत खरीदारों को बिजली

समझौता, या (iv) (क) भूमि के घोषित मूल्य में कोई परिवर्तन परियोजना के लिए या (बी) उल्लिखित परियोजना के लिए भूमि के पुनर्वास और पुनर्वास पैकेज के कार्यान्वयन की लागत

आर. एफ. पी. में या (ग) आर. एफ. पी. में उल्लिखित विद्युत केंद्र के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना को लागू करने की लागत या (घ) लागत

कोयला खदान के लिए प्रतिपूरक वनीकरण को लागू करना, आर. एफ. पी. और पी. पी. ए. के तहत इंगित किया गया है; लेकिन इसमें (i) कोई भी रयान पावर खरीद केंद्र V शामिल नहीं होगा।

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

विक्रेता के शेयरधारकों को वितरित आय या लाभांश पर किसी भी रोक कर में परिवर्तन, या (ii) यू. आई. के संबंध में परिवर्तन। एक उपयुक्त आयोग द्वारा प्रभार या आवृत्ति अंतराल।

बशर्ते कि यदि भारत सरकार धारा के तहत बिजली उत्पादन परियोजनाओं के लिए आयकर अवकाश नहीं बढ़ाती है

80 आयकर अधिनियम का आई. ए., अनुसूचित वाणिज्यिक तक पावर स्टेशन के संचालन की तारीख, इस तरह के गैर-विस्तार को कानून में परिवर्तन माना जाएगा।

(42) अनुच्छेद 13.1। 2 यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण या भारत में इसी तरह के न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकाय में, जिसके पास परियोजना से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने की क्षमता है, उस पर विचार किया जाएगा।

अक्षम न्यायालय।

(43) अनुच्छेद 13.2 कानून में परिवर्तन के प्रभाव की गणना के लिए वास्तविक अनुप्रयोग और उपबंध प्रदान करता है। वह इस प्रकार है:

" 13.2 परिवर्तन के प्रभाव की गणना के लिए अनुप्रयोग और सिद्धांत

कानून में। इस अनुच्छेद 13 के तहत कानून में परिवर्तन के परिणाम का निर्धारण करते समय, पार्टियों को इस सिद्धांत का उचित सम्मान करना होगा।

कानून में परिवर्तन, मासिक शुल्क भुगतान के माध्यम से, इस अनुच्छेद 13 में विचार की गई सीमा तक, प्रभावित पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में बहाल करने के लिए है जैसे कि कानून में इस तरह के परिवर्तन ने नहीं किया है। हुआ।

क) निर्माण अवधि

कानून में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप, शुल्क में परियोजना की पूंजी लागत में वृद्धि/कमी का प्रभाव नीचे दिए गए सूत्र द्वारा नियंत्रित किया जाएगा: इस समझौते की अवधि में पूंजी लागत में प्रत्येक पचास करोड़ रुपये (Rs.50 करोड़) की संचयी वृद्धि/कमी के लिए, गैर-वृद्धि योग्य क्षमता शुल्क में वृद्धि/कमी शून्य बिंदु दो छह सात के बराबर होगी।

(0.267 %) गैर-एस्केलेबल क्षमता शुल्क।

बशर्ते कि विक्रेता खरीददार को कानून में ऐसे परिवर्तन के प्रभाव को स्थापित करने के लिए पूंजी लागत में ऐसी वृद्धि/कमी का दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करता है। विवाद के मामले में, अनुच्छेद

17 लागू होगा।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(50) करोड़।

ख) संचालन अवधि

कानून में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, किसी के लिए मुआवजा

विक्रेता के लिए राजस्व या लागत में वृद्धि/कमी निर्धारित की जाएगी और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की गई तारीख से प्रभावी होगी, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी, अपील के अधिकारों के अधीन

लागू कानून के तहत प्रदान किया गया।

बशर्ते कि उपर्युक्त मुआवजा होगा

केवल तभी देय होगा जब विक्रेता को राजस्व या लागत में वृद्धि/कमी के लिए 1 प्रतिशत के बराबर राशि से अधिक हो।

एक संपर्क वर्ष के लिए कुल मिलाकर ऋण पत्र।

(44) अनुच्छेद 13.4। 2 भुगतान करने का तरीका बताएँ

कानून में फांसी लागू की जानी है। वह इस प्रकार है:

" 13.4. 2 कानून में परिवर्तन के लिए भुगतान इसके माध्यम से किया जाएगा।

अनुच्छेद 11.8 में उल्लिखित पूरक विधेयक। हालांकि, इस समझौते के अनुसार निर्धारित कानून में बदलाव के कारण शुल्क में किसी भी बदलाव के मामले में, शुल्क में इस तरह के बदलाव के बाद विक्रेता द्वारा उठाया जाने वाला मासिक चालान उचित होगा। बदले हुए शुल्क को प्रतिबिंबित करें।

(45) हम उन अन्य मूलभूत लेखों को देख सकते हैं जिन पर प्रथम प्रतिवादी ने भरोसा किया था। अनुच्छेद 17 शासी कानून और विवाद निवारण से संबंधित है। अनुच्छेद 17.2। 1 इस प्रकार पढ़ता है:

" 17.2. 1 किसी भी पक्ष को कोई भी दावा, विवाद उठाने का अधिकार है या इस समझौते के तहत, बाहर या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का अंतर, जिसमें दूसरे को लिखित सूचना देकर इसका अस्तित्व या वैधता या समाप्ति (सामूहिक रूप से "विवाद") शामिल है।

पार्टी, जिसमें शामिल होंगे: ((i) विवाद का विवरण;

((ख) ऐसे विवाद के लिए आधार; और

((ग) उसके दावे के समर्थन में सभी लिखित सामग्री। हरियाणा पावर खरीद केंद्र V.

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

(46) आगे के लेख जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है

कि दावे को जवाबी दावे और एक प्रयास के साथ भी पूरा किया जा सकता है

विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया जाना चाहिए (अनुच्छेद 17.2.3 देखें)। किसी समझौते पर पहुंचने में विफलता अनुच्छेद 17.3 के द्वार खोलती है। यह उचित है क्योंकि शीर्षक 'विवाद समाधान' है।

(47) अनुच्छेद 17.3। 1 यह महत्वपूर्ण लेख है। इसमें लिखा है: -

" जहां किसी पक्ष द्वारा शुल्क में किसी परिवर्तन या निर्धारण या शुल्क से संबंधित किसी मामले या किसी पक्ष द्वारा किए गए दावों के लिए किए गए दावे से कोई विवाद उत्पन्न होता है, जो आंशिक या पूर्ण रूप से

शुल्क में किसी भी परिवर्तन या ऐसे किसी भी दावे के निर्धारण के परिणामस्वरूप शुल्क में परिवर्तन हो सकता है या (ii) अनुच्छेद 4.7 के तहत उपयुक्त आयोग को भेजे जाने के लिए सहमत किसी भी मामले से संबंधित हो सकता है। 1 , 13.2 , 18.1 या खंड 10.1। 3 इसके अनुसूची 17 के अनुसार, इस तरह के विवाद को उपयुक्त आयोग द्वारा निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। उपयुक्त आयोग के निर्णयों के खिलाफ अपील केवल आयोग के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

समय-समय पर संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003।

विक्रेता के प्रति इस समझौते के तहत खरीदारों के दायित्व किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे।

खरीददारों के बीच विवाद।

(48) इसके बाद जैसा कि हमने देखा है, अनुच्छेद 17.3। 2 दिखाई देता है

जिनका हम उल्लेख नहीं कर रहे हैं, वे उन विवादों के निपटारे से संबंधित हैं जो अनुच्छेद 17.3 के दायरे से बाहर हैं। 1 .

(49) हम शुरुआत में ही दिशानिर्देश में लाए गए बदलाव को देख सकते हैं। यह सच है कि जैसा कि हमने देखा है कि पहले

19.01.2005 पर तैयार किए गए दिशानिर्देशों में कानून में परिवर्तन और विवाद समाधान दोनों के संबंध में एक अलग व्यवस्था पर विचार किया गया था। हालाँकि सवाल यह होगा कि पहला उत्तरदाता इससे किस हद तक लाभ प्राप्त कर सकता है। जहाँ तक अनुच्छेद 13.1 का संबंध है। 1 संबंधित है, खंड 1 और 2 स्पष्ट रूप से जल ग्रहण प्रणाली में लाए गए परिवर्तन के आधार पर दावे के संबंध में अप्रयोज्य हैं।

(50) यह खंड (iii) है जिसका उल्लेख श्री सज्जन पोवय्या ने किया है और उस पर भरोसा किया गया है। वह इस प्रकार है:

" (ग) उपलब्ध किसी भी सहमति, अनुमोदन या लाइसेंस में परिवर्तन या परियोजना के लिए प्राप्त किया गया, विक्रेता के चूक के अलावा, जिसके परिणामस्वरूप [2023] 8 एस. सी. आर. से किसी भी लागत या राजस्व में कोई बदलाव होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विक्रेता द्वारा खरीदारों को बिजली बेचने का व्यवसाय

इस समझौते की शर्तें "।

(51) यह पहले प्रत्यर्थी का मामला है कि चूंकि अनुसूची में प्रारंभिक सहमति थी, जो वास्तव में, एक प्रारंभिक सहमति मानी जाती थी जिसमें

बिजली संयंत्र और पाइपलाइन के लिए भूमि उपलब्ध कराने के कार्य को पूरा करने के लिए और वैपकोस की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार जो हुआ उसे देखते हुए इसमें बदलाव किया गया है, पहला

प्रतिवादी राहत का हकदार था। उक्त तर्क के संबंध में, हमें निम्नलिखित बाधाओं पर ध्यान देना चाहिए जो निर्विवाद हैं। हम देखते हैं कि जिन अभिवचनों को हमने आयोग के समक्ष रखा है और जो अधिक है, न्यायाधिकरण के समक्ष भी, वे यह प्रकट नहीं करते हैं कि प्रथम प्रतिवादी ने ऐसा रुख अपनाया है। अनुसूची 2 का कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं मिला है जिसमें कथित प्रारंभिक सहमति को कानून में परिवर्तन के आधार पर दावे के लिए एक आधार के रूप में बाद की सहमति द्वारा ओवरराइड किया जा रहा है।

(52) दूसरी बाधा जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि हम धारा 125 के तहत एक अपील पर विचार कर रहे हैं जो कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के अस्तित्व पर आधारित है। इस संबंध में, निर्विवाद रूप से आयोग और न्यायाधिकरण दोनों ने समवर्ती निष्कर्ष निकाला है कि प्रथम प्रतिवादी कानून में कोई बदलाव स्थापित करने में विफल रहा है। इस प्रकार, पहला प्रतिवादी समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ है जिन्हें हम हल्के में नहीं ले सकते हैं।

(53) तीसरा, हम देख सकते हैं कि प्रथम प्रतिवादी ने न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निष्कर्ष को स्वतंत्र रूप से चुनौती नहीं दी है।

कि कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमने देखा है कि न्यायाधिकरण ने पहले प्रतिवादी को राहत देने और मामले को पूरी तरह से अलग आधार पर रिमांड करने के लिए आगे बढ़ा है। यहाँ, हम कोई संदेह नहीं देख सकते हैं कि इसे पारित किए गए विवादित आदेश में निष्कर्षों में त्रुटियों को सुधारने के लिए अपीलीय न्यायालय की शक्ति का एक हिस्सा मानते हुए आदेश XLI नियम 22 के सिद्धांत द्वारा उचित मामलों में विस्तार किया जा सकता है। हालाँकि, अपीलकर्ताओं द्वारा अधिनियम की धारा 125 के तहत अपील जैसी स्थिति में शासन करने के लिए आदेश XLI नियम 22 सी. पी. सी. में सिद्धांत की अनुमति देने पर आपत्ति जताई गई है। हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि प्रतिवादी को कोई अपील या प्रति याचिका दायर किए बिना भी प्रतिवादी के खिलाफ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निष्कर्ष पर आक्षेप करने की अनुमति देने की शक्ति है।

(54) गुण-दोष के आधार पर दावे की जांच करने पर हम पाते हैं कि पहला प्रतिवादी विफल हो जाएगा। याचिका के पैरा 68 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हरियाणा शक्ति खरीद केंद्र V.

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

लागत में वृद्धि सीधे बोली लगाने से पहले के चरण में बोलीदाताओं को प्रदान की गई वैपकोस रिपोर्ट में त्रुटि के कारण होती है। यह तर्क दिया जाता है कि प्रथम प्रत्यर्थी को उसी के लिए क्षतिपूर्ति की आवश्यकता होती है।

(55) पैरा 108 में, यह कहा गया है कि आर. एफ. पी. के अनुसार, खरीदारों को जल सेवन अध्ययन रिपोर्ट प्रदान करनी थी। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, लागत

जल ग्रहण प्रणाली लगभग Rs.92 करोड़ थी। पैरा 110 में आगे कहा गया है कि जल ग्रहण प्रणाली के कारण जल की लागत में काफी वृद्धि हुई थी। यह कहा गया है कि यह रिपोर्ट में त्रुटियों के कारण है। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पैरा 111 में कहा गया है कि चूंकि पानी की पाइपलाइन बिजली स्टेशन की भूमि और पानी के सेवन का हिस्सा है पाइपलाइन बिजली स्टेशन का एक अभिन्न अंग है, पानी के सेवन प्रणाली की सांकेतिक लागत कानून में बदलाव द्वारा कवर की जाएगी। अपील में भी, हमने रुख को विस्तार से देखा है।

(56) प्रारंभिक सहमति को पी. पी. ए. में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है अनुसूची 2 में सूचीबद्ध सहमति। पी. पी. ए. का अनुच्छेद 5.5 इस प्रकार है:

" 5.5 सहमति।

विक्रेता सभी सहमति (अन्य) प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा।

इंटरकनेक्शन और संचरण के लिए आवश्यक लोगों की तुलना में

विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं और प्रारंभिक सहमति),

परियोजना का वित्तपोषण, निर्माण, संचालन और रखरखाव और सामान्य रूप से इस समझौते और विशेष रूप से इस अनुच्छेद 5 के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए ऐसी सभी सहमतिओं को बनाए रखना/नवीनीकृत करना और प्रमुख खरीददार को प्रत्येक आवेदन की प्रतियां जो वह प्रस्तुत करता है, और प्रत्येक सहमति/अनुमोदन/लाइसेंस की प्रतियां जो वह प्राप्त करता है, तुरंत प्रदान करेगा। संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि विक्रेता प्रारंभिक सहमति को बनाए रखने/नवीनीकरण करने और उसमें निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

(57) यह सच है कि खरीदारों को कुछ प्रारंभिक सुरक्षित करना था

सहमति जबकि सहमति का विशाल बहुमत विक्रेता द्वारा खरीदा जाना था। जाहिरा तौर पर खरीदारों द्वारा जो कुछ भी खरीदा जाना था प्रारंभिक सहमति के रूप में वर्णित किया गया है। यह भी विवाद में नहीं है कि यद्यपि सहमति शब्द का उपयोग अनुच्छेद 13.1 में किया गया है। 1 , प्रारंभिक सहमति भी सहमति के रूप में योग्य होगी। अपीलार्थियों का तर्क है कि जहां तक प्रारंभिक सहमति पर विचार किया गया है जिसे खरीदारों द्वारा किया जाना था

यह जल संपर्क प्रदान करने के लिए था। जल संपर्क में पानी का स्रोत उपलब्ध कराना शामिल था जिसमें गोविंद [2023] 8 एस. सी. आर. शामिल था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वल्लभ पंत सागर (रिहंद जलाशय)। कोई बदलाव नहीं किया गया है

उक्त सहमति। यह पहले उत्तरदाता का मामला नहीं है, दूसरे शब्दों में, कि पहले उत्तरदाता को किसी अन्य जल स्रोत से पानी लेने के लिए मजबूर किया गया है। इस संबंध में दिनांक 23.10.2006 के संचार द्वारा, हम निम्नलिखित पाते हैं:

- (i) यह पहले ही 12 अक्टूबर, 2006 को प्रदान किया जा चुका है।
- (ii) भू-तकनीकी अध्ययन, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, क्षेत्र जल निकासी अध्ययन, सामाजिक-आर्थिक अध्ययन और ई. आई. ए. (त्वरित) सहित जल ग्रहण अध्ययन रिपोर्ट और परियोजना रिपोर्ट 3 तारीख को प्रदान की गई थी।

अगस्त, 2006 "।

(58) जबकि इस दस्तावेज़ पर, हम आर. एफ. पी. में विचार की गई भूमि की घोषित कीमत के संबंध में निम्नलिखित पर भी ध्यान दे सकते हैं।

खंड 1.4 (ii):

" 2. संदर्भ खंड: आर. एफ. पी. 1.4 (ii)-के घोषित मूल्य के संबंध में

पावर स्टेशन के लिए भूमि

(i) विद्युत संयंत्र क्षेत्र-Rs.110 करोड़

(ii) एमजीआर भूमि-Rs.80 करोड़।

(iii) जल पाइपलाइन गलियारा-रु। 0. 63 करोड़

(iv) ऐश पाइपलाइन कॉरिडोर-रु। 0.047 करोड़ "

(59) इस पहलू पर कोई विवाद नहीं है। इस संबंध में, हम देखते हैं कि पी. पी. ए. की अनुसूची 1 ए के तहत यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है

परियोजना में वह जल स्रोत गोविंद वल्लभ पंत सागर (रिहंद जलाशय) है। (60) इसके बाद, हमें ध्यान देना चाहिए कि अनुसूची 2 में शीर्षक प्रारंभिक सहमति के तहत, खरीदारों की ओर से, एस. पी. वी. की अपेक्षा की गई थी।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करना, बिजली के लिए आवश्यक रूप से पर्यावरण और वन मंजूरी प्राप्त करना।

स्टेशन, कैप्टिव कोयला खदानों का आवंटन करें और अंत में, उचित परियोजना आवश्यकताओं के लिए जल संपर्क प्रदान करें। उचित परियोजना आवश्यकताओं के लिए यह जल संपर्क है जिसे हरियाणा बिजली खरीद केंद्र V को पूरा करने पर विचार किया गया था।

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

जल स्रोत गोविंद वल्लभ पंत सागर (रिहंद जलाशय) से। 23.10.2006 दिनांकित संचार से संकेत मिलता है कि केंद्रीय जल आयोग ने विचाराधीन जल निकाय से पानी की आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। उक्त अर्थ में, खरीदारों ने आर. एफ. पी. में विचार किए गए अपने दायित्व को पूरा किया था।

(61) आर. एफ. पी. जो पी. पी. ए. से पहले था, कुछ शर्तों के लिए प्रदान किया गया था जो हम पहले ही संकेत दे चुके हैं। खंड 1.4 अन्य बातों के साथ-साथ

इसमें बोली की समय सीमा से कम से कम 30 दिन पहले केंद्रीय जल आयोग की अपेक्षित मंजूरी के साथ परियोजना के लिए जल संपर्क प्रदान करने का वचन शामिल है। पी. पी. ए. में, यह संकेत दिया गया है कि खरीददारों ने परियोजना रिपोर्ट में निहित प्रारंभिक अध्ययन पूरा कर लिया है और परियोजना के लिए आवश्यक प्रारंभिक सहमति प्राप्त कर ली है जो अनुसूची 2 के भाग I में निर्धारित की गई है और विक्रेता को दो मामलों को छोड़कर पी. पी. ए. की तारीख पर उपलब्ध कराई गई है: (1) वन मंजूरी और भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा। पी. पी. ए. की भाग I अनुसूची 2 में कहा गया है कि भूमि की धारा 6 के तहत अधिसूचना

अधिग्रहण अधिनियम खरीददारों द्वारा निष्पादित किया जाने वाला एक अधिनियम था। यह वह अधिनियम है जो शुरू में पी. पी. ए. के स्तर पर नहीं किया गया था। अनुसूची 2 के भाग 1 में वन निकासी का भी उल्लेख किया गया है। यहाँ तक कि कहा गया है

मंजूरी भी स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं की गई थी जैसा कि पी. पी. ए. की शुरुआत में संकेत दिया गया है। इसके बाद, अनुसूची 2 के भाग 2 में वह खंड है जो प्रारंभिक सहमति के आधार पर तर्क का आधार है।

(62) इसने अनुच्छेद में उल्लिखित कार्य को पूरा करने पर विचार किया।

(63) तब यह सवाल उठेगा कि क्या कार्य के निष्पादन में देरी जो इसके प्रदर्शन पर विशेषता है। एक मानी गई प्रारंभिक सहमति के रूप में समय के भीतर अनुच्छेद 13.1 के अर्थ के भीतर कानून में परिवर्तन होगा। 1 . हम पाते हैं कि अनुच्छेद 3। 3 पी. पी. ए. इस प्रकार है:

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 3.3. 3 अनुच्छेद 3.1 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने में विक्रेता की असमर्थता के मामले में। 2 किसी भी आकस्मिक घटना के कारण, अनुच्छेद 3.1 में उल्लिखित शर्त के बाद की पूर्ति के लिए समय अवधि। 2 और अनुच्छेद 3.1। 2 ए, ऐसी आकस्मिक घटना की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा, जो कुल मिलाकर निरंतर या गैर-निरंतर दस (10) महीनों की अधिकतम विस्तार अवधि के अधीन होगा। इसके बाद, इस समझौते को खरीदार (संयुक्त रूप से) या विक्रेता द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित रूप में कम से कम सात (7) दिनों का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

इसी तरह, खरीदारों की पूर्ति करने में असमर्थता के मामले में

दस (10) महीनों की विस्तारित अवधि, कुल मिलाकर निरंतर या गैर-निरंतर। इसके बाद, इस समझौते को खरीदार (संयुक्त रूप से) या विक्रेता द्वारा दूसरे को लिखित रूप में कम से कम सात (7) दिनों का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

पार्टी "।

(64) हमें अगले अनुच्छेद 3 पर ध्यान देना चाहिए। 3 ए जो निम्नलिखित है: " 3.3. 3 ए अनुच्छेद 3.1 में निर्दिष्ट गतिविधियों को करने में खरीदारों की अक्षमता के मामले में। 2 ए उसमें निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर, विक्रेता या फोर्स मैजेयर घटना के लिए सीधे जिम्मेदार कारणों के अलावा, अनुच्छेद 3.1 में उल्लिखित बाद की शर्त। 2 एक 'दिन के लिए दिन' के आधार पर बढ़ाया जाएगा, के बराबर

अनुच्छेद 3.1 में उल्लिखित गतिविधियों को पूरा करने के लिए खरीददारों को अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है। 2 ए, अधिकतम छह (6) महीने के अतिरिक्त समय के अधीन। इसके बाद, इस समझौते को विक्रेता द्वारा खरीददारों को लिखित रूप में कम से कम सात (7) दिनों का नोटिस देकर अपने विकल्प पर समाप्त किया जा सकता है। यदि विक्रेता इस समझौते को समाप्त करने का विकल्प चुनता है, तो खरीददार, तीस दिनों की अवधि के भीतर, निम्नलिखित राशि के लिए विक्रेता में पूरी हिस्सेदारी खरीद लेंगे। बशर्ते कि शेयरों की ऐसी खरीद खरीददारों द्वारा उनकी तत्कालीन आवंटित संविदित क्षमता के अनुपात में की जाएगी:

क) सफल बोलीदाता द्वारा विक्रेता के शेयरधारकों को भुगतान की गई खरीद मूल्य की कुल राशि

आर. एफ. पी. के अनुसार विक्रेता; साथ ही हरियाणा पावर खरीद केंद्र V. ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

ख) भूमि के घोषित मूल्य और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (जी. आर.) की कुल राशि, जो चयनित बोलीदाता द्वारा अपनी 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद विक्रेता द्वारा पहले ही भुगतान की जा चुकी है;

प्लस

ग) उपखंड (क) और (ख) में उल्लिखित कुल राशियों के दस प्रतिशत (10 प्रतिशत) के बराबर एक अतिरिक्त राशि।

इसके अलावा, विक्रेता की प्रदर्शन गारंटी भी होगी।

तुरंत रिहा किया जाए। "

अनुच्छेद 3.1 में यथा अनुध्यात भूमि उपलब्ध कराना। 2 ए. इसका लंबा और छोटा यह है कि यदि खरीददारों द्वारा एक निश्चित समय सीमा को पार किया जाता है इस संबंध में अपने दायित्वों का पालन करते हुए, विक्रेता (प्रथम प्रतिवादी) को अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, यह खरीददारों पर कंपनी की पूरी शेयर पूंजी खरीदने पर जोर दे सकता है। , प्रथम प्रत्यर्थी, जैसा कि उसमें दिया गया है। यह पहले उत्तरदाता का मामला नहीं है कि उपरोक्त अनुच्छेदों को लागू करके, पहले उत्तरदाता

कथित तौर पर अनुबंध को अस्वीकार करने के लिए। दूसरी ओर, यह आम मामला है कि अनुबंध जीवित रहा और यह उन दावों के अधीन बच गया है जो इसके तहत उठाए गए हैं। इसका मतलब यह होगा कि अनुबंध में प्रदान किए गए तरीके से कार्य को पूरा करने में विफलता के परिणाम के रूप में, हमें सामान्य रूप से यह पूछने में देरी नहीं करनी चाहिए कि क्या यह अनुच्छेद 13.1 के तहत विचार किए गए कानून में परिवर्तन के लिए आधार प्रदान करेगा। 1 . हम अनिवार्य रूप से अभी भी सवाल उठाते हैं कि क्या यह कानून में बदलाव होगा। ऐसा नहीं है कि हम इस तथ्य से बेखबर हैं कि दोनों निकायों ने समवर्ती रूप से पाया है कि कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ है और अपील में प्रतिवादी द्वारा दर्ज किए गए हमले द्वारा बोलने के तरीके से इस तरह के निष्कर्ष को हटाने का प्रयास किया गया है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां पहले प्रतिवादी ने गलियारे के माध्यम से पाइपलाइन बिछाने के उद्देश्य से भूमि का उपयोग किया है जैसा कि विचार किया गया है और पाया गया है कि जल अंतर्ग्रहण प्रणाली से पानी लेने के परिणामस्वरूप पानी उपलब्ध नहीं होगा।

वर्ष की अवधि के दौरान पर्याप्त मात्रा। ऐसा कोई मामला नहीं है।

(66) दूसरी ओर, पहले प्रत्यर्थी का मामला यह है कि पी. पी. ए. पर दूसरे सप्ताह में 07.08.2007 पर हस्ताक्षर किए गए थे।

उसी वर्ष दिसंबर-2007, जल ग्रहण प्रणाली के माध्यम से पानी की उपलब्धता की पुष्टि करने के लिए, जैसा कि पहले [2023] 8 एस. सी. आर. में विचार किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वैपकोस की रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट को उसी सलाहकार के माध्यम से विडंबनापूर्ण तरीके से कमीशन किया गया था। ऐसा कोई मामला नहीं है कि पहली डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. रिपोर्ट के संदर्भ में पानी खींचने के प्रयास किए गए और यह पाया गया कि इस तरह का प्रयास विफल रहा, वे उसी निकाय द्वारा दूसरे अध्ययन का सहारा लेने के लिए मजबूर हुए। इस बात का कोई कारण सामने नहीं आ रहा है कि किस बात ने पहले उत्तरदाता को दूसरा अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। दूसरा, यह ऐसा मामला नहीं है जहां खरीदार लाए थे अध्ययन में अपने दम पर कानून में किसी भी बदलाव के बारे में या उन्होंने पहले प्रतिवादी को पाइपलाइन बिछाने के मार्ग के लिए गलियारे को बदलने के लिए राजी किया या मजबूर किया। पहले उत्तरदाता ने इसमें शामिल भी नहीं किया

दूसरे अध्ययन में खरीददार। ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है कि पहला उत्तरदाता एक नया अध्ययन शुरू कर रहा था। इस बात का कोई आधार नहीं है कि किस बात ने पहले उत्तरदाता को एक नया अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। केवल इतना कहा गया है कि यह पहले जल सेवन अध्ययन के संदर्भ में पानी की उपलब्धता की पुष्टि करना चाहता था। दूसरे शब्दों में, हमें संक्षेप में इस प्रकार कहना चाहिए: (67) यहां तक कि पी. पी. ए. की अनुसूची 2 के भाग 2 के आसपास बनाए गए मामले के संदर्भ में भी, जिसके तहत अनुच्छेद में उल्लिखित कार्य का निष्पादन किया जाता है।

3.1. 2 ए प्रदान किए गए समय के भीतर एक प्रारंभिक सहमति के रूप में माना जाना था, ऐसा करने में विफलता के परिणाम को स्पष्ट रूप से लिखा गया है जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं। सबसे अच्छा या सबसे बुरा, यह पहले प्रतिवादी को अनुबंध को रद्द करने का अधिकार दे सकता था। इसके अलावा, हम उन कारणों से इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में नहीं हैं, जिनके बारे में हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि यह कानून में बदलाव के बराबर होगा। कानून में बदलाव के दौरान, हम मामले का एक और पहलू देख सकते हैं।

(68) अनुच्छेद 13.3। 1 इस प्रकार पढ़ता है:

" 13.3. 1 यदि विक्रेता अनुच्छेद 13.2 के अनुसार कानून में परिवर्तन से प्रभावित होता है और इस अनुच्छेद के तहत कानून में परिवर्तन का दावा करना चाहता है, तो वह इसके बारे में जागरूक होने के बाद कानून में इस तरह के परिवर्तन के खरीदारों को जल्द से जल्द नोटिस देगा या उन्हें कानून में परिवर्तन के बारे में यथोचित रूप से पता होना चाहिए।

(69) इस प्रकार, पी. पी. ए. विचार करता है कि यदि विक्रेता कानून में परिवर्तन से प्रभावित है और कानून में परिवर्तन का दावा करना चाहता है, तो उसे सूचित करना होगा

कानून में परिवर्तन की प्राप्ति करने वाले इसके बारे में जागरूक होने के बाद जितनी जल्दी हो सके उचित रूप से व्यवहार्य हैं। यह सच हो सकता है कि के आधार पर

प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा किया गया अनुरोध स्पष्ट रूप से दूसरी वैपकोस रिपोर्ट के आधार पर किया गया है कि प्रथम प्रत्यर्थी ने हरियाणा पावर खरीद केंद्र V प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं।

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक भूमि। यह सच हो सकता है कि उक्त पाइपलाइन को अधिक दूरी पार करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि यह इस आधार पर था कि खरीददारों ने खुद को कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराया या खुद को दोषी ठहराया।

लागत में वृद्धि को ठीक करने के लिए कानून में उत्तरदायी। ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है जो यह दर्शाती हो कि खरीदारों ने कहा है कि वे उत्तरदायी होंगे। यह विवाद में नहीं है कि बिजली संयंत्र की पहली इकाई वास्तव में अगस्त, 2012 में चालू की गई थी। वास्तव में, जब हमने पूछा कि क्या अनुच्छेद 13.3 के संदर्भ में कोई नोटिस दिया गया था। 1 , विद्वान वकील श्री अमित कपूर, 15.12.2012 पर दिए गए नोटिस के अलावा इस तरह के किसी भी नोटिस की ओर इशारा नहीं कर सके। इस संबंध में भी, हम उक्त सूचना की सामग्री पर ध्यान दे सकते हैं:

" 5.2 भूमि के घोषित मूल्य में परिवर्तन, पुनर्वास के कार्यान्वयन की लागत और भूमि का पुनर्वास पैकेज, खनन पर सीमा शुल्क में बदलाव

उपकरण, जल ग्रहण प्रणाली आदि।

(क) एस. पी. एल. द्वारा भूमि के लिए किया गया वास्तविक व्यय, परियोजना के लिए भूमि के पुनर्वास और पुनर्वास पैकेज का कार्यान्वयन, जल ग्रहण प्रणाली, खनन पर सीमा शुल्क। सीमेंट और इस्पात पर उपकरण और उत्पाद शुल्क।

(70) इसमें केवल इतना संकेत दिया गया है कि पानी के सेवन के लिए मूल लागत Rs.92 करोड़ रखी गई थी, जबकि अनुमानित लागत

(71) इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री अमित कपूर ने कार्यवृत्त से प्रेरणा लेने का प्रयास किया। बैठक जो 20.03.2013 पर हुई थी जिसके अनुसार प्रमुख खरीददार परिवर्तन के लिए सहमत हुआ प्रतीत होता है। विद्वान वकील श्री अमित कपूर का मामला है कि प्रमुख खरीददार अन्य खरीददारों को बाध्य कर सकता है

श्री एम. जी. रामचंद्रन द्वारा चुनाव लड़ा गया, विद्वान वरिष्ठ वकील।

(73) यह तर्क कि खरीदार उस भूमि के अधिग्रहण के लिए सहमत हुए जिसके माध्यम से नए मार्ग को यात्रा करनी थी, भी अपील नहीं करता है। कानून में पहले प्रतिवादी के दावे को दृढ़ता से स्थापित करने के लिए। इस मामले को कानून में परिवर्तन और कानून में वास्तविक परिवर्तन को परिभाषित करने वाले विशिष्ट प्रावधानों के चश्मे से देखा जाना चाहिए जो कि हमारे पास [2023] 8 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऊपर समझाया गया है। संक्षेप में, एक अनुबंध से सम्मानित होने और पी. पी. ए. में प्रवेश करने के बाद और तथ्यों में किसी भी आधार के बिना, पहले प्रतिवादी ने एक नया अध्ययन शुरू करने का साहस किया और उसी पर कार्य करते हुए, एक नया पाइपलाइन गलियारा घटनास्थल पर आया। आवश्यक रूप से लागत बढ़ सकती है।

लेकिन हमें जो सवाल तय करना है वह यह है कि क्या यह कानून में बदलाव है और हमारा विचार है कि यह कानून में बदलाव नहीं हो सकता है जैसा कि समझौते में विचार किया गया है क्योंकि यह प्रारंभिक सहमति में बदलाव नहीं है जो एकमात्र है। जिस मामले में इस संबंध में बहस की गई है।

(74) आगे तर्क केवल यह है कि अनुमानित लागत Rs.92 करोड़ थी और उससे अधिक राशि खर्च करनी थी। इस संबंध में, हम पी. पी. ए. में निम्नलिखित खंड देख सकते हैं:

" 5.2 साइट

विक्रेता स्वीकार करता है कि इस समझौते में प्रवेश करने से पहले, उसे साइट की जांच करने का पर्याप्त अवसर मिला है और उसकी स्थिति के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता है (जिसमें साइट पर इसकी भूगर्भीय स्थिति, साइट पर सड़क और रेल लिंक की पर्याप्तता और पानी की पर्याप्त आपूर्ति की उपलब्धता शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है) और सहमत है कि उसे इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा या साइट की अनुपयुक्तता के कारण समय के किसी भी विस्तार या वित्तीय मुआवजे का हकदार नहीं होगा।

किसी भी कारण से।

पुनर्वास और पुनर्वास पैकेज ("आर एंड आर") परियोजना के लिए स्थल, जिसके लिए लागत विक्रेता द्वारा वहन की जानी है। खरीददार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि राज्य सरकार विभिन्न निर्माण गतिविधियों के लिए भूमि समय पर उपलब्ध हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिजलीघर और प्रत्येक इकाई समय पर चालू हो। आर एंड आर पैकेज की उन गतिविधियों के निष्पादन में और अनुमानित लागतों के अनुसार, विक्रेता की सहायता मांगी जा सकती है, जो वह सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर प्रदान करेगा, यदि ऐसी गतिविधियों का निष्पादन त्वरित कार्यान्वयन के हित में है।

पैकेज और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है। "

(75) वास्तव में दिए गए निष्कर्षों की ओर बढ़ते हुए

न्यायाधिकरण द्वारा, न्यायाधिकरण ने विवादित आदेश में पाया है कि डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. की पहली रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। हम यह समझने से चूक गए हैं कि इस तरह के निष्कर्ष को प्रस्तुत करने का आधार क्या था।

हरियाणा शक्ति खरीद केंद्र के बिना V. ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

किसी भी सामग्री के रूप में, यह थोड़ा अस्पष्ट है कि न्यायाधिकरण इस तरह के निष्कर्ष को कैसे प्रस्तुत कर सकता था जिसके गंभीर परिणाम हैं जैसा कि हमने देखा है। यह निस्संदेह यह पता लगाने के बाद है कि कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वस्तुतः न्यायाधिकरण ने अस्वीकरण खंडों को खारिज कर दिया है। डिस्कलेमर खंडों पर जाने से पहले, हम यह भी संकेत दे सकते हैं कि पहली डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. रिपोर्ट का अवलोकन इंगित करता है कि यह एक काफी विस्तृत रिपोर्ट है।

जैसा कि हमने देखा है कि खरीदारों के संदर्भ के बिना तैयार की जा रही दूसरी वैपकोस रिपोर्ट कुछ भी ऐसा नहीं कहती है जो पहली वैपकोस रिपोर्ट की आलोचना करती हो। कम से कम, वास्तव में, पहली रिपोर्ट के बारे में कोई स्पष्ट फुसफुसाहट नहीं है। वह सब दूसरा वैपकोस रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि काम दिए जाने के बाद वैपकोस ने एक और रिपोर्ट तैयार की है। कम से कम हम यह पता लगाने में असमर्थ हैं कि दूसरी रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधिकरण कैसे पता लगा सकता है कि पहली डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. रिपोर्ट सरासर गलत थी। न्यायाधिकरण ने दोनों रिपोर्टों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया है। दोनों रिपोर्टों पर कोई चर्चा नहीं हुई है। न ही कोई

इस तरह के निष्कर्ष को प्रस्तुत करने के लिए प्रदान की गई अन्य सामग्री। एकमात्र क्षेत्र जहाँ हम पाते हैं कि शायद पहली रिपोर्ट के संदर्भ के रूप में क्या समझा जा सकता है वह खंड 4.2 है। 2 . वह इस प्रकार है:

“ 4.2. 2 . जैसा कि परियोजना प्राधिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि वल्लभ पंत सागर के दाईं ओर पाइपलाइन गलियारे का अधिग्रहण अंतिम चरण में है और डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस./सी. डब्ल्यू. पी. आर. एस. दल द्वारा स्थानीय जांच सर्वेक्षण क्षेत्र 'ए' द्वारा स्थल की यात्रा के दौरान एकत्र की गई अन्य जानकारी को विस्तृत सर्वेक्षण के दौरान विस्तृत सर्वेक्षण के लिए पहचाना गया है। कि अंतर्ग्रहण के लिए पर्याप्त गहराई उपलब्ध नहीं है और साथ ही जलाशय का तल स्तर लगभग 252.5 है और यह भी एक छोटे से पैच में था।

इसलिए, इस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है।

(76) ऐसा प्रतीत होता है कि श्री एम. जी. रामचंद्रन के अनुसार 'परियोजना प्राधिकरण' शब्द को पहले प्रतिवादी के रूप में समझा जाना चाहिए।

वह सब भी खंड 4.2। 2 इंगित करता है कि पहले प्रतिवादी ने सूचित किया कि पाइपलाइन गलियारे के लिए अधिग्रहण अपने अंतिम चरण में था और उसके बाद यह संकेत दिया जाता है कि विस्तृत सर्वेक्षण के दौरान, यह पाया गया कि पर्याप्त गहराई उपलब्ध नहीं है।

(77) हमें नहीं लगता कि यह पहली रिपोर्ट को सरासर गलत बताने के बाद दूसरी रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का आधार हो सकता है।

(78) अब हम अस्वीकरण खंडों पर विचार कर सकते हैं। अस्वीकृतियाँ

दिशानिर्देशों में उनकी उत्पत्ति है। आर. एफ. पी. का नोट 4 इंगित करता है कि अपने निदेशकों, कर्मचारियों के अलावा खरीदारों को [2023] 8 एस. सी. आर. के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी भी कानून के तहत अन्य बातों के साथ-साथ भले ही बोली लगाने वाले को उनकी ओर से किसी भी कार्य या चूक से कोई नुकसान या क्षति हो। आर. एफ. पी. के खंड 1.4 ने बोलीदाताओं को स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि खरीददार अन्य बातों के साथ-साथ जल ग्रहण अध्ययन रिपोर्ट और परियोजना रिपोर्ट में किए गए किसी भी बयान या चूक के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं या कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं। उसमें निहित जानकारी की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता के बारे में भी एक विशिष्ट अस्वीकृति है। यह समान है। यदि चयनित बोलीदाता को उनकी ओर से किसी कार्य या चूक से कोई नुकसान या क्षति होती है। इस प्रकार, जल सेवन अध्ययन रिपोर्ट के संबंध में, भावी विक्रेता या बोलीदाताओं को विशेष रूप से बिना किसी अनिश्चित शब्दों में कहा गया था कि जल सेवन अध्ययन रिपोर्ट में किसी भी विवरण या चूक के परिणामस्वरूप खरीदारों को देयता के साथ नहीं देखा जाएगा, भले ही चयनित बोलीदाता को नुकसान या क्षति हुई हो। निम्नलिखित कारणों से इस समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(79) पहले उत्तरदाता का मामला है कि जल ग्रहण प्रणाली जल विज्ञान में जाती है जबकि भूविज्ञान के संबंध में, पहला उत्तरदाता

स्वयं पूछताछ करने के लिए कर्तव्यबद्ध था। चूँकि जलविज्ञान और जल ग्रहण प्रणाली के बीच संबंध वास्तविक है और चूँकि जलविज्ञान के बारे में स्थितियों के संबंध में, पहले उत्तरदाता ने खरीदारों या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर भरोसा किया, विशेष रूप से, उन्हें राहत मिलनी चाहिए।

अपने दम पर किसी भी आगे की जांच करने के लिए किसी भी दायित्व का संचालन करता है तर्क।

अन्य खंडों के संचालन से बोली लगाने वाला। एक कानूनी संबंध के माध्यम से एक अनुबंध क्या उत्पन्न करता है, इस मामले में एक न्यायपूर्ण परिणाम को सभी प्रासंगिक खंडों के सामंजस्यपूर्ण सर्वेक्षण पर समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। किसी भी अन्य दृष्टिकोण में, परिणाम का विषय से संबंधित विशिष्ट खंडों को प्रस्तुत करने का प्रभाव होगा। आर. एफ. पी. के खंड 1.4 को ध्यान में रखते हुए, दूसरे शब्दों में, बोलीदाता कर्तव्यबद्ध था यदि उसे डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. द्वारा दी गई रिपोर्ट की शुद्धता की जांच करने की सलाह दी जाती है। यह हो सकता है। अपना अध्ययन स्वयं किया है। अनुबंध दिए जाने और पी. पी. ए. में प्रवेश करने के चार महीने बाद उसने जो किया, वह बोली लगाने और पी. पी. ए. में प्रवेश करने का निर्णय लेने से पहले किया जा सकता था। कम से कम हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जो बोली लगाने वाले के अपने हरियाणा पावर खरीद केंद्र V के संचालन के रास्ते में आड़े आ रहा हो।

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

अध्ययन करना और रिपोर्ट की शुद्धता से आश्वस्त होना। हम ऐसा इस कारण से कहते हैं कि इसमें एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली शामिल है। बोली प्रक्रिया अधिनियम की धारा 63 के संदर्भ में मूल्य के निर्धारण की नींव है। आयोग ने दरों को मंजूरी दी

आश्वस्त होना कि दरें उचित और प्रतिस्पर्धी हैं और एक उचित बोली प्रक्रिया के आधार पर प्राप्त की गई हैं। इसलिए, आर. एफ. पी. के प्रावधानों को इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि बोली लगाने वालों को उन अभेद्य वस्तुओं के बारे में सतर्क किया जाए जो अनिवार्य रूप से मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में शामिल हैं।

इसका मतलब यह है कि आर. एफ. पी. के खंड 1.4 के संबंध में, कोई भी बोलीदाता संभवतः इस दावे के साथ आगे नहीं आ सकता है कि डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. रिपोर्ट की सामग्री को पवित्र और अचूक माना जाना चाहिए और इसे एक चुटकी नमक के बिना नहीं लिया जाना चाहिए। कम से कम यह वह संदेश था जो उक्त खंड में व्यापक रूप से लिखा गया है। जिसने अभिनय किया

रिपोर्ट के बारे में चेतावनी की अवहेलना ने अपने जोखिम पर काम किया।

(81) पुनः, हम खंड 2.7 पर ध्यान देते हैं। 2 आर. एफ. पी. जो हम पहले ही संकेत कर चुके हैं। यह बोलीदाता की ओर से कर्तव्य पर विचार करता है

स्वतंत्र जांच करना और आवश्यक जानकारी, इनपुट, शर्तों, परिस्थितियों के संबंध में खुद को संतुष्ट करना, जो बोली को प्रभावित कर सकते हैं। यह खंड 5 में पी. पी. ए. में निर्दिष्ट स्थल से अलग है जिसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं।

(82) अस्वीकरण खंडों के धन के साथ जो हमने देखा है, हम न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। हम.

उनका विचार है कि न्यायाधिकरण ने उन विशिष्ट और असंदिग्ध अस्वीकृतियों को दरकिनार करके गलत किया था जिनके तहत खरीददार दायित्व से मुक्त थे।

' इस अनुच्छेद 13 में जिस हद तक विचार किया गया है। जब हम अनुच्छेद 13.2 के भाग के रूप में 'इस अनुच्छेद 13 में विचार की गई सीमा तक' शब्दों को पढ़ते हैं, तो यह आवश्यक रूप से अनुच्छेद 13.2 के खंड (ए) और (बी) को शामिल करता है। दूसरे शब्दों में, पार्टियों ने जो विचार किया है वह परिवर्तन का परिणाम है कानून के परिणामस्वरूप इसे मासिक [2023] 8 एस. सी. आर. के तंत्र के माध्यम से संबोधित किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूरक विलों के माध्यम से शुल्क भुगतान (अनुच्छेद 13.4.2 देखें)। लेकिन यह उस हद तक है जिस पर अनुच्छेद 13 में विचार किया गया है। सवाल यह उठेगा कि क्या पक्षों ने विचार किया कि उन्होंने सक्षम निकाय को अधिकार दिया है। , आयोग अनुच्छेद 13.2 (क) और (ख) में दिए गए सूत्र को त्याग देगा। हमारा विचार है कि अनुच्छेद 13.2 के तहत पक्षों ने जो विचार किया वह यह था कि कानून में परिवर्तन को खंड (ए) और (बी) के विशिष्ट प्रावधानों के माध्यम से देखा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, निर्माण की अवधि के दौरान कानून में परिवर्तन हो सकता है। फिर इसे अनुच्छेद 13.2 (ए) के तहत आने वाला माना जाएगा। इसके संचालन की अवधि के दौरान कानून में बदलाव हो सकता है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर खंड (ख) के तहत विचार किया जाएगा। यदि इस अवधि के दौरान कानून में कोई परिवर्तन होता है

निर्माण के बाद इसके प्रभाव को परियोजना की पूंजी लागत के संदर्भ में मापा जाना है। पी. पी. ए. में 'पूंजी लागत' शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। एक सूत्र उत्कीर्ण किया गया है। इस सूत्र में विचार किया गया है कि कानून में बदलाव के परिणामस्वरूप पूंजी लागत में प्रत्येक Rs.50 करोड़ की वृद्धि/कमी के लिए, गैर-वृद्धि योग्य क्षमता शुल्क में वृद्धि/कमी गैर-वृद्धि योग्य क्षमता शुल्क का 0.267 प्रतिशत होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह तब होता है जब विक्रेता खरीददारों को स्थापना में इस तरह की वृद्धि/कमी का दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करता है।

इस तरह के परिवर्तन का प्रभाव।

(84) दूसरे शब्दों में, के दौरान कानून में परिवर्तन का प्रभाव

निर्माण अवधि 13.2 (ए) से ली गई है। हमें यह समझना चाहिए कि यह अनुबंध के माध्यम से सावधानीपूर्वक सोचा गया है जो एक लंबी कठोर प्रक्रिया के बाद उभरा है। पार्टियां इस बारे में स्पष्ट थीं कि कानून में बदलाव कैसे करना था

क्षतिपूर्ति की जाए और कार्यप्रणाली स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। इसलिए, अनुच्छेद 13.2 में सामान्य भाग को की गई कोई भी अपील जो प्रभावित पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में बहाल करने के बारे में बताती है जैसे कि कानून में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ था, उसके परिणामस्वरूप उस विशिष्ट सूत्र से प्रस्थान नहीं हो सकता है जो निर्धारित किया गया है। यह अर्थ इस अनुच्छेद 13 में विचार किए गए शब्दों से अपरिहार्य है, जो सामान्य शब्दों से पहले आता है। इस संबंध में, हम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और Anr.¹ में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं। उक्त निर्णय में, प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा भी इस पर समझदारी से भरोसा किया गया है और जो उसी खंड (अनुच्छेद 13.2) के तहत भी उत्पन्न हुआ है, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

" 10. अनुच्छेद 13.2 एक अंतर्निर्मित प्रतिस्थापन सिद्धांत है जो कानून में इस तरह के परिवर्तन से प्रभावित पक्ष को क्षतिपूर्ति करता है और जो

} 1 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और अन्न. वी. अदानी पावर लिमिटेड और अन्य।

(2019) 5 एस. सी. सी. 325 रयान पावर खरीद केंद्र v. ससान पावर लिमिटेड & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

मासिक शुल्क भुगतान के माध्यम से, प्रभावित पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में बहाल करना चाहिए जैसे कि कानून में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब यह होगा कि इस खंड द्वारा एक कल्पना बनाई गई है, और पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में रखा जाना चाहिए जैसे कि कानून में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी पक्ष को नागरिक कानून में समझे गए पुनर्स्थापन का लाभ दिया जाना चाहिए। हालाँकि, अनुच्छेद 13.2 इस तरह की बहाली को दो अलग-अलग अवधियों में विभाजित करता है। पहली अवधि "निर्माण अवधि" है जिसमें शुल्क में परियोजना की पूंजी लागत की वृद्धि/कमी को एक निश्चित सूत्र द्वारा नियंत्रित किया जाना है। हालाँकि, विक्रेता को खरीददार को इस तरह की वृद्धि का दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करना होगा।

इस तरह के परिवर्तन के प्रभाव को स्थापित करने के लिए पूंजी लागत में कमी

कानून में और उसी के बारे में विवाद के मामले में, पी. पी. ए. के अनुच्छेद 17 के अनुसार एक विवाद समाधान तंत्र का सहारा लिया जाना है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि मुआवजा केवल किसी भी पक्ष को देय है। केवल उस तारीख से प्रभावी जिस दिन कुल वृद्धि/कमी उसमें बताई गई राशि से अधिक हो।

13. इसलिए, अनुच्छेद 13 को समग्र रूप से पढ़ने से यह स्थिति आती है कि अनुच्छेद 13 में निहित प्रतिस्थापन सिद्धांतों के अधीन, मासिक शुल्क भुगतान में समायोजन, वर्तमान मामले के तथ्यों में, वापस लेने की तारीख से होना चाहिए।

छूट जो 6-4 दिनांकित प्रशासनिक आदेशों द्वारा दी गई थी

2015 और 16-2-2016। अतः वर्तमान मामला अनुच्छेद 13.4 के अंतर्गत आता है। 1 (i)। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि मासिक शुल्क भुगतान में समायोजन उस तारीख से प्रभावी होना चाहिए जिस दिन दी गई छूट वापस ली गई थी। इस मामले में, टैरिफ में इस तरह के बदलाव के बाद विक्रेता द्वारा उठाए जाने वाले मासिक चालान उचित रूप से बदले हुए टैरिफ को दर्शाते हैं। वर्तमान मामले के तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता उस तारीख से अपने मासिक शुल्क भुगतान में समायोजन के हकदार थे जिस दिन छूट अधिसूचनाएं प्रभावी हुईं। इस मामले में, अनुच्छेद 13.2 में निहित प्रतिस्थापन सिद्धांत होगा

इस साधारण कारण से प्रवेश करें कि यह केवल 4 5-2017 [अडानी पावर लिमिटेड v. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन सी. ई. आर. सी. 66] कि सी. ई. आर. सी. ने माना कि उत्तरदाता अतिरिक्त लागत का दावा करने के हकदार थे क्योंकि

डब्ल्यू. ई. एफ. 1-4-2015 कानून में परिवर्तन। इस मामले में, यह कहना गलत होगा कि उत्तरदाता [2023] 8 एस. सी. आर. के बाहर इक्विटी के कुछ सामान्य सिद्धांत पर इस प्रतिस्थापन राशि का दावा करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पीपीए। चूँकि यह स्पष्ट है कि वहन लागत की यह राशि केवल

पीपीए के अनुच्छेद 13 से संबंधित, हमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है

अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय के साथ।

19. अंत में, एनर्जी वॉचडॉग बनाम में इस न्यायालय का निर्णय।

सी. ई. आर. सी. [एनर्जी वॉचडॉग बनाम। सी. ई. आर. सी. (2017) 14 एस. सी. सी. 80:
(2018) 1

एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 133] पर भी भरोसा किया गया था। इस फैसले में तीन मुद्दे हैं।

निर्धारित और तय किया गया था, जिनमें से एक से संबंधित था

पी. पी. ए. के कानून प्रावधान में परिवर्तन। उस परिवर्तन को बनाए रखने में

इंडोनेशियाई कानून के तहत कानून में परिवर्तन के रूप में योग्य नहीं होगा

पी. पी. ए. के साथ पठित दिशानिर्देश, इस न्यायालय ने खंड 13.2 का उल्लेख किया इस प्रकार है: (एस. सी. सी पी. 131, पैरा 57)

" 57 यह इस प्रकार होने के कारण, यह स्पष्ट है कि जहां तक खरीद की बात है

भारतीय कोयले का संबंध इस हद तक है कि कोयले से आपूर्ति

भारत और अन्य भारतीय स्रोतों में कटौती की गई है, पीपीए के साथ पढ़ा जाता है

इन दस्तावेजों में खंड 13.2 में यह प्रावधान किया गया है कि कानून में परिवर्तन के परिणामों का पक्षकारों को उचित सम्मान होगा।

इस सिद्धांत पर कि पक्ष को क्षतिपूर्ति देने का उद्देश्य प्रभावित हुआ कानून में इस तरह के बदलाव से मासिक शुल्क के माध्यम से बहाल किया जाना है।

भुगतान, प्रभावित पक्ष को आर्थिक स्थिति के लिए जैसे कि कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

इस निर्णय से कोई संदेह नहीं हो सकता है कि प्रतिस्थापन

खंड 13.2 में निहित सिद्धांत को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

भले ही लागत में वृद्धि/कमी के लिए मुआवजा हो सीईआरसी द्वारा निर्धारित "।

(जोर दिया गया)

(85) हमारा मानना है कि हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह सही है।

इस द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण के साथ किसी भी तरह से टकराव
टी.

(86) इसमें कोई संदेह नहीं है कि एनर्जी वॉचडॉग में एक बार फिर ऐसा निर्णय लिया गया है जो

1 दोनों पक्षों द्वारा, न्यायालय के तहत एक मामले पर विचार कर रहा था

सी. टी. और निम्नलिखित विचार व्यक्त किया है:

इस अधिनियम के प्रावधान, वर्तमान में निर्णय के लिए आते हैं
सकता है कि धारा 63 एक गैर के साथ शुरू होती है

अपीलें करें। यह ध्यान दिया जा

जी वॉचडॉग वी। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य (2017)

सी 80 रयान पावर खरीद केंद्र v. ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

अड़चन खंड, लेकिन यह केवल धारा 62 को शामिल करने वाला एक अड़चन खंड है। दूसरा, धारा 61 और 64 के साथ पठित धारा 62 के विपरीत, उपयुक्त आयोग शुल्क "निर्धारित" नहीं करता है, बल्कि केवल धारा 63 के तहत पहले से निर्धारित शुल्क को "अपनाता है"। तीसरा, इस तरह की "स्वीकृति" केवल तभी होती है जब बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से इस तरह के शुल्क का निर्धारण किया गया हो, और चौथा, बोली लगाने की यह पारदर्शी प्रक्रिया जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए।

केंद्र सरकार द्वारा। हमारे सामने जो तर्क दिया गया है वह यह है कि धारा 63 एक स्वतंत्र प्रावधान है और इसे अपनी शर्तों पर समझा जाना चाहिए, और इसलिए, पारदर्शी बोली के मामले में बोली के अलावा कुछ भी नहीं देखा जा सकता है जो केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। एक बात तुरंत स्पष्ट है कि उपयुक्त आयोग धारा 63 के तहत केवल डाकघर के रूप में कार्य नहीं करता है। इसे उस शुल्क को अपनाना चाहिए जो एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश। इस धारा के तहत 19-1-2005 पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है। खंड 4, विशेष रूप से, शुल्क से संबंधित है और उपयुक्त आयोग के पास निश्चित रूप से यह देखने का अधिकार क्षेत्र है कि बोली लगाने की प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित शुल्क खंड 4 के अनुरूप है या नहीं। 20. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां तक शुल्क का संबंध है, केंद्रीय आयोग की नियामक शक्तियां विशेष रूप से निम्नलिखित हैं -

धारा 79 (1) में उल्लिखित है। यह नियामक शक्ति एक सामान्य है

एक, और यह कहना बहुत मुश्किल है कि जब आयोग धारा 63 के तहत शुल्क को अपनाता है, तो यह धारा 79 (1) (बी) के तहत अपनी सामान्य नियामक शक्ति का उल्लंघन करता है। एक बात यह है कि इस तरह का विनियमन केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के तहत होता है। दूसरे के लिए, ऐसी स्थिति में जहां कोई दिशानिर्देश नहीं है या

ऐसी स्थिति जो दिशानिर्देशों में शामिल नहीं है, क्या यह कहा जा सकता है कि शुल्क को "विनियमित" करने की आयोग की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है? हमारे अनुसार, यह उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों को पढ़ने का सही तरीका नहीं है। वैधानिक का पहला नियम

व्याख्या यह है कि कानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। उस नियम के सहवर्ती के रूप में, यह भी स्पष्ट है कि विभिन्न अनुभागों द्वारा लगाए गए सभी विसंगत नोटों में सामंजस्य होना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गैर-बाध्यकारी खंड सलाह से धारा 62 तक ही सीमित है, हम धारा 79 को [2023] 8 एस. सी. आर. से बाहर रखने का कोई उचित कारण नहीं देखते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूरी तरह से। केवल धारा 62 के होने का कारण

रास्ते से हटकर यह है कि शुल्क का निर्धारण दो तरीकों में से एक में हो सकता है-या तो धारा 62 के तहत, जहां आयोग

स्वयं के प्रावधानों के अनुसार शुल्क निर्धारित करता है

अधिनियम (के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करने के बाद) धारा 61 में उल्लिखित शुल्क का निर्धारण) या धारा 63 के तहत जहां आयोग पहले से ही बोली की एक पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा निर्धारित शुल्क को अपनाता है। दोनों ही मामलों में, धारा 79 (1) (बी) के तहत आयोग की सामान्य नियामक शक्ति विनियमित करने की शक्ति का स्रोत है, जिसमें शुल्क निर्धारित करने या अपनाने की शक्ति शामिल है। वास्तव में, धारा 62 और 63 शुल्क के "निर्धारण" से संबंधित हैं, जो शुल्क को "विनियमित" करने का हिस्सा है।

जबकि अंतर-राज्य संचरण के लिए शुल्क का "निर्धारण"

बिजली को धारा 79 (1) (डी) द्वारा नियंत्रित किया जाता है, धारा 79 (1) (बी) शुल्क को "विनियमित" करने के लिए बिजली का एक व्यापक स्रोत है। यह स्पष्ट है कि ए

ऐसी स्थिति जहाँ केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश

धारा 63 के तहत स्थिति को शामिल किया गया है, केंद्रीय आयोग है

उन दिशानिर्देशों से बंधे और धारा 79 (1) (बी) के तहत अपने नियामक कार्यों का प्रयोग केवल उन दिशानिर्देशों के अनुसार करना चाहिए। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह केवल ऐसी स्थिति में है जहां कोई दिशानिर्देश नहीं बनाए गए हैं या जहां दिशानिर्देश लागू होते हैं। किसी दी गई स्थिति से निपटने के लिए नहीं कि आयोग के जनरल

तब धारा 79 (1) (बी) के तहत नियामक शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

(87) यह सच है कि जहां तक उक्त मामले का संबंध है, मामला उन दावों से उत्पन्न हुआ जो पीपीए के तहत इस आधार पर किए गए थे कि

इस तर्क के अलावा कानून में बदलाव किए गए थे कि फोर्स मैजेयर का मामला बनाया गया था। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें वास्तव में तथ्यों के आधार पर न्यायालय धारा 63 के तहत शुल्क के निर्धारण से उत्पन्न मामले से निपट रहा हो। वास्तव में, यह पी. पी. ए. की मंजूरी के बाद उत्पन्न हुआ और धारा 63 के तहत दरें पहले से ही तय की गई थीं। हालाँकि, यदि हम पैरा 19 और 20 की सामग्री पर ध्यान देते हैं, तो वह सिद्धांत जो पहला प्रतिवादी हमारे सामने प्रकट करना चाहता है, प्रकट नहीं होता है। प्रथम प्रत्यर्थी का तर्क है कि अनुबंध की शर्तों के बावजूद, अधिनियम की धारा 79 के तहत सामान्य नियामक शक्ति उपलब्ध है। वहाँ एक है

आयोग के साथ धारा 79 के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाला व्यापक अधिकार जो इसे सक्षम बनाएगा और जो इसे अनुबंध की शर्तों के बावजूद मुआवजा देने के लिए सशक्त बनाएगा। तर्क यह प्रतीत होता है कि अनुबंधों की व्यापकता के विपरीत, एक विनियमित अनुबंध जो एक दीर्घकालिक अनुबंध या एक अपूर्ण अनुबंध है, हरियाणा पावर खरीद केंद्र V उत्पन्न करता है।

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

दरों पर फिर से विचार करने के लिए उपयुक्त नियामक निकाय के साथ शक्ति के लिए स्थान

और इस प्रकार दोनों पक्षों के लिए एक उचित सौदा सुनिश्चित करता है, चाहे वह विक्रेता हो या विक्रेता।

खरीददार।

(88) इस न्यायालय ने एनर्जी वॉचडॉग 3 में पैरा 19 और 20 में जो कुछ निर्धारित किया है, उसका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

(89) अधिनियम की धारा 63 के तहत शुल्क निर्धारित करने के मामले में, जो विचार किया गया है वह दिशानिर्देशों के साथ शुरू करना है जो जारी किए गए हैं। धारा 63 के तहत। जब आयोग को शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है

धारा 63 के तहत, यह दिशानिर्देशों का पालन करता है क्योंकि यह उसी से अलग नहीं हो सकता है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां दिशा-निर्देश लागू नहीं होते हैं, निस्संदेह आयोग को एक नियामक निकाय के रूप में सभी पक्षों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने और शुल्क को इस तरह से तय करने की शक्ति प्राप्त है जो इस अर्थ में उचित हो कि बिजली के बड़े हुए उत्पादन के सर्वोपरि हित, उपभोक्ता के हित को ध्यान में रखते हुए, और विक्रेता को उचित लाभ सुनिश्चित करना भी। अब तक बहुत अच्छा है। जब आयोग धारा 63 के तहत शक्ति का प्रयोग करता है, तो इस शक्ति को तब कम नहीं किया जाता है जब क्षेत्र को धारण करने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं होते हैं।

(90) हम ऐसे मामले पर विचार नहीं कर रहे हैं जहां धारा 63 के तहत आयोग की शक्ति का प्रयोग समीक्षा के अधीन है। एक मामले में जहाँ,

हालाँकि, दरों को धारा 63 के तहत अनुमोदित किया जाता है और पी. पी. ए. में प्रवेश किया जाता है, निस्संदेह यह सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसी शक्ति है जिसे धारा 79 के तहत आयोग के साथ पूर्ण शक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है? क्या कोई ऐसी शक्ति हो सकती है जो

सर्वव्यापी के रूप में नामित किया जा सकता है? क्या न्यायाधिकरण, दूसरे शब्दों में, अनुबंध के स्पष्ट शब्दों की अवहेलना कर सकता है? क्या यह कानून में एक नए परिवर्तन की खोज कर सकता है जिसे पक्षों ने कानून में परिवर्तन के रूप में नहीं माना है? संक्षेप में, क्या न्यायाधिकरण अनुबंध को फिर से लिख सकता है और एक नया सौदा कर सकता है?

(91) हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण वास्तव में पक्षों के लिए एक नया सौदा नहीं कर सकता है। न्यायाधिकरण किसी अनुबंध को फिर से नहीं लिख सकता है।

गंभीरता से प्रवेश किया। यह एक नए समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है। कार्य करने की ऐसी अवशिष्ट शक्तियाँ जो लिखित अनुबंध में परिवर्तन करती हैं, उन्हें विनियमित करने की शक्ति में नहीं पाया जा सकता है। शक्ति का प्रयोग किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता है अनुबंध के स्पष्ट प्रावधान।

(92) हम इसे इस कारण से देखते हैं कि पहले प्रतिवादी के पास एक मामला है कि अनुच्छेद 13.2 (ए) में क्या प्रदान किया गया है (क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं)।

3 एनर्जी बॉचडॉग बनाम। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य (2017) 14 एस. सी. सी. 80
[2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्माण अवधि के दौरान कानून में कथित परिवर्तन का मामला) पक्षों के साथ न्याय नहीं करता है या यह कि यह एक उचित परिणाम देने में असमर्थ है और इसलिए, न्यायाधिकरण को अनिवार्य रूप से अपनी नियामक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शक्ति प्रदान की जाएगी। ऐसे मामले में जहां पक्षों ने स्पष्ट प्रावधानों के साथ एक अनुबंध किया है, हम पहले प्रतिवादी के साथ सहमत होने में असमर्थ हैं कि न्यायाधिकरण के पास अनुबंध के स्पष्ट प्रावधानों की अवहेलना करने की शक्ति होगी क्योंकि यह पता चलता है कि समय बीतने और यहां तक कि परिस्थितियों में बदलाव के साथ, यह पाया जाता है कि अनुबंध ठेकेदार के नुकसान के अलावा काम नहीं किया जा सकता है।

कि अन्यायपूर्ण पक्ष अनुबंध के निष्पादन पर जोर दे सकता है और फिर भी, यह माँग करने में दृढ़ रह सकता है कि उसे उसी पद पर रखा जाए यदि वह गलत निरूपण से गुमराह नहीं हुआ था। इस सिद्धांत को लेकर कोई विवाद नहीं हो सकता है। लेकिन हमने देखा है कि अस्वीकरण खंडों में निहित विभिन्न खंड। जब अनुबंध का कोई पक्ष यह कहता है कि पहली डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. रिपोर्ट में जो कुछ भी निहित है और आर. एफ. पी. और पी. पी. ए. में जैसा कुछ भी विचार किया गया है, वह प्रतिनिधित्व के बराबर नहीं है, तो हम इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ हैं कि इसे अभी भी धारा 18 के अर्थ के भीतर एक प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाएगा और इस तरह अनुबंध अधिनियम की धारा 19 के तहत दावा किया जाएगा। इसलिए, हम पाते हैं कि धारा 18 और 19 के प्रावधानों के तहत पहले प्रतिवादी द्वारा उठाए गए तर्क असमर्थनीय हैं।

(94) रिलायंस को इस कोर्ट पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम के फैसले पर रखा गया था। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (2010) 4 एस. सी. सी.

603. पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड में जो वास्तविक प्रश्न उठा वह था -

4 पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (2010) 4 एस. सी. सी. 603
रयान बिजली खरीद केंद्र बनाम।

अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के पास अधिनियम की धारा 178 आर की शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए विनियमों की वैधता की जांच करने की धारा के तहत अधिकार क्षेत्र है। एक और सवाल जो उठा वह थाउनकी संसद ने अधिनियम की धारा 121 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की है। इस निर्णय के दौरान,

अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

" 53. 2003 के अधिनियम की योजना में उपर्युक्त परीक्षणों को लागू करते हुए, हम पाते हैं कि अधिनियम के तहत, केंद्रीय आयोग एक

निर्णय लेने के साथ-साथ विनियमन करने का अधिकार,

एक साथ। धारा 79 केंद्र के कार्यों का वर्णन करती है।

आयोग को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है-अनिवार्य कार्य

और सलाहकार कार्य। प्रशुल्क विनियमन, अनुज्ञप्ति (अंतर-राज्य व्यापार अनुज्ञप्ति सहित), उत्पादन करने वाली कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों से जुड़े विवादों पर निर्णय शीर्ष के अंतर्गत आते हैं।

" राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देते समय अनिवार्य कार्य होंगे।

"सलाहकार कार्य" शीर्ष के अंतर्गत आता है। इस मायने में, केंद्रीय आयोग निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। धारा 79 (1) के तहत ऐसा निर्णय लेना विनियम बनाने पर निर्भर नहीं है।

केंद्रीय आयोग द्वारा धारा 178 के तहत। इसलिए, धारा 79 में उल्लिखित केंद्रीय आयोग के कार्य अलग-अलग हैं।

और केंद्रीय आयोग के कार्यों से अलग धारा 178। पूर्ववर्ती प्रशासनिक/न्यायिक कार्य हैं।

जबकि बाद वाले विधायी हैं।

55. विनियमन एक ऐसी कवायद है जो विनियम बनाने से अलग है। हालांकि, धारा 178 के तहत एक विनियमन बनाना केंद्रीय आयोग के लिए धारा 79 (1) के तहत कोई कदम/उपाय करने की पूर्व शर्त नहीं है। जैसा कि कहा गया है, यदि कोई विनियमन है, तो धारा 79 (1) के तहत उपाय धारा 178 के तहत ऐसे विनियमन के अनुरूप होना चाहिए। यह सिद्धांत

इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से प्रवाहित होता है जो हमारे पास हैं

इसके बाद चर्चा की गई। उदाहरण के लिए, धारा 79 (1) (जी) के तहत केंद्रीय आयोग को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए शुल्क लगाने की आवश्यकता है - 2003 का अधिनियम। धारा 178 के तहत विनियमन के अभाव में भी नियामक शुल्क लगाने का आदेश पारित किया जा सकता है। यदि शुल्क अनुचित है, तो यह धारा 111 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष चुनौती का विषय हो सकता है क्योंकि शुल्क एक आदेश/निर्णय लेने की प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। धारा 178 के तहत विनियमन बनाना [2023] 8 एस. सी. आर. लगाने वाले आदेश को पारित करने की पूर्व शर्त नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 79 (1) (जी) के तहत नियामक शुल्क। हालांकि, अगर उस संबंध में धारा 178 के तहत कोई विनियमन है तो धारा 79 (1) (जी) के तहत शुल्क लगाने का आदेश ऐसे विनियमन के अनुरूप होना चाहिए।

(95) हम यह देखने में असमर्थ हैं कि उक्त निर्णय पहले प्रतिवादी के मामले को कैसे आगे बढ़ा सकता है। जिस प्रश्न पर विचार किया जाना था और जो राय दी गई है, वह किसी भी तरह से हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग नहीं है। काफी हद तक, यह माना गया था कि विनियमन बनाना विनियामक शुल्क लगाने के लिए एक पूर्व शर्त नहीं थी धारा 79 (1) (छ)। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयोग का एक न्यायिक कार्य है। इसे राय देने का भी अधिकार है। विनियम बनाने की शक्ति इंगित करती है कि इसके पास विधायी शक्तियाँ भी हैं। मुद्दा यह है कि चूंकि इस मामले में हम आयोग के न्यायिक कार्य से संबंधित हैं, इसलिए हम उन ट्रामेलेओं से संबंधित हैं जिनके लिए यह अनुबंध की स्पष्ट शर्तों के रूप में है। हम जो कुछ भी धारण कर रहे हैं वह यह है कि

मामला जहां मामला अनुबंध की स्पष्ट शर्तों द्वारा शासित होता है, यह आयोग के लिए अनुबंध की स्पष्ट शर्तों से परे जाने के लिए एक नियामक निकाय की आड़ में भी खुला नहीं हो सकता है। यह उचित है कि हम देखते हैं कि पैरा 58 इस प्रकार है:

" 58. अधिनियम की धारा 178 के तहत व्यापार मार्जिन को सीमित करने के मामले में एक विनियमन क्यों बनाया गया है, इसका कारण समझना चाहिए। एक व्यापार मार्जिन तय करने के बजाय (कैपिंग सहित)

मामला-दर-मामला आधार पर, केंद्रीय आयोग ने एक ऐसा विनियमन बनाना उचित समझा जो 2003 के अधिनियम के तहत पहली बार मान्यता प्राप्त संपूर्ण व्यापारिक गतिविधि के लिए एक सामान्य अनुप्रयोग हो। इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 178 के तहत एक विनियमन बनाना आवश्यक हो गया क्योंकि धारा 178 के तहत बनाए गए विनियमन का विनियमित संस्थाओं के बीच मौजूदा संविदात्मक संबंध में हस्तक्षेप करने और उसे खत्म करने का प्रभाव पड़ता है। धारा 178 के तहत एक विनियमन एक अधीनस्थ विधान की प्रकृति में है। इस तरह के अधीनस्थ कानून भी कर सकते हैं

बिजली खरीद सहित मौजूदा अनुबंधों को हटा दें।

ऐसे समझौते जिन्हें धारा 178 के तहत विनियमों के साथ जोड़ा जाना है और जिन्हें धारा 178 के तहत केंद्रीय आयोग के आदेश द्वारा पूरे बोर्ड में नहीं किया जा सकता था

79 (1) (जे)। "

(96) जबकि यह अपने हरियाणा पावर खरीद केंद्र V के दौरान किसी पक्ष को अपने संविदात्मक दायित्वों से बाहर निकालने के लिए एक विनियमन के लिए खुला हो सकता है जैसा कि उसमें संकेत दिया गया है।

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

न्यायनिर्णायक शक्ति आयोग के लिए इसका उपयोग करके खुली नहीं हो सकती है

अनुबंध की शर्तों की अवहेलना करने के लिए इस शक्ति को हड़पने के लिए नामकरण विनियमन।

(97) एक अन्य तर्क जो पहले प्रतिवादी की ओर से उठाया गया है, वह यह है कि दिशानिर्देश 19.01.2005 पर बनाए गए थे। हालाँकि, पी. पी. ए. में प्रवेश करने से पहले और आर. एफ. पी. से पहले भी खंड 4.7 और 5.17 को संशोधित किया गया था और इसलिए, पी. पी. ए. और अनुच्छेद 17.3 को व्यापक रूप से लागू किया गया है।

(98) हम पहले ही अनुच्छेद 17.3 का अध्ययन कर चुके हैं। 1 . अनुच्छेद 17.3 शुरू में विशिष्ट उदाहरणों की बात करता है जो विवाद समाधान को गति दे सकते हैं।

तंत्र। एक मामला बिंदु में और तथ्यों के करीब एक विवाद है जो कानून में परिवर्तन से उत्पन्न होता है, जब एक दावे को अस्वीकार कर दिया जाता है और निपटान के माध्यम से समाधान नहीं किया जाता है। अन्य विशिष्ट खंड हैं जो पी. पी. ए. का हिस्सा हैं जिन्हें अनुच्छेद 17.3 के बाद के भाग में जोड़ा गया है। 1 . इसलिए, प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि अनुच्छेद 17 के प्रारंभिक शब्द। 1 इस मामले के तथ्यों द्वारा दर्शाए जाने जैसी स्थितियों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से डिज़ाइन किए गए हैं। दूसरे शब्दों में, भले ही ऐसी स्थिति अनुच्छेद 13.1 द्वारा शासित न हो, ताकि विक्रेता को उचित प्रतिफल का आश्वासन देने वाले आजीवन विनियमन की ओर ले जाने वाले प्रतिस्थापन सिद्धांत या अपूर्ण अनुबंध के सिद्धांत का पालन किया जा सके, दरों पर पुनर्विचार करने की शक्ति वही है जिस पर संशोधित दिशानिर्देश में विचार किया गया है जो इसमें निहित है -

अनुच्छेद 17.3। 1 . , यह प्रतिवाद किया जाता है।

(99) वास्तव में, जब हम पी. पी. ए. को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि उन मामलों के अलावा जो अनुच्छेद 17.3 में स्पष्ट रूप से संदर्भित हैं। 1 , अर्थात् , लेख

4.7. 1 , अनुच्छेद 13.2, अनुच्छेद 18.1 या खंड 10.1। 3 पी. पी. ए. में अनुसूची 17 के अन्य अनुच्छेद भी हैं जिनके साथ अनुच्छेद 17.3 है। 1 के साथ संबंध बना सकते हैं। इनमें स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 4.5 शामिल हैं। 2 , 11.6. 6 और 11.6। 7 . यह 12.7 (ई) के अलावा है जो फोर्स मैजेयर के तहत दावों के प्रवर्तन से संबंधित है। इसलिए, यह अनुच्छेद 17.3 जैसा नहीं है। 1 अनुबंध के अन्य भागों के संदर्भ के बिना इसे नहीं समझा जाना चाहिए। किसी भी न्यायालय को अनुबंध के किसी भी हिस्से को अलग से पढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम जिस प्रकृति के अनुबंध से निपट रहे हैं, उसका मसौदा तैयार करने वाले ने उस अनुबंध को सद्भाव और देखभाल की भावना के साथ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। इसलिए, हम प्रथम प्रतिवादी के इस तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं कि आयोग, न्यायाधिकरण और इस न्यायालय को अनुच्छेद 17.3 के शुरुआती शब्दों में अर्थ डालना चाहिए। 1 ताकि तथ्यों में, पहला प्रतिवादी इस आधार पर मुआवजे का दावा कर सके कि उसने पहली डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. रिपोर्ट पर कार्य करते हुए खर्च किया है।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(100) यहाँ, हमें अंत में ध्यान देना चाहिए, कि काफी हद तक, दावा

जल ग्रहण प्रणाली के संबंध में पहली डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. रिपोर्ट और दूसरी डब्ल्यू. ए. पी. सी. ओ. एस. के बल पर निर्भरता स्थापित की गई थी। रिपोर्ट करें।

(101) हम निम्नलिखित से अपने विचार में सुदृढीकरण भी पाते हैं।

खंड 1.2.12:

क्या इसके कुछ हिस्सों के बीच या उनके बीच कोई विसंगति है समझौता, उनकी व्याख्या एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से की जाएगी ताकि

प्रत्येक भाग को प्रभाव देने के लिए।

" "

(जोर दिया

गया)

(102) श्री अमित कपूर ने एक तर्क दिया कि अनुबंध

इस मामले में कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम नियम के सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता है।

(103) हमारा विचार है कि विरोध का सिद्धांत

इसका उपयोग आम तौर पर बीमा अनुबंधों और मानक रूप अनुबंधों में किया जाता है।

(104) स्पष्ट रूप से सार में विरोधी प्रस्ताव का सिद्धांत

यह है कि इसकी शर्तों में किसी भी संदेह के मामले में, अनुबंध का मसौदा तैयार करने वाले पक्ष के खिलाफ संदेह का समाधान किया जाना चाहिए। हम इस मामले के तथ्यों में यह नहीं सोचेंगे कि प्रथम प्रतिवादी उन खंडों के संबंध में कोई गंभीर संदेह पैदा करने में सक्षम रहा है जिनके साथ हम उसी की सही समझ पर चिंतित हैं।

(105) दूसरी शिकायत-कार्यालय ज्ञापन दिनांकित

17.06.2011 .

जहाँ तक ओ. एम. दिनांक 17.06.2011 से संबंधित प्रश्न का संबंध है।

कानून के दावे में परिवर्तन के लिए आधार प्रदान करना संबंधित है, हम

उनका विचार है कि दावे में योग्यता नहीं हो सकती है। यह सच है।

वह अनुच्छेद 13.1। 1 अन्य बातों के साथ यह प्रावधान है कि बदलाव लाया जा सकता है।

एक भारतीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बारे में

प्राधिकरण। किसी भी भारतीय द्वारा किसी भी कानून की व्याख्या में परिवर्तन सरकारी साधन अन्य बातों के साथ-साथ बशर्ते कि यह अंतिम हो।

ऐसी व्याख्या के लिए कानून के तहत प्राधिकरण का गठन होगा

भारतीय सरकारी साधन को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है: -
" भारतीय सरकारी साधन "का अर्थ है भारत सरकार,

उन राज्यों की सरकार जहां खरीददार और परियोजना स्थित हैं, हरियाणा बिजली खरीद केंद्र

V.

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

और भारत सरकार द्वारा नियंत्रित कोई मंत्रालय या विभाग या बोर्ड, एजेंसी या अन्य नियामक
या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण या
राज्यों की सरकार जहाँ खरीददार और परियोजना स्थित हैं

और इसमें उपयुक्त आयोग भी शामिल है।

(106) पी. पी. ए. में परिभाषित कानून इस प्रकार है:

" "कानून" का अर्थ है, इस समझौते के संबंध में, भारत में लागू बिजली कानूनों और किसी भी कानून, अध्यादेश सहित सभी कानून,

किसी भी भारतीय सरकारी साधन द्वारा विनियमन, अधिसूचना या संहिता, नियम या उनमें से किसी की भी कोई व्याख्या और कानून का बल रखने वाले और आगे सभी लागू नियम शामिल होंगे,

एक भारतीय द्वारा नियम, आदेश, अधिसूचनाएँ

उनमें से किसी के अनुसार या उसके तहत सरकारी साधन और इसमें सभी नियम, विनियम, निर्णय और आदेश शामिल होंगे।

उपयुक्त आयोग;

(107) जबकि 'सक्षम न्यायालय' शब्द जो किसी भी कानून की व्याख्या में परिवर्तन का स्रोत भी हो सकता है, को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है

अनुच्छेद 13.1। 1 . , जब भारत सरकार के अंतिम प्राधिकरण की बात आती है, तो पी. पी. ए. में कोई परिभाषा नहीं है। विवाद यही है।

(108) प्रथम प्रतिवादी ने कथित रूप से इस उद्देश्य के लिए वस्तुओं का आयात किया

कैप्टिव खनन संयंत्र का निर्माण। यह मामला है कि इस तरह से आयातित वस्तुओं का उपयोग खनन संयंत्र के निर्माण के लिए किया जा रहा था जो

इसका उपयोग अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट परियोजना के निर्माण और संचालन के लिए किया गया था। प्रथम प्रत्यर्थी के अनुसार इस तरह के सामान को क्षेत्र धारण करने वाली अधिसूचना के आधार पर सीमा शुल्क से स्पष्ट रूप से छूट दी गई थी। जिन अधिसूचनाओं को क्षेत्र में रखा गया है, उन्हें समझा जाना चाहिए, वे अधिसूचनाएं थीं जो कट ऑफ तिथि से पहले क्षेत्र में रखी गई थीं। निश्चित रूप से कट ऑफ तिथि 21.07.2007 है। दूसरे शब्दों में, उक्त तिथि वह तिथि है जो बोली की समय सीमा से सात दिन पहले है। ओ. एम. जो तर्क का आधार है, निदेशक द्वारा बिना किसी संदेह के जारी किया गया है।

विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव की मंजूरी। वह इस प्रकार है:

" संख्या 12/20/2009-यू. एम. पी. पी.

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नई दिल्ली, 17 जून, 2011

कार्यालय स्मारक

उप: 3960 एम. डब्ल्यू. सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, जिला। सिंगरौली-परियोजना
आयात-विनियमन के तहत सीमा शुल्क से छूट।

अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति को सरकार को संदर्भित करने का निर्देश दिया जाता है। इस विषय पर
मध्य प्रदेश का पत्र सं. 4468/13/2011 01 दिनांक 24.05.2011

केवल उपकरण।

यह बिजली मंत्रालय के संयुक्त सचिव (तापीय) की मंजूरी से जारी किया गया है।

(ए. ए. तज़ीर)

निर्देशक

श्री मोहम्मद। सुलेमान

सचिव (ऊर्जा)

सरकार. मध्य प्रदेश के,

भोपाल "

(109) यह प्रथम प्रतिवादी का तर्क है कि जब वह माल का आयात करता था तो उसे उसी पर सीमा
शुल्क का भुगतान करना पड़ता था और यह

(110) दूसरे शब्दों में, कानून के विपरीत, जैसा कि यह कट ऑफ तिथि से पहले था, संयुक्त सचिव द्वारा
ओ. एम. जारी करके विद्युत मंत्रालय, कानून की व्याख्या में बदलाव लाया गया है। यह अनुच्छेद
13.1 के अर्थ के भीतर कानून में परिवर्तन के दावे को खोजने के लिए पर्याप्त था। 1

(111) दूसरी ओर, खरीददारों का तर्क है, जैसा कि हमने देखा है कि ओ. एम. को एक द्वारा जारी नहीं
किया जा सकता है

सरकारी साधन जिसे ऐसी व्याख्या के लिए कानून के तहत अंतिम प्राधिकरण के रूप में माना जा सकता है।
यही कारण है कि छूट देने वाली अधिसूचना सीमा शुल्क अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा जारी की गई है
और बिजली मंत्रालय में संयुक्त सचिव ऐसा प्राधिकरण नहीं है। दूसरा, यह खरीददारों का तर्क है कि इस
मामले को उपयुक्त मंच के समक्ष पहले द्वारा लिया जाना चाहिए था। प्रत्यर्थी इस आधार पर कि
कानून में, वास्तव में, वस्तुओं का आयात हरियाणा पावर खरीद केंद्र V था।

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

छूट दी गई है यदि इसे छूट दी गई थी और यह पहले प्रतिवादी के लिए कानून का सहारा लिए बिना बोझ उठाने के लिए खुला नहीं था। तीसरा, यह तर्क दिया जाता है कि मामले का तथ्य यह है कि कटौती की तारीख से पहले भी स्थिति यह थी कि विचाराधीन वस्तुओं को छूट नहीं दी गई थी।

अधिसूचनाएँ और उसी के साथ निपटा गया हालांकि अधिकार के संदर्भ में मेगा बिजली संयंत्र में छूट लेकिन अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना के लिए नहीं। लेकिन हमारा मानना है कि जहां तक अधिसूचनाओं का इतिहास है, यह प्रासंगिक बना रहेगा:

" 7.1 वर्तमान प्रविष्टि के अनुरूप प्रविष्टि पहली बार 1999 में शुरू की गई थी। जैसा कि आवेदक के विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया, सीमा शुल्क अधिसूचना में इस प्रविष्टि की शुरूआत केंद्र सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय का अनुसरण प्रतीत होती है जैसा कि सचिव, बिजली मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांकित संचार में निर्धारित किया गया है और 1998 में जारी मेगा बिजली परियोजनाओं से संबंधित संशोधित नीति/दिशानिर्देश। 1995 में बनाई गई नीति "क्षमता के बिजली संयंत्रों की स्थापना" के संबंध में थी।

एक से अधिक राज्यों को 1000 मेगावाट या उससे अधिक बिजली की आपूर्ति। उस नीति दस्तावेज में, यह कहा गया है कि "1000 मेगावाट और उससे अधिक की क्षमता और एक से अधिक राज्यों को बिजली आपूर्ति की परियोजना को एक बड़ी परियोजना माना जाना चाहिए। जो परियोजनाएं किसी एक राज्य को बिजली प्रदान करती हैं, चाहे उनका आकार कुछ भी हो, वे इसके अंतर्गत नहीं आएंगी।

यह श्रेणी "। 1998 में जिस नीति का पुनर्गठन किया गया था, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि अंतर-राज्य और अंतर-क्षेत्रीय बड़ी बिजली परियोजनाएं

सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में स्थापित किए जाने थे। नीति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के पुनर्गठन की भी परिकल्पना की गई थी। इस नीति में लाभार्थी राज्यों को शुल्क तय करने की शक्तियों के साथ नियामक आयोगों का गठन करने पर विचार किया गया है। दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 5 महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि "इन परियोजनाओं के लिए पूंजीगत उपकरणों का आयात सीमा शुल्क से मुक्त होगा"। यह सुनिश्चित करने के लिए कि घरेलू बोलीदाता प्रतिकूल न हों

प्रभावित, कुछ सुरक्षा उपायों को लिखा गया था।

7.2 प्रविष्टि/SI.No। Ch का 288A। 98.01 अधिसूचना संख्या 63/1999 द्वारा अंतःस्थापित, 1998 की संशोधित नीति के साथ पठित 1995 की नीति को काफी हद तक प्रभावी बनाता है। मेगा बिजली परियोजना की एक ही अवधारणा

उस प्रविष्टि में पाया जाना है। प्रविष्टि में लिखा है:

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शर्त

मानक

अतिरिक्त

एस. एल. नहीं।

अध्याय /

वस्तुओं का विवरण

शीर्षक/उप-शीर्ष

शुल्क दर

नहीं।

दर

नहीं।

शून्य सेट करने के लिए आवश्यक सामान

नील

288 ए.

9801

82

किसी भी मेगा पावर से ऊपर

सूची 33 में निर्दिष्ट परियोजना,

अगर ऐसी मेगा पावर परियोजना है

ए। एक अंतर-राज्य तापीय

क्षमता का विद्युत संयंत्र

1500 मेगावाट या उससे अधिक; या

बी। अंतर-राज्यीय पनबिजली

क्षमता का विद्युत संयंत्र

500 एम. डब्ल्यू. या अधिक।

शर्त संख्या 82 इस प्रकार है: -

82. (क) यदि कोई अधिकारी संयुक्त सचिव के पद से कम नहीं है

विद्युत मंत्रालय में भारत सरकार प्रमाणित करती है कि
(i) बिजली खरीद राज्य, सिद्धांत रूप में, निजीकरण का कार्य करता है।

उस राज्य के सभी शहरों में वितरण, जिनमें से प्रत्येक में एक

द्वारा निर्धारित की जाने वाली अवधि के भीतर दस लाख से अधिक की जनसंख्या

विद्युत मंत्रालय; और

((ii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा आयात के मामले में,

मात्रा, कुल मूल्य, विवरण और विनिर्देश

आयातित वस्तुओं को अध्यक्ष और प्रबंधकों द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

" 7.3 सूची 33 तापीय परियोजनाओं और पनबिजली के नाम से निर्दिष्ट करती है।
जिन परियोजनाओं के संबंध में छूट लागू की जाती है। फिर,

सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 99 की 100 दिनांक 28/7/99 के तहत,

पहले की अधिसूचना में निर्दिष्ट ताप विद्युत परियोजना की क्षमता

इसे 1500 मेगावाट से बदलकर 1000 मेगावाट कर दिया गया। इस अधिसूचना के
परिणामस्वरूप,

7 सूची में और अधिक तापीय परियोजनाओं को जोड़ा गया।

" 7.4 फिर, लगातार अगली अधिसूचनाएँ सीमा शुल्क हैं।

2000 की अधिसूचना संख्या 16 और 2001 की अधिसूचना संख्या 17 जो काफी हद तक
तापीय और पनबिजली परियोजनाओं की संख्या को छोड़कर

सूची 33 में निर्दिष्ट नीचे चला गया है।

" 7.5 इसके बाद 2002 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 21 आती है।

01.03.2002 जो हमारे उद्देश्य के लिए सामग्री है। वह इस प्रकार है:

रयान पावर खरीद केंद्र V. ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

3 . अध्याय /

मानक अतिरिक्त शर्त	
वस्तुओं का विवरण	
शीर्षक/उप-शीर्ष	शुल्क दर सं।
	दर
नहीं।	
स्थापना के लिए आवश्यक वस्तुएँ	
9801	नील
	नील
	86
परियोजना है	अगर ऐसी मेगा पावर है
ए। एक अंतर-राज्य तापीय	
एक क्षमता का बिजली संयंत्र	बी। अंतर-राज्यीय पनबिजली
ए के पद से नीचे नहीं	एक अधिकारी द्वारा प्रमाणित
संयुक्त सचिव	
भारत सरकार में	
विद्युत मंत्रालय	

" 7.6 प्रविष्टि 400 को अधिसूचना संख्या 26/2003 द्वारा संशोधित किया गया था।

नीतिगत निर्णय के कारण सहायता संशोधन की आवश्यकता थी

सरकार द्वारा जैसा कि केंद्रीय बजट भाषण में परिलक्षित होता है

04. हिलाये हुए भाषण से निम्नलिखित उद्धरण प्रासंगिक है:

" शक्ति में सुधार पर जोर देने के साथ ही

वितरण, क्षमता वृद्धि पर हमारा ध्यान बना रहता है। द.
बिजली परियोजनाओं को अधिसूचित किया था।

सरकार ने इससे पहले 1999 में 18

मेगा परियोजनाएं, उन्हें विभिन्न कर्तव्य और लाइसेंस प्रदान करना

लाभ होता है। सरकार अब मेगा को उदार बनाने का प्रस्ताव करती है

इन सभी लाभों को किसी भी व्यक्ति तक विस्तारित करके बिजली परियोजना नीति आगे बढ़ेगी।

बिजली परियोजना जो पहले से निर्धारित शर्तों को पूरा करती है

मेगा बिजली परियोजनाएं "।

उपरोक्त नीति के अनुसार, अधिसूचना संख्या 26/2003-क्यूएस। था।

अधिसूचना संख्या में संशोधन करते हुए जारी किया गया। 21 / 2002 - कुस। प्रविष्टि 400 के रूप में
संशोधित में लिखा है:

नील

9801

आवश्यक वस्तुएं

86

नील

कहो -

ए। एक अंतर-राज्य तापीय

एक क्षमता का बिजली संयंत्र

1000 मेगावाट या उससे अधिक; या

एक क्षमता का बिजली संयंत्र

से

500 एम. डब्ल्यू

या

एक अधिकारी द्वारा प्रमाणित

ए के पद से नीचे नहीं

संयुक्त सचिव

भारत सरकार में

विद्युत मंत्रालय "[2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिजली की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी किए गए संशोधित नीति दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए और संशोधन किया गया जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में परियोजनाएं। प्रविष्टि 399

1999 के बाद से काफी हद तक वही रहा, सिवाय इसके कि

कि एस. एल. में परिवर्तन हुआ था। नहीं. और दर "।

(113) अग्रिम निर्णय प्राधिकरण का आदेश दिनांकित है

19.12.2008 . इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कट ऑफ डेट के बाद है। प्रथम प्रत्यर्थी का मामला अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के आदेश पर आधारित नहीं है। प्रथम प्रत्यर्थी का मामला विशेष रूप से केवल विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव द्वारा जारी ओ. एम. पर आधारित है। हम देख सकते हैं कि अधिसूचना के संदर्भ में विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव की भूमिका है। उन्हें सौंपी गई भूमिका अधिसूचना 63/1999 की शर्त 82 में निहित है और यह शर्त उसके बाद भी जारी रही है। जैसा कि हमने देखा है कि शर्त यह है कि यह कहा गया है कि संयुक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी को उन पहलुओं को प्रमाणित करना है जो शर्त 82 में उल्लिखित हैं।

(114) वास्तव में, विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव को सरकारी प्राधिकरण के रूप में वर्णित करना मुश्किल है जो अंतिम है।

कानून के तहत प्राधिकरण। कानून के तहत अंतिम प्राधिकरण सीमा शुल्क अधिनियम के तहत प्राधिकरण होगा जो छूट अधिसूचना जारी करता है। लेकिन हम अपने निष्कर्षों को उक्त आधार पर नहीं रखना चाहेंगे क्योंकि हमें लगता है कि खरीदारों की आपत्ति निश्चित आधार पर हो सकती है। पहला प्रत्यर्थी भी बिना किसी संदेह के 26.05.2006 दिनांकित अधिसूचना पर निर्भर करता है, जिसमें इसे निम्नानुसार इंगित किया गया है:

" अधिसूचना No.49/2006-सीमा शुल्क

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त गरीबों का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है,

इसलिए, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं -

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना No.21/2002-सीमा शुल्क, दिनांक 1

मार्च, 2002, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ए. एन. ए. पावर खरीद केंद्र v.

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]असाधारण वीडियो संख्या जी. एस. आर. 118 (ई), दिनांक 1 मार्च,

002 , अर्थात्:

(I) तालिका में, S.No.400 के विपरीत, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए,

निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: " किसी भी वृहद विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए आवश्यक वस्तुएँ, जो संयुक्त सचिव के पद से कम के अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं हैं -

विद्युत मंत्रालय में भारत सरकार, अर्थात्

कहो (क) जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में स्थित 700 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता का अंतर-राज्यीय ताप विद्युत संयंत्र,

नागालैंड और त्रिपुरा, या

ऊपर; या (ग) जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में स्थित 350 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता का अंतर-राज्यीय पनबिजली संयंत्र।

नागालैंड और त्रिपुरा, या

(घ) खंड में निर्दिष्ट राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में स्थित 500 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता का अंतर-राज्यीय पनबिजली संयंत्र।

(ग) ऊपर ",

(II) उपखंडों के लिए अनुलग्नक में, शर्त No.86 में (ii) खंड (ए) के और (iii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

" ((ii) बिजली खरीद राज्य, सैद्धांतिक रूप से, उस राज्य के सभी शहरों में वितरण का निजीकरण करता है, जिनमें से प्रत्येक की आबादी दस लाख से अधिक है। बिजली मंत्रालय द्वारा तय किया गया "।

15) वस्तुतः न्यायाधिकरण ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि -

प्रश्न विद्युत परियोजनाओं से संबंधित प्रविष्टि 400 के अंतर्गत आएगा।

इसलिए, उन्हें छूट दी गई थी। न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि संयुक्त सचिव द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.06.2011

घ एक ऐसी व्याख्या के लिए जो कानून में परिवर्तन का गठन करती है।

16) हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। अधिसूचना [2023] 8 एस. सी. आर. के अलावा कोई सामग्री नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह इंगित करने के लिए कि विचाराधीन माल को कटौती की तारीख से पहले छूट के रूप में माना जा रहा था। दूसरे शब्दों में, यह पहले प्रतिवादी पर यह स्थापित करने के लिए निर्विवाद सामग्री का उत्पादन करने का दायित्व था कि माल को छूट दी गई थी

और कट ऑफ डेट से पहले ऐसा इलाज किया जा रहा था। सबसे अच्छी सामग्री ऐसे मामलों के उदाहरण होते जहां माल को छूट के रूप में माना जा रहा था। भले ही, यह बताया गया है कि पहला उत्तरदाता एकमात्र अल्ट्रा मेगा बिजली संयंत्र था, फिर भी मेगा बिजली संयंत्रों सहित बिजली संयंत्र चालू थे। यह कल्पना करना मुश्किल है कि वहाँ ऐसा एक भी मामला नहीं होगा जहां अन्य बिजली परियोजनाओं के उदाहरणों के माध्यम से समान निवेश, भले ही यह अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाएं न हों, पहले उत्तरदाता के लिए संचालित नहीं होतीं।

(117) कानून शब्द को परिभाषित किया गया है जैसा कि हमने देखा है। जबकि अभिव्यक्ति 'भारतीय सरकारी उपकरण' का उपयोग किया जाता है

अनुच्छेद 13.1 में विधि शब्द की परिभाषा। 1 , व्याख्या में परिवर्तन

भारतीय सरकारी प्राधिकरण द्वारा किसी भी कानून की इस तरह की व्याख्या के लिए कानून के तहत अंतिम प्राधिकरण होना चाहिए। विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव को भारतीय सरकारी प्राधिकरण की स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराना मुश्किल हो सकता है, जिसके पास कानून के तहत अंतिम अधिकार है। लेकिन जैसा कि हमने संकेत दिया है कि इसे उस आधार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जिसके आधार पर हम न्यायाधिकरण से असहमत हैं।

(118) ओ. एम. का अवलोकन एक अन्य अच्छे कारण के लिए पहले प्रतिवादी के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है। ओ. एम. में नहि छथि।

यह इंगित करता है कि विचाराधीन माल को कटौती की तारीख से पहले छूट दी गई थी और यह कि कटौती की तारीख के बाद की तारीख को माल शुल्क के लिए उपयुक्त हो गया था। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की है कि जिस प्रकार के सामान से हम संबंधित हैं, वे छूट के लिए योग्य नहीं हो सकते हैं। अपीलार्थियों का एक मामला है कि वास्तव में, संयुक्त सचिव अनिवार्य रूप से अग्रिम निर्णय का पालन कर रहे थे। जबकि यह सच है कि

अग्रिम निर्णय प्रथम प्रत्यर्थी को बाध्य नहीं कर सकता है क्योंकि वह एक पक्ष नहीं है, और प्रत्यर्थी कानून के तहत निर्णय की मांग नहीं कर सकता था, यह है निस्संदेह एक ऐसा पहलू जो अन्यथा अपीलार्थियों के मामले में ताकत जोड़ता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां बाद की अधिसूचना या उक्त कटौती की तारीख के बाद जारी की गई व्याख्या के साथ-साथ कटौती की तारीख से पहले क्षेत्र को धारण करने वाली अधिसूचना को रखते हुए, आयोग या एक न्यायाधिकरण यह पा सकता है कि कानून में परिवर्तन हुआ है, जिससे विक्रेता की लागत में वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, जब पहले प्रत्यर्थी के मामले में अधिसूचना की शर्तों की व्याख्या शामिल है, तो विशेष रूप से जब दो विचार निकाय के समक्ष स्वीकृति के लिए उचित रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, हरियाणा पावर खरीद केंद्र V.

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

सबसे अच्छा, हम सोचेंगे कि न्यायाधिकरण ने यह पता लगाने के लिए एक खतरनाक रास्ता अपनाने का जोखिम उठाया है कि संयुक्त सचिव द्वारा जारी ओ. एम. ने कानून में बदलाव का गठन किया है। हालाँकि इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है जो मनोहर लाल शर्मा बनाम में रिपोर्ट किया गया है। प्रधान सचिव और अन्य। (2014) 9 एस. सी. सी. 516 और मनोहर लाल शर्मा बनाम

प्रधान सचिव और अन्य। (2014) 9 एस. सी. सी. 614 जिन निर्णयों का उद्देश्य खनन पट्टों को छूट देना था, जो विशेष रूप से विचाराधीन बिजली परियोजनाओं सहित बिजली परियोजनाओं के उद्देश्य के लिए संचालित कैप्टिव पट्टे थे, वे अपने निर्णय के दायरे से इस सवाल को निर्धारित कर सकते हैं कि क्या कैप्टिव खनन संयंत्र के उद्देश्य से आयात की गई वस्तुओं को कभी छूट दी गई थी। बिजली परियोजना के उद्देश्य से आयातित वस्तुओं को छूट दी गई थी। दूसरे शब्दों में, कि क्या विचाराधीन माल ऐसी वस्तुएँ थीं जो एक प्रविष्टि के भीतर आती थीं या दूसरी, इस मामले में एक ऐसा मामला है जो अत्यधिक विवादित है और प्रथम प्रतिवादी का आधार है। , संयुक्त सचिव के ओ. एम. को ऐसा दावा करने के लिए एक ठोस आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(119) पार्टियों ने वास्तव में एक परियोजना का निर्माण और संचालन करने पर विचार किया। हम पाते हैं कि 'परियोजना' शब्द का उपयोग अनुबंध के कई खंडों में किया गया है। 'परियोजना' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" " " " "परियोजना" का अर्थ है बिजली स्टेशन और बंदी कोयला खदान (ओं) जो डिजाइन, वित्तपोषण, इंजीनियरिंग, खरीद के लिए शुरू की गई है।

विक्रेता द्वारा निर्माण, संचालन, रखरखाव, मरम्मत, नवीनीकरण, विकास और बीमा इस समझौते के नियम और शर्तें; "

(120) चूंकि 'पावर स्टेशन' शब्द का उपयोग 'परियोजना' शब्द में किया गया है, इसलिए यह उचित है कि हम शब्दों की परिभाषा का विज्ञापन करें। ' पावर स्टेशन ':

" पावर स्टेशन "का अर्थ है:

(क) कोयले से चलने वाली बिजली उत्पादन सुविधा जिसमें कोई भी या सभी इकाइयाँ शामिल हों;

(ख) किसी भी संबद्ध ईंधन हैंडलिंग, उपचार या भंडारण सुविधाओं

(ग) ऊपर निर्दिष्ट विद्युत उत्पादन सुविधा के संचालन के लिए आवश्यक कोई जल आपूर्ति, उपचार या भंडारण सुविधा;

(घ) ऐश डाइक सहित ऐश निपटान प्रणाली; [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ई) कर्मचारी कॉलोनी के लिए टाउनशिप क्षेत्र; और
प्रणाली के लिए बे/एस

(च) बिजली के स्विचयार्ड में संचरण

स्टेशन,

(छ) अन्य सभी परिसंपत्तियाँ, भवन/संरचनाएँ, उपकरण, संयंत्र और मशीनरी, सुविधाएँ और संबंधित परिसंपत्तियाँ जो कुशलता के लिए आवश्यक हैं।

और बिजली उत्पादन सुविधा का आर्थिक संचालन;

चाहे वह पूरा हो गया हो या विकास के किसी भी चरण में हो और के अनुसार निर्माण या विकसित करने और निर्माण करने का इरादा

इस समझौते के प्रावधान "।

(121) चूंकि 'कैप्टिव कोयला खदान' शब्द को भी 'परियोजना' शब्द की परिभाषा का हिस्सा कहा गया है, इसलिए यह सही है कि हम

परिभाषा के अनुसार:

" बंदी कोयला खदानों का अर्थ है बंदी कोयला खदानें जैसा कि वर्णित है।

अनुसूची 1 ए और संबंधित ईंधन परिवहन प्रणाली में पावर स्टेशन; "

(122) ' परियोजना दस्तावेजों को फिर से परिभाषित किया गया है। हम 'विवेकपूर्ण उपयोगिता प्रथाओं' शब्दों की परिभाषा को देख सकते हैं:

" परियोजना दस्तावेज़ मतलब

क) निर्माण अनुबंध;

समझौता, यदि कोई हो; ग) ओ एंड एम अनुबंध;

घ) आर. एफ. पी. और आर. एफ. पी. परियोजना दस्तावेज; और ई) समय-समय पर लिखित रूप में नामित कोई अन्य समझौते

समय-समय पर, खरीदार और विक्रेता द्वारा संयुक्त रूप से; " विवेकपूर्ण उपयोगिता प्रथाओं का अर्थ है प्रथाएं, तरीके और

मानक जो आम तौर पर विद्युत उपयोगिताओं या कोयला खनन संस्थाओं द्वारा समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए जाते हैं

इसमें निर्दिष्ट प्रकार की कोयला खदानों और बिजली उत्पादन उपकरणों और खदानों का सुरक्षित, कुशल और आर्थिक डिजाइन, निर्माण, चालू करना, संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करना।

समझौता और कौन सी प्रथाएं, तरीके और मानक होंगे
आवश्यकतानुसार समायोजित, ध्यान में रखने के लिए:

हरियाणा पावर खरीद केंद्र V. ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

क) द्वारा अनुशंसित संचालन और रखरखाव दिशानिर्देश

संयंत्र और इसमें शामिल किए जाने वाले उपकरणों के निर्माता

परियोजना;

(ख) भारतीय कानून की आवश्यकताएँ; और

ग) स्थल पर भौतिक स्थितियाँ;

(123) हमने संबंधित अधिसूचनाओं का इतिहास निर्धारित किया है

विद्युत परियोजनाओं के लिए छूट प्रदान करना। यह सब वर्ष 1995 में जारी नीति के साथ शुरू हुआ। छूटों की अपनी उत्पत्ति थी

वर्ष 1999 में जारी अधिसूचना। इसके बाद अधिसूचना 21/2002 है जो 01.03.2002 पर जारी की गई थी। उक्त अधिसूचना में प्रविष्टि 400 इस प्रकार है:

एस. नं. वस्तुओं का अध्याय या विवरण

मानक अतिरिक्त शर्त

शीर्षक या उप

शुल्क दर

सं।

दर

शीर्षक

" स्थापना के लिए आवश्यक वस्तुएँ

नील

86

नील

किसी भी मेगा बिजली परियोजना, तो

एक अधिकारी द्वारा प्रमाणित जो नीचे नहीं है

संयुक्त सचिव का पद

बिजली मंत्रालय, अर्थात्

(a) एक अंतर-राज्य तापीय ऊर्जा

700 मेगावाट की क्षमता वाला संयंत्र या

राज्यों में स्थित अधिक

जम्मू और कश्मीर, सिक्किम,

अरुणाचल प्रदेश, असम,

मेघालय, मणिपुर, मिजोरम,

नागालैंड और त्रिपुरा; या

बी एक अंतर-राज्य ताप विद्युत संयंत्र

1000 मेगावाट या उससे अधिक की क्षमता का,

उन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में स्थित

ऊपर खंड (ए) में निर्दिष्ट; या

ग एक अंतर-राज्यीय पनबिजली संयंत्र

350 मेगावाट या उससे अधिक की क्षमता,

जम्मू राज्यों में स्थित है और

कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल

प्रदेश, असम, असम, मेघालय,

मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और

डी एक अंतर-राज्यीय पनबिजली संयंत्र

500 मेगावाट या उससे अधिक की क्षमता,

उन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में स्थित

उपरोक्त खंड (ग) में निर्दिष्ट; [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(124) इसके बाद एक और अधिसूचना-अधिसूचना संख्या 26 /

03 जिसने इसे अंतिम रूप दिया है, जारी किया गया है जिसे अग्रिम निर्णय प्राधिकरण द्वारा भी देखा गया है। वह इस प्रकार है:

स्थापना के लिए आवश्यक वस्तुएँ

9801

नील

400

नील

86

कोई भी मेगा बिजली परियोजना जो
कहने के लिए -

ए। एक अंतर-राज्य तापीय शक्ति

1000 मेगावाट क्षमता का संयंत्र

या अधिक; या

बी। अंतर-राज्यीय पनबिजली

500 मेगावाट की क्षमता वाला संयंत्र या

अधिक।

एक अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं

संयुक्त पद से नीचे

सरकार के सचिव

विद्युत मंत्रालय में भारत

(जोर दिया

गया)

(125) हम देख सकते हैं कि उक्त अधिसूचना जारी होने के साथ

जो बात सामने आती है वह निम्नलिखित है:

(126) जबकि प्रविष्टि के शुरुआती शब्दों में, रेफरी होता है

बिजली परियोजना के लिए, यह 'कहने के लिए है' शब्दों द्वारा वातानुकूलित है। हम इस आधार पर काफी सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकते हैं कि अधिसूचना संख्या 21/2002 में प्रविष्टि 400, जो अधिसूचना संख्या 01.03.2002 पर लागू हुई, जैसा कि अधिसूचना संख्या 46/2008 द्वारा संशोधित किया गया है, वह प्रविष्टि है जिसे कट ऑफ तिथि पर क्षेत्र धारण करने के रूप में माना जाना चाहिए। इसके बाद, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले प्रतिवादी ने 17.06.2011 पर जारी OM से प्रेरणा लेने की मांग करते हुए कानून खंड में परिवर्तन का आह्वान किया है।

(127) कानून खंड में परिवर्तन को स्पष्ट रूप से लागू करने की मांग की गई है

यह तर्क देते हुए कि भारतीय सरकारी प्राधिकरण द्वारा व्याख्या में बदलाव किया गया है, जो कानून के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेता है। न्यायालय के समक्ष जो बड़ा सवाल है वह यह है कि क्या सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जारी अधिसूचनाओं के तहत प्राप्त स्थिति के संदर्भ में सरकारी प्राधिकरण द्वारा 'व्याख्या में परिवर्तन' के संदर्भ में कानून में कोई बदलाव किया गया है। यहां तक कि पी. पी. ए. के जिन खंडों का हमने उल्लेख किया है, वे भी बिजली संयंत्र और कैप्टिव खदान के बीच अंतर बनाए रखते हैं। एक बिजली संयंत्र को बंदी खदान के समान नहीं माना जा सकता है। वास्तव में, अनुसूची 1 ए जो स्थल को परिभाषित करती है, आवंटित किए गए कोयला ब्लॉकों के संदर्भ में बंदी खदानों को संदर्भित करती है। कैप्टिव माइन की परिभाषा यह भी इंगित करती है कि यह हरियाणा पावर खरीद केंद्र V के रूप में कोयला खदानें हैं।

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

अनुसूची 1 ए में वर्णित और बिजली स्टेशन तक संबंधित ईंधन परिवहन प्रणाली। निस्संदेह, 'स्थल' शब्द को उस भूमि के रूप में भी परिभाषित किया गया है जिस पर परियोजना का विकास किया जाएगा जैसा कि अनुलग्नक में दिया गया है।

1 ए.

(128) निस्संदेह, एक कोयला खदान होने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो बिजली के संचालन के लिए आवश्यक ईंधन की आपूर्ति करना है

संयंत्र, भौगोलिक निकटता का एक निश्चित माप होगा। लेकिन इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए सवाल यह है कि क्या यह सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना की सामग्री के भाग्य का फैसला करेगा।

(129) हमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि पहला प्रतिवादी एकमात्र व्यक्ति है जिसे छूट के लाभ का दावा करने का अधिकार था इस आधार पर कि जिन वस्तुओं का आयात उनकी बंदी खदान के उद्देश्य से किया गया है, उन्हें बिजली परियोजना में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के रूप में माना जाना चाहिए। जैसा कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के क्रम में ली गई अधिसूचनाओं का इतिहास समय के साथ दिखाएगा, ऐसे कई बिजली संयंत्र हैं जो उभरे हैं। वे सभी बिजली पैदा करने के उद्देश्य से कैप्टिव खानों का भी उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा किए गए आयात पर छूट देने और इसके तहत छूट के लाभ का दावा करने के उदाहरणों की कमी होगी।

अधिसूचना। किसी अन्य को दी गई छूट का एक भी उदाहरण नहीं

परियोजना जहाँ कैप्टिव खदान में उपयोग के लिए आयातित माल किया गया है आयोग, न्यायाधिकरण या यहाँ तक कि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह पहले प्रतिवादी के इस दावे को नकारने के लिए एक लंबा रास्ता तय करता है कि जिसे कभी छूट दी गई थी, उसे केवल दिनांकित ओ. एम. 17.06.2011 जारी करने के आधार पर छूट नहीं दी गई है।

(130) एक और बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति है जो हमें प्रभावित करती है। जो सामग्री हमें आकर्षित करती है वह निस्संदेह में पाई जाती है

शासक प्राधिकरण। हम इस आधार पर आगे नहीं बढ़ सकते कि जिस विवाद के कारण निर्णय की मांग की गई और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अग्रिम निर्णय से पहले सीमा शुल्क प्राधिकरण का लगातार रुख प्राधिकरण इस बात पर प्रकाश नहीं डालेगा कि विभाग इस मामले को कैसे देखता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीमा शुल्क विभाग है जिसने छूट अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के लेखक होने के नाते, वे अधिसूचना [2023] 8 एस. सी. आर. की चौड़ाई और उद्देश्य को समझने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

छूट। उन्होंने आवेदन का कड़ा विरोध किया है और इसे रखा है

एक महत्वपूर्ण आधार जिसने, निस्संदेह, अग्रिम जी प्राधिकरण को भी अपील की है। यह एक ऐसा पहलू है जो यह दिखाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करता है कि सीमा शुल्क प्राधिकरण का दृष्टिकोण जिसे बोलने के तरीके से समकालीन स्थिति के रूप में देखा जा सकता है, इस न्यायालय द्वारा संपादित नहीं किया जाना चाहिए। (131) पहले उत्तरदाता ने मेगा बिजली परियोजनाओं से ईगार्ड में काफी निर्भरता की भी मांग की: संशोधित नीति दिशानिर्देश। एलिवेन्ट भाग इस प्रकार है:

" मेगा पावर परियोजनाएं: समीक्षा नीति

गाइड लाइन्स

विकासकर्ता द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।

वृहद परियोजना का दर्जा देने के लिए:

क) जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में स्थित 700 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता का अंतर-राज्यीय ताप विद्युत संयंत्र; या ख) खंड (क) में निर्दिष्ट राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में स्थित 1000 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता का अंतर-राज्यीय ताप विद्युत संयंत्र।

ऊपर; या

घ) खंड (ग) में निर्दिष्ट राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में स्थित 500 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता का अंतर-राज्यीय पनबिजली संयंत्र। ऊपर '।

मेगा बिजली परियोजनाओं के लिए उपलब्ध राजकोषीय रियायतें/लाभ

शून्य सीमा शुल्क: वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्या 21/2002-सीमा शुल्क दिनांक 18 मार्च, 2002-सीमा शुल्क संख्या 49/2006-सीमा शुल्क दिनांक 26 मई, 2006 में भारत सरकार की अधिसूचना के संदर्भ में. पूंजी का आयात

इन परियोजनाओं के लिए उपकरण सीमा शुल्क से मुक्त होंगे।

(132) अग्रिम निर्णय प्राधिकरण की समझ यह होनी चाहिए कि जहां तक हरियाणा शक्ति खरीद केंद्र V के तहत छूट की पात्रता है।

ससान पावर लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

अधिसूचना एक मेगा बिजली परियोजना से संबंधित है जिसे इस रूप में समझना होगा

यह 'कहने के लिए' शब्दों के बाद क्या होता है, उस तक सीमित है। दूसरे शब्दों में, हालांकि प्रविष्टि 400 में बिजली परियोजना शब्दों का उपयोग यह सुझाव देता प्रतीत होता है कि यह अपने दायरे में एक कैप्टिव खदान को अपनाने में सक्षम है जिससे बिजली संयंत्र को चलाने के लिए ईंधन उत्पन्न किया जाता है, जब प्रविष्टि 400 के वास्तविक लाभार्थी की बात आती है, तो अधिसूचना के निर्माता ने बिजली संयंत्र के उद्देश्य के लिए माल को छूट सीमित कर दी है।

दूसरे शब्दों में, शब्द बिजली परियोजना के साथ मिला दिया गया है बिजली संयंत्र। यह अग्रिम के तर्क की आत्मा प्रतीत होती है।

शासक प्राधिकरण। यद्यपि हम इस बात से अवगत हैं कि प्रथम प्रत्यर्थी उक्त निर्णय से बाध्य नहीं है क्योंकि वह एक पक्ष नहीं है, हम इसके तर्क में योग्यता खोजने या इस न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से उत्पन्न होने वाले प्रश्न का निर्णय करने के उद्देश्य से इसे अपनाने में अपनी ओर से इसे गलत नहीं पाते हैं। , क्या कानून में कोई बदलाव हुआ है।

(133) अपीलार्थी के इस तर्क में भी योग्यता है कि अनुच्छेद 13.1 के लिए। 1 विक्रेता द्वारा सफलतापूर्वक आह्वान किए जाने के लिए, इसे प्रदर्शित करना होगा कि कटौती की तारीख से पहले या उस तारीख तक एक व्याख्या थी जो विक्रेता के लिए फायदेमंद थी और कटौती की तारीख के बाद उक्त व्याख्या में बदलाव हुआ है।

(134) दूसरे शब्दों में, विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव की मंजूरी से जारी ओ. एम. यह संकेत नहीं देता है कि यह एक

व्याख्या में परिवर्तन का मामला। वह यह नहीं कहते हैं कि ओ. एम. में अंकित स्थिति कट ऑफ तिथि से पहले की स्थिति से एक बदलाव या परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। यह किसी भी सामग्री से अलग है जो यह दिखाने के लिए उपलब्ध है कि कटौती की तारीख से पहले पहले प्रतिवादी के पक्ष में एक व्याख्या थी।

(135) हम दोहराते हैं कि बिजली परियोजना के हिस्से के रूप में किसी भी व्यक्ति द्वारा कैप्टिव खदान के लिए आयात की जाने वाली समान प्रकृति की वस्तुओं को छूट देने का कोई उदाहरण आयोग के समक्ष नहीं रखा जाता है, चाहे वह मेगा या अल्ट्रा मेगा संयंत्र हो। यह कहना एक बात है कि एक लोकप्रिय अर्थ में और यह आग्रह किया जा सकता है और यह सच हो सकता है कि परियोजना शब्द को पी. पी. ए. में बिजली संयंत्र और कैप्टिव कोयला खदान के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि यह सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 के तहत अधिसूचना के लेखक द्वारा क्या इरादा था, इस पर निर्धारित किया जाना है और मामले को सीमा शुल्क अधिनियम की स्पष्ट शर्तों के संदर्भ में आगे निर्धारित किया जाना है। अधिसूचना। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कट ऑफ तिथि से पहले और कट ऑफ तिथि के बाद उपलब्ध व्याख्या के संदर्भ में प्रश्न का निर्णय लिया जाना चाहिए। संचार, जो ओ. एम. दिनांकित 17.06.2011 [2023] 8 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम प्रतिवादी द्वारा भरोसा किया गया मध्य प्रदेश राज्य को प्रथम प्रतिवादी द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर जारी किया गया था।

(136) श्री अमित कपूर, प्रथम की ओर से विद्वान वकील

प्रतिवादी ने अधिसूचना संख्या 21/02 दिनांक 1.3.2002 की प्रविष्टि 78 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। प्रविष्टि 78 इस प्रकार है:

अध्याय या मानक दर का विवरण। अतिरिक्त

श्री.

शर्त सं।

शीर्षक या सामान

नहीं।

दर

उप-शीर्षक

सभी वस्तुओं के लिए

नील

78 .

2714.90

सत्ता का उद्देश्य

पीढ़ी

(137) श्री रामचंद्रन, विद्वान वरिष्ठ वकील, इंगित करेंगे

कि उक्त प्रविष्टि बिजली उत्पादन के लिए निवेश से संबंधित है। प्रथम प्रत्यर्थी का मामला यह भी है कि प्रविष्टि 399 वास्तव में विशेष रूप से कोयला खनन परियोजना के लिए आवश्यक वस्तुओं से संबंधित है जिसके तहत प्रथम प्रत्यर्थी को सीमा शुल्क के साथ भेजा गया है।

(138) श्री अमित कपूर का तर्क है कि सबसे पहले, प्रवेश

78 यदि एंट्री 400 के साथ तुलना की जाए तो यह पता चलेगा कि एक बिजली परियोजना के लिए आवश्यक सभी सामान जिन्हें बड़े अर्थों में एक कैप्टिव कोयला खदान सहित समझा जाता है, वे भी एंट्री 400 की चार दीवारों के भीतर आते हैं।

(139) विद्वान वकील श्री अमित कपूर इंगित करेंगे कि बंदी

इस तरह से परिकल्पित कोयला खदान वह है जहां कोयले के पूरे उत्पादन का उपयोग बिजली संयंत्र के लिए किया जाना है जो यह भी संकेत देगा कि यह बिजली परियोजना का हिस्सा है। यह विवाद में नहीं है कि एक मेगा बिजली परियोजना, एक अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना (हम बाद वाले से संबंधित हैं) के बीच जो भी अंतर हो सकता है, वह कोई नहीं है। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अलग अधिसूचना जो अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना से संबंधित है।

(140) उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि हम

विचार है कि प्रथम प्रत्यर्थी यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं है कि अनुच्छेद 13.1 में विचार के अनुसार कानून में परिवर्तन हुआ था। 1 ओ. एम. दिनांक 17.06.2011 जारी करके।

विश्वास

(141) तीन खरीददार जो इससे पहले उत्तरदाता थे

न्यायाधिकरण ने इस न्यायालय के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराने का विकल्प नहीं चुना है।

प्रमुख हरियाणा पावर खरीद केंद्र V. ससान पावर लिमिटेड & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

खरीददार ने इस न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की है। इसके अलावा, केवल एक पी. पी. ए. है। विडंबना यह है कि आदेश एक्सएलआई नियम 21 और नियम 33 से संबंधित निर्णय इस न्यायालय के समक्ष पहले प्रतिवादी द्वारा याद दिलाते हुए रखे गए हैं। इसके लिए उपलब्ध शक्ति का यह न्यायालय। निस्संदेह, उन्होंने इस स्थिति को जल ग्रहण प्रणाली के संबंध में कानून में कोई बदलाव नहीं होने से संबंधित निष्कर्ष को चुनौती देने वाली कोई अपील दायर नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति को बचाने के प्रयास में रखा।

(142) इस मामले के तथ्यों में, हम यह भी देखते हैं कि तीन गैर-दाखिल करने वाले पक्ष अपीलार्थियों द्वारा दायर अपीलों में प्रतिवादी हैं। हम.

श्री पी. चिदम्बरम के तर्क से भी बेपरवाह नहीं हो सकते और

अन्य यह कि यदि पहले प्रत्यर्थी का मामला था कि वे कटौती की तारीख से पहले की स्थिति के तहत छूट के हकदार थे, तो उचित उपाय इस आधार पर धनवापसी की मांग करना होगा कि उन्हें अवैध रूप से सीमा शुल्क के साथ भेजा गया है।

(143) इस मामले के तथ्यों में, हम महसूस करते हैं कि न्याय के हित के लिए यह आवश्यक है कि विवादित आदेश को न केवल इसके खिलाफ अलग रखा जाए

अपीलार्थी लेकिन तीन गैर-अपीलार्थी के खिलाफ भी। मुकदमे की प्रकृति में, हम सोचेंगे कि इस आदेश का लाभ तीन उत्तरदाताओं को भी दिया जाना चाहिए। , (1) प्रतिवादी संख्या 12 (बी. एस. ई. एस. राजधानी पावर लिमिटेड); (2) प्रतिवादी संख्या 13 (बी. एस. ई. एस. यमुना पावर लिमिटेड); और (3) प्रत्यर्थी संख्या 15 (उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड)। जाहिर है, इन उत्तरदाताओं ने अपीलों का विरोध नहीं किया है।

(144) जैसा कि हमने शुरुआत में विवादित आदेश की अगली कड़ी के रूप में देखा है, आयोग ने दावे की अनुमति देने वाले आदेश पारित किए हैं

जल ग्रहण प्रणाली से संबंधित जबकि इसने ओ. एम. दिनांक 17.06.2011 से बहने वाले कानून में परिवर्तन से संबंधित प्रार्थना को खारिज कर दिया है। प्रभावित लोग पक्षकारसभ अपीलमे एहि मामलाके न्यायाधिकरणमे लऽ गेल छथि। यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि इस न्यायालय ने दिनांक 25.11.2019 पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है। चूंकि अपीलकर्ताओं ने न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी है, इसलिए आयोग के बाद के आदेश को केवल निम्नलिखित के रूप में माना जा सकता है:

परिणामी क्रम और इसलिए, इसमें खड़े होने के लिए कोई स्वतंत्र पैर नहीं हो सकते हैं। अपीलार्थियों को निर्णय का फल दिया जाना चाहिए जो अंततः उनके पक्ष में दिया जाता है, क्योंकि हम यह निर्णय दे रहे हैं।

(145) तदनुसार, अपीलों की अनुमति दी जाती है। विवादित आदेश को अलग कर दिया जाता है। आदेश से तीनों को भी लाभ होगा।

उत्तरदाता भी, अर्थात् , (1) प्रतिवादी संख्या 12 (बी. एस. ई. एस. राजधानी पावर [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सीमित); (2) प्रतिवादी संख्या 13 (बी. एस. ई. एस. यमुना पावर लिमिटेड); और (3) प्रत्यर्थी संख्या 15 (उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड)। समान रूप से, विवादित आदेश के तहत रिमांड के परिणामस्वरूप आयोग द्वारा पारित आदेश जीवित नहीं रह सकता है। दाखिल की गई अपीलें भी अपना बल खो देंगी और यह अपीलार्थियों पर है कि वे इस निर्णय के आलोक में इसे समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्य करें।

दलों को अपनी लागत खुद वहन करनी पड़ेगी।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

बिभूति भूषण बोस (सहायक: राहुल राठी, एलसीआरए)